चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 15 जून –21 जून 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अरबों के घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय मंत्री की बदहवासी

ऐसा है प्रधानमंत्री कार्यालय

दस्तख़त जून का भेज दिया मई में

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तेज गति से चल रही है, ऐसा दिखने-दिखाने के चक्कर में केंद्र की सत्ता चक्करघिन्नी हो रही है. सरकार आगे की तारीखों में आदेश जारी करती है और बदहवासी में उसे पीछे की तारीख पर ही डिस्पैच कर देती है. इस तरह का शासनिक चुटकुला आपने शायद ही पहले कभी सुना हो. केंद्र सरकार के मंत्री अपने आदेशों और सरकारी जवाबों में तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं. किस तरह? यही बता रही है, इस बार की आमुख कथा...

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश के पांच हज़ार करोड़ रुपये के ऊर्जा घोटाले की सीबीआई जांच के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने तथ्यों से ध्यान हटाने की आधिकारिक कोशिश तो की ही, उन्होंने अपने शासनिक पत्र पर सात जून, 2015 का हस्ताक्षर मई महीने में ही चस्पा कर दिया और उनके विभाग ने बिना तारीख देखे उसे मई महीने में ही डिस्पैच भी कर दिया. एक लोकसभा सदस्य को भेजे जा रहे शासनिक पत्र को लेकर भी केंद्र सरकार सतर्कता नहीं बरतती. फिर आम आदमी की स्थिति के बारे में तो हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं. सांसद महोदय को केंद्रीय मंत्री महोदय का पत्र एक महीना पहले ही प्राप्त हो गया. उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेता, नौकरशाह और न्यायाधीश सब मिलकर इस अरबों रुपये के ऊर्जा घोटाले की लीपापोती में किस तरह लिप्त हैं, इसकी वीभत्स गाथा चौथी दुनिया में कवर स्टोरी के रूप में प्रकाशित हो चुकी है. फिर भी सत्ता की खाल पर असर का हाल यह है कि पीएमओ के साथ-साथ कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री का भी प्रभार संभालने वाले डॉ. जितेंद्र सिंह अपनी ही पार्टी के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को भेजे जाने वाले आधिकारिक पत्र पर मई महीने में ही सात जून, 2015 की तारीख दर्ज कर हस्ताक्षर कर देते हैं, उनका विभाग बिना तारीख देखे वह पत्र डिस्पैच भी कर देता है और एक महीने पहले ही यानी मई 2015 में ही सांसद को पत्र प्राप्त भी हो जाता है.

इस पत्र के ज़रिये डॉ. जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा घोटाले में सीबीआई जांच की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं और आधिकारिक तौर पर न केवल तारीख, बल्कि तथ्यों को लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं. केंद्रीय मंत्री से उस ऊर्जा घोटाले के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता और नौकरशाह लिप्त रहे हैं. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच कराने की औपचारिक सिफारिश के बावजूद घोटाले की जांच

भारत सरकार सेवार्थ

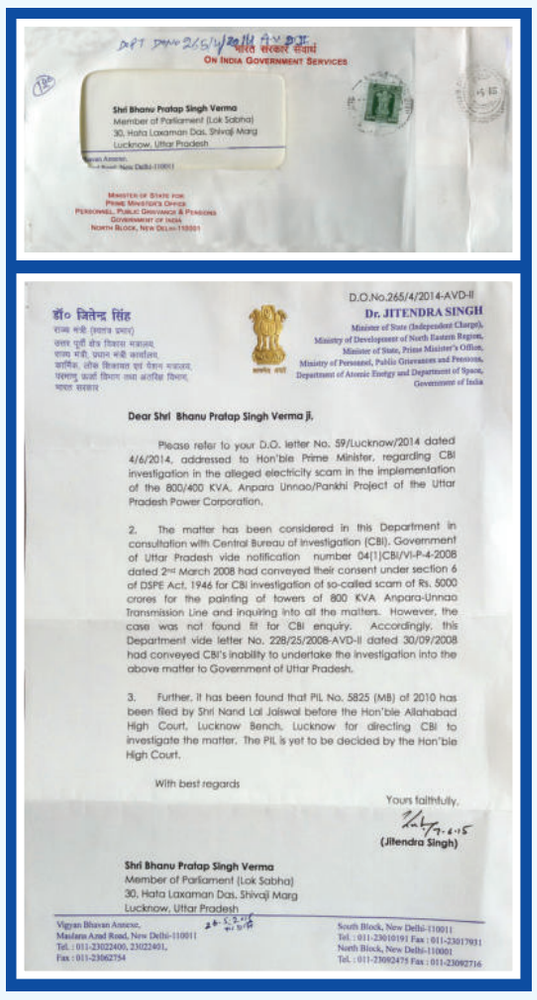

ON INDIA GOVERNMENT SERVICES

Shri Bhanu Pratap Singh Verma
Member of Parliament (Lok Sabha)
30, Hata Laxaman Das, Shivaji Marg
Lucknow, Uttar Pradesh

MINISTER OF STATE FOR
PRIME MINISTER'S OFFICE
PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
GOVERNMENT OF INDIA
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

D.O.No.265/4/2014-AVD-II

डॉ० जितेन्द्र सिंह

Dr. JITENDRA SINGH
Minister of State (Independent Charge),
Ministry of Development of North Eastern Region,
Minister of State, Prime Minister's Office,
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions,
Department of Atomic Energy and Department of Space,
Government of India

Dear Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji,

Please refer to your D.O. letter No. 59/Lucknow/2014 dated 4/6/2014, addressed to Hon'ble Prime Minister, regarding CBI investigation in the alleged electricity scam in the implementation of the 800/400 KVA, Anpara Unnao/Pankhi Project of the Uttar Pradesh Power Corporation.

2. The matter has been considered in this Department in consultation with Central Bureau of Investigation (CBI). Government of Uttar Pradesh vide notification number 04(1)CBI/VI-P-4-2008 dated 2nd March 2008 had conveyed their consent under section 6 of DSPE Act, 1946 for CBI investigation of so-called scam of Rs. 5000 crores for the painting of towers of 800 KVA Anpara-Unnao Transmission Line and inquiring into all the matters. However, the case was not found fit for CBI enquiry. Accordingly, this Department vide letter No. 228/25/2008-AVD-II dated 30/09/2008 had conveyed CBI's inability to undertake the investigation into the above matter to Government of Uttar Pradesh.

3. Further, it has been found that PIL No. 5825 (MB) of 2010 has been filed by Shri Nand Lal Jaiswal before the Hon'ble Allahabad High Court, Lucknow Bench, Lucknow for directing CBI to investigate the matter. The PIL is yet to be decided by the Hon'ble High Court.

With best regards

Yours faithfully,
7.6.15
(Jitendra Singh)

Shri Bhanu Pratap Singh Verma
Member of Parliament (Lok Sabha)
30, Hata Laxaman Das, Shivaji Marg
Lucknow, Uttar Pradesh

Vigyan Bhavan Annexe,
Maulana Azad Road, New Delhi-110011
Tel. : 011-23022400, 23022401,
Fax : 011-23062754

South Block, New Delhi-110011
Tel. : 011-23010191 Fax : 011-23017931
North Block, New Delhi-110001
Tel. : 011-23092475 Fax : 011-23092716

नहीं होने दी गई. सीबीआई से ही यह लिखवा दिया गया कि ऊर्जा घोटाले की जांच करने की उसके पास तकनीकी क्षमता नहीं है. सीबीआई ने जांच करने से बचने के लिए कई तरह के ग़ैर-क़ानूनी, ग़ैर-ज़रूरी, अतार्किक और अगंभीर बहाने गढ़े, लेकिन किसी ने भी सीबीआई से यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसने इतने ऊलजुलूल बहाने क्यों गढ़े! निजी नैतिक विवेक पर चलने का हमेशा आह्वान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री का निजी नैतिक विवेक देखिए कि उन्होंने एक सांसद को दिए गए जवाब में सीबीआई का वही पुराना बहाना हूबहू लिखकर भेज दिया. जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की बनाई हुई छवि के मुताबिक लोगों को यह उम्मीद थी (भाजपा के सांसद को भी) कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले को उजागर करने में केंद्र सरकार नए सिरे से पहल करेगी, न कि पुरानी ढपली ही बजाएगी.

पांच हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक के इस ऊर्जा घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद सीबीआई ने जांच करने से मना कर दिया, यह भ्रष्टाचार के इतिहास का एक हैरतअंगेज तथ्य है. लेकिन, न तबकी केंद्र सरकार और न अबकी केंद्र सरकार ने सीबीआई से यह पूछा कि ऐसी दुस्साहसिक हुकुमउदूली उसने क्यों की? तो यह क्यों न समझा जाए कि घोटाले की रकम इतनी बड़ी थी कि उसने राज्य एवं केंद्र सरकार में बैठे सियासतदानों, नौकरशाहों और सीबीआई के अधिकारियों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया! तभी तो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना तक को ताक पर रखकर यह कह दिया कि मामला जांच के उपयुक्त नहीं है. सीबीआई के अधिकारियों की यह अराजकता केंद्र के सत्ता अलमबरदारों को नहीं दिखी. सीबीआई ने ऊर्जा घोटाले की जांच करने से मना करते हुए पहले इसे पुराना मामला बताया, फिर कहा कि घोटाले से संबंधित जानकारियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी जा रही हैं, फिर उसके बाद कहा कि सीबीआई के पास जांच की तकनीकी क्षमता ही नहीं है और यह भी कहा कि इस घोटाले का कोई अंतरराष्ट्रीय प्रसार नहीं है. जबकि सीबीआई के सारे तर्क आधारहीन हैं.

ग़ौरतलब है कि पांच हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का यह ऊर्जा घोटाला विदेशी कंपनी कोरिया की मेसर्स हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत से

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जब बिजली नहीं, तो एमओयू क्यों!

इस गर्मी में उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की पोल खुल गई. लोगों को यह भी समझ में आ गया कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के नाम पर औद्योगिक और पूंजी घरानों से हो रहे करार महज झांसापट्टी हैं. विभागीय अभियंताओं ने भी जब इन करारों के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया, तो आम लोगों की समझ को आधिकारिक पुष्टि मिल गई. बिजली घरों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों से हुए करार (एमओयू) की अवधि लगातार बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से यह मांग की गई है कि एमओयू निरस्त कर व्यापक जनहित में नई बिजली परियोजनाओं का काम ऐसी सरकारी संस्था को दिया जाए, जिसकी साख हो, जिससे समय पर परियोजनाएं पूरी हो सकें और प्रदेश को सस्ती बिजली मिल सके. उल्लेखनीय है कि 10,340 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी कंपनियों के साथ 10 दिसंबर, 2010 से चार जनवरी, 2011 के बीच 10 एमओयू किए गए थे, जिसके अनुसार 18 माह में काम शुरू न होने पर एमओयू निरस्त करके लगभग पांच अरब रुपये की जमानत धनराशि जब्त की जानी चाहिए थी, लेकिन एमओयू की अवधि को लगातार विस्तार दिया जाता रहा. निजी कंपनियों द्वारा काम शुरू न किए जाने से साफ़ है कि उनकी दिलचस्पी बिजली घर लगाने के बजाय ज़मीनों पर कब्जा करने में अधिक है. एमओयू की अवधि बढ़ाते चले जाने का असर यह हुआ कि बिजली परियोजनाएं किसी भी हालत में वर्ष 2020 के पहले बिजली उत्पादन नहीं कर सकेंगी. इस साल काम शुरू भी हो गया, तो 2020 के पहले परियोजनाओं का पूरा होना संभव नहीं है. ऐसे में 2017 में प्रदेश में 10 हज़ार मेगावाट का अतिरिक्त बिजली संकट होगा. अगर निजी कंपनियां 2020 तक बिजली उत्पादन शुरू भी कर देती हैं, तो इन बिजली घरों से उत्पादित बिजली अत्यधिक महंगी होगी. ■

जॉर्ज फर्नांडीज जैसी विभूतियां हमारी धरोहर हैं | P-3

जलयुक्त शिवार अभियान : मराठवाड़ा के लिए वरदान | P-4

मोदी के काम आ रही है सरेशवाला की दोस्ती | P-5

अरबों के घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय मंत्री की बदहवासी

ऐसा है प्रधानमंत्री कार्यालय : दस्तख़त जून का, भेज दिया मई में

पृष्ठ 1 का शेष

ही अंजाम दिया गया था. 400 केवी सब स्टेशन एवं पारेषण (डिस्ट्रिब्यूशन) लाइन के निर्माण की इस परियोजना में जापान की तरफ़ से भी 11 सौ करोड़ रुपये मिले थे. जापान की कंपनी मेसर्स टेपेस्को इस परियोजना की सलाहकार भी थी. फिर सीबीआई ने यह कैसे कह दिया कि मामले का कोई अंतरराष्ट्रीय प्रसार नहीं है, इसलिए वह इसकी जांच नहीं कर सकती? इस घोटाले में उत्तर प्रदेश के नेताओं एवं नौकरशाहों के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के साथ-साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आला अधिकारी भी लिप्त रहे हैं. लिहाजा, यह मामला सीधा-सीधा सीबीआई जांच की परिधि में आता है. केंद्रीय मंत्री द्वारा भाजपा सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को लिखे गए इस तीव्र गति के पत्र का एक और विचित्र पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा घोटाले की जांच की अद्यतन स्थिति के बारे में मंत्री से चार जून, 2014 को ही जानकारी मांगी गई थी. एक सांसद द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब देने का समय केंद्रीय मंत्री को साल भर बाद मिला, वह भी तारीखों में गड्डमड्ड करके.

और जवाब भी क्या मिला! पहले बिंदु में सीबीआई का वही घिसा-पिटा संदर्भ दोहराया गया. दूसरे बिंदु में कहा गया कि नंदलाल जायसवाल ने मामले की सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर रखी है और उस पर अदालत का निर्णय आना बाकी है. जबकि केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को यह पता है कि अरबों रुपये के इस ऊर्जा घोटाले की सीबीआई जांच के लिए वर्ष 2007 में ही सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ़ से मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जनहित याचिका (संख्या-6605-एमबी 2007) दाखिल की थी. इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच की रिपोर्ट मांगी थी. तब सीबीआई ने कहा कि मामले की कोई जांच इसलिए नहीं की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को बाकायदा अधिसूचना जारी कर मामले की सीबीआई से जांच कराने को कहा. तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने दो मार्च, 2008 को अधिसूचना जारी कर दी और केंद्र सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया. अधिसूचना जारी होने के बावजूद सीबीआई ने खेल कर दिया. सीबीआई ने 30 सितंबर, 2008 को यह कह दिया कि वह मामले की जांच नहीं कर सकती. केंद्र सरकार भी सीबीआई के इस खेल में शामिल है.

ऊर्जा सेक्टर के व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल की जिस जनहित याचिका का केंद्रीय मंत्री ने जिक्र किया है, वह तो बाद का अध्याय है. अधिसूचना जारी होने के बावजूद सीबीआई द्वारा जांच से टालमटोल किए जाने के कारण नंदलाल जायसवाल ने अलग से पीआईएल दाखिल की थी. केंद्रीय मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी से नंदलाल जायसवाल की जनहित याचिका का जिक्र तो किया, लेकिन प्रशांत भूषण की याचिका का संदर्भ वह गोल कर गए. हाईकोर्ट ने नंदलाल जायसवाल और प्रशांत भूषण, दोनों की याचिकाओं को एक साथ जोड़ (क्लब कर) दिया है. यदि मामले की गहराई से जांच हो, तो इसमें सीबीआई के कुछ आला अफसरों की भी संदेहास्पद भूमिका सामने आएगी. सीबीआई जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बावजूद सीबीआई मुख्यालय ने सीबीआई लखनऊ जोन को इस बारे में कोई भनक नहीं लगने दी. जबकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा मामला होने के कारण मुख्यालय को सबसे पहले सीबीआई के लखनऊ जोन को इत्तिला करनी चाहिए थी. सीबीआई की सारी जांच यूनिटें लखनऊ जोन में हैं, इसके बावजूद मुख्यालय में बैठे कुछ खास अफसरों ने दिल्ली से ही जांच का रास्ता बंद कर दिया. घोटाले की जांच न हो, इसके लिए सीबीआई ने तमाम झूठ बोले और धोखाधड़ी की. सूचना का अधिकार क़ानून के तहत सीबीआई मुख्यालय से जब जानकारी मांगी गई, तो उसे लखनऊ जोन के मत्थे मढ़ने की कोशिश की गई. लेकिन, सीबीआई लखनऊ जोन ने मुख्यालय का निर्देश उसे ही वापस लौटा दिया. इस पूरे प्रकरण से लखनऊ जोन को अलग रखा गया, लिहाजा लखनऊ जोन ने भी मुख्यालय को बेबाकी से लिख दिया कि जवाब तो मुख्यालय को ही देना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भानु प्रताप सिंह वर्मा

एक तरफ़ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ़ जनता से लूट

भ्रष्टाचार से जर्जर हो चुकी वित्तीय हालत ठीक करने के लिए पॉवर कॉरपोरेशन जनता से धोखाधड़ी करके उसका पैसा लूट रहा है. पॉवर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल के नाम पर 40 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं से 100 करोड़ रुपये से अधिक वसूल लिए हैं. विद्युत नियामक आयोग ने जिस बिजली टैरिफ को ग्रामीण उपभोक्ताओं पर लागू करने पर रोक लगाई थी, उसी टैरिफ पर बिजली कंपनियों ने वसूली कर ली. अब नियामक आयोग ने रिपोर्ट मांगी है. लेकिन यह कवायद भी फिसड्डी पटाखा ही साबित होगी, क्योंकि इसके पहले भी अतिरिक्त फिक्स चार्ज और एमडी पेनाल्टी के नाम पर दो अरब रुपये से ज़्यादा की वसूली की जा चुकी है. बिना मीटर वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं से भी क़रीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई. ■

विभागीय कर्मचारी बग़ावत की राह पर

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अब विभागीय कर्मचारी ही विद्रोह का बिगुल फूंक रहे हैं. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ विद्युत कर्मचारी मोर्चा जन-जागरण अभियान तक चला चुका है. इस अभियान का समर्थन करने वाली विद्युत मज़दूर पंचायत के महामंत्री एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक गिरीश पांडेय ने कहा कि पॉवर कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है. यदि अकूत भ्रष्टाचार और घोटालों की सीबीआई से जांच कराई जाए, तो पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन के उच्च पदों पर बैठे आला अधिकारियों एवं अभियंताओं का पर्दाफाश हो जाएगा. व्हिसिल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर को अलग-अलग आयामों से चूसा जा रहा है. अरबों रुपये के घोटाले के अलावा अभियंताओं एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से ठेके के संविदा कर्मचारियों के भी लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये हड़प लिए गए हैं. भ्रष्टाचार का विरोध करने पर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है, पुलिस से पिटवाया जाता है, जेल भेजा जाता है, निलंबन किया जाता है और नौकरी से निकाल दिया जाता है. नंदलाल जायसवाल खुद इसके भुक्तभोगी रहे हैं. भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण उन्हें भीषण प्रताड़ना से गुज़रना पड़ा और आख़िरकार उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया. बाद में अदालत के हस्तक्षेप पर उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई. नंदलाल जायसवाल की पुनर्बहाली का मसला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. ऊर्जा सेक्टर के विभिन्न बड़े घोटालों में पॉवर कॉरपोरेशन का पांच हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला शीर्ष पर है, जिसकी सीबीआई से जांच के लिए मायावती सरकार ने अधिसूचना जारी की, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई ने जांच नहीं होने दी. इसी तरह उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में भी 1600 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. इस मामले में पिछले क़रीब एक दशक से जांच ही चल रही है. नतीजा शून्य है. विद्युत नियामक आयोग की शह पर जेपी समूह समेत निजी बिजली घरानों को लाभ पहुंचाए जाने के सनसनीखेज मामले में भी नतीजा ढाक के तीन पात ही निकला. इस भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश को क़रीब 30 हज़ार करोड़ रुपये की क्षति हुई. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश अवस्थी हटा तो दिए गए, पर घोटाले की जांच फाइलों में ही बंद रह गई. यही हाल जल विद्युत निगम में हुए 750 करोड़ रुपये के घोटाले का भी हुआ. तत्कालीन एमडी आलोक टंडन समेत कई अभियंताओं के इस घोटाले में सीधे शामिल होने का आरोप है. आधिकारिक तौर पर कहा भी जाता है कि मामले की जांच जारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई यह नहीं कहता कि जांच का नतीजा कब आएगा और कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं. एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल घोटाला भी दरवाजे-दरवाजे भटक रहा है. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और अधिकृत बिलिंग कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला किया गया. इसमें बिलिंग से जुड़ी कुछ आईटी कंपनियां भी शामिल हैं. लखनऊ के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को जांच का ज़िम्मा दिया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 15
दिल्ली, 15 जून –21 जून 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कैबिनेट सचिव की खोज पूरी

पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1977 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्हा को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया, तो पिछले साल के अंत से इस पद के लिए जारी खोज और कुछ महीनों से मीडिया सहित कुछ लोगों के बीच चल रही अटकलबाजियों पर विराम लग गया कि अजित सेठ की जगह कौन लेगा. ग़ौरतलब है कि अजित सेठ का कार्यकाल सबसे लंबा था. 77 अधिकारियों में से पांच के नाम अंतिम रूप से इस पद के लिए उपयुक्त समझे गए थे, जिनमें से तीन नाम प्रधानमंत्री के पास भेजे गए. जो दो अधिकारी सिन्हा से पीछे रह गए, वे आलोक रावत और राजीव महर्षि हैं. कहना दिलचस्प होगा कि सिन्हा के चयन के साथ ही मोदी को दिल्ली के सत्ता के गलियारों में दिग्गज नेताओं का ज़्यादा समर्थन हासिल हो गया है. सिन्हा की बहन रश्मि वर्मा वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और कथित तौर पर देश में जीएसटी लागू करने के लिए मोदी सरकार की मुहिम चला रही हैं. रश्मि के पति नवीन वर्मा कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर पहले से ही कार्यरत हैं. दोनों को उम्मीद है कि जल्द ही वे प्रोन्नति पाकर सचिव बन जाएंगे. ■

प्रसार भारती की स्वायत्तता खत्म!

प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार इस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप से कथित तौर पर परेशान हैं. इस परेशानी का प्रमुख कारण है, दूरदर्शन द्वारा नया लॉन्च किया गया चैनल किसान, जिसे मंत्रालय के बदले एक निजी संचालक द्वारा चलाया जाएगा. जवाहर सरकार ने प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश को लिखे गए एक पत्र में इस पर नाराज़गी जाहिर की और कहा है कि इस भ्रम को दूर किया जाए. सरकार ने मंत्रालय के ख़िलाफ़ एक और शिकायत की है. मंत्रालय ने सूचना सेवा अधिकारी वीणा जैन को मंत्रालय की ओएसडी के साथ-साथ दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की है. यह घोषणा प्रसार भारती के अध्यक्ष और सीईओ को जानकारी दिए बगैर की गई है. यह स्वाभाविक है कि मंत्रालय प्रसार भारती की भागीदारी के बिना सीधे दूरदर्शन चलाने की योजना बना रहा है. ■

नियुक्तियों और तबादलों में तेजी

मोदी सरकार की पहली वर्षगांठ के समय ये अफवाहें थीं कि सरकार नौकरशाही को प्रेरित करने के लिए अपने प्रयासों में ढीलापन ला रही है. कई महत्वपूर्ण पद खाली थे, जिससे सरकार की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही थी, लेकिन सरकार ने अचानक अपने इस रुख में बदलाव किया. अब दिल्ली में नियुक्तियों और तबादलों की जैसे बारिश हो रही है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सचिव स्तर के 17 तबादलों को मंजूरी दे दी है. हालांकि, रूटीन में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर की अधिकांश नियुक्तियां ही रहीं, सचिव स्तर की नियुक्तियां न के बराबर देखने को मिलीं. यह कई लोगों को चौंकाने वाला था. वरिष्ठ नौकरशाहों की प्रमुख मंत्रालयों में नियुक्तियों और तबादलों में चलती है. 17 अधिकारियों में, जो प्रभावित हैं, वे हैं नई वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया, ऊर्जा सचिव प्रदीप कुमार पुजारी (जो पीके सिन्हा के स्थान पर नियुक्त हुए, जिनका नाम कैबिनेट सचिव के लिए प्रस्तावित किया गया) और नए नागरिक उड्डयन सचिव राजीव नयन चौबे. दिलचस्प है कि तेवतिया और पुजारी 1981 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं. मोदी के रेस कोर्स रोड आने के बाद दिल्ली के लिए इन अधिकारियों का पलायन देखा गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय गुजरात के बाबुओं को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके साथ मिलकर काम किया है. साफ़ है कि प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दिनों को नहीं भूले होंगे. कहना ग़लत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में गुजरात से अधिक बाबुओं को केंद्र में लाया जाएगा. ■

dilipcherian@gmail.com

जॉर्ज फर्नांडीज ने 1974 में आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में हड़ताल की घोषणा की. भारत के इतिहास में उससे बड़ी हड़ताल कभी नहीं हुई. लगभग 30 हज़ार मज़दूर नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं और 17 लाख कर्मचारियों ने उस हड़ताल में हिस्सा लिया था. आपातकाल के दौरान जॉर्ज साहब राम मनोहर लोहिया का अनुसरण करते हुए भूमिगत हो गए और लोकतंत्र के लिए अनवरत लड़ते रहे. उन्होंने वही तौर– तरीके अपनाए, जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल लोहिया जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था. बड़ौदा डाइनामाइट प्रकरण में उन्हें पत्रकार किरीट भट्ट और के. विक्रम राव के साथ 10 जून को गिरफ्तार किया गया.

जॉर्ज फर्नांडीज जैसी विभूतियां हमारी धरोहर हैं

लोहिया को देखते रह गए जॉर्ज

दीपक मिश्र

भारतीय राजनीति एवं समाजवादी विचारधारा के अप्रतिम व्याख्याता एवं जाज्वल्यमान नक्षत्र जॉर्ज फर्नांडीज के साथ किया गया संवाद मेरे जीवन की वह उपलब्धि है, जिसे मूकास्वादानवत् मैं महसूस तो कर सकता हूं, पर अभिव्यक्त नहीं कर सकता. लोहिया के मात्रा भेद व सामीप्य के सिद्धांत को मैं समझ नहीं पा रहा था. विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसरों और विद्वानों से पूछा, पर कोई भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पाया. छोटे लोहिया जनेश्वर जी ने कहा कि इसे सिर्फ़ दो लोग ही ठीक से बता सकते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष रहे रवि राय और दूसरे जॉर्ज फर्नांडीज. मेरे दिमाग में जॉर्ज साहब की जो तस्वीर थी, वह एक अनवरत एवं अपराजेय योद्धा की थी. मैं उनके वैचारिक योगदान और क्षमता से वाकिफ न था. जब जनेश्वर जी ने कहा कि जॉर्ज मात्रा भेद व सामीप्य के सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा. दूसरे दिन मैं जॉर्ज साहब के आवास पर पहुंचा. पूरे आवास में कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा, हिचकते हुए अंदर पहुंचा, तो एक व्यक्ति ने टोका कि जॉर्ज साहब बाईं तरफ़ बैठे हैं, उधर जाइए. जॉर्ज फर्नांडीज के कमरे में पहुंचने के पश्चात मुझे लगा कि मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आ गया हूं. एक से एक दुर्लभ पुस्तकें करीने से सजी हुईं और कुछ बिखरी पड़ी थीं. एक सोफे पर बैठे जॉर्ज साहब कोई पुस्तक पढ़ रहे थे. मुझे देखते ही उन्होंने आने का कारण पूछा. मैं भावातिरेकवश आने का हेतुक नहीं बता सका. सिर्फ़ इतना ही कह पाया कि आपको लोहिया जी एवं समाजवाद पर लिखी अपनी दो पुस्तकें भेंट करनी हैं.

मैंने समाजवाद की अपरिहार्य आधारिकाएं और भारत–रत्न लोहिया भेंट की. वह पुस्तक के मुख पृष्ठ पर छपी लोहिया की तस्वीर को एकटक देखते रहे, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे. उन्होंने लरजते लहजे में कहा कि हम लोग लोहिया के अधूरे कामों को पूरा नहीं कर सके. उन्होंने पांच–छह मिनट के निस्तब्ध मौन के बाद मेरी पीठ को थपथपाते हुए शाबाशी दी और कहा कि इतनी कम उम्र में लोहिया पर लिखना बड़ी बात है. देखकर अच्छा लगा कि नई पीढ़ी समाजवाद पर काम कर रही है. उन्होंने मुझे दो बंडल पुस्तकें दीं और लगभग छह घंटे तक विभिन्न विषयों पर मेरी तमाम भ्रांतियों को दूर किया. यदि डॉक्टर ने वीटो न लगाया होता, शायद दो– चार घंटे और ज्ञान देते. वह इस समय के सचमुच जीवित किंवदंती हैं, जिसे ज्ञान पुंज और विद्वता का असीम खजाना कहा जाए, तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं होगा. उन्होंने न केवल मात्रा–भेद सिद्धांत समझाया, अपितु यह भी बताया कि इस दर्शन के मूल में अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षिकता की अवधारणा है. उन्होंने अल्बर्ट एवं लोहिया संवाद की भी दुर्लभ जानकारी दी. जॉर्ज साहब अनन्य योद्धा एवं लोक संघर्षों की प्रतिमूर्ति से बड़े विचारक और चिंतक लगे. उनका वैचारिक पक्ष अभी तक हम सभी के सामने नहीं आया है. जन संघर्षों के पुरोधा एवं राजनीतिज्ञ जॉर्ज ने विचारक, संपादक, चिंतक, लेखक जॉर्ज को पृष्ठभूमि में कर दिया है. बहुत

जॉर्ज फर्नांडीज ने प्रारंभिक जीवन में कोंकड़ी युवक नामक कोंकण समाचार-पत्र के साथ-साथ कन्नड़ साप्ताहिक रैथवाणी में काम किया था. उनका पत्रकारिता में अनुपम योगदान अंग्रेजी मासिक द अदर साइड और हिंदी मासिक प्रतिपक्ष है. उन्हें लोहिया जी द्वारा प्रकाशित मैनकाइंड व जन की अगली कड़ी कहा जाए, तो ग़लत न होगा. जॉर्ज विश्व नागरिक एवं वैश्विक समाजवादी हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गांधी, लोहिया एवं लिमये की भांति काफी कार्य किया और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई. तिब्बत की आज़ादी, म्यांमार का जनांदोलन और श्रीलंका में तमिल आंदोलन को उनका खुला समर्थन रहा है.

कम लोग जानते हैं कि जॉर्ज साहब अंग्रेजी, कोंकड़ी, उर्दू, लैटिन, हिंदी, मराठी, बर्मन, तिब्बती, टुलू, कन्नड़ समेत 12 भाषाओं के जानकार हैं और राजनीति एवं सामयिक–सैद्धांतिक सवालों पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें वाट एल्स द सोशलिस्ट, द काश्मीर प्रॉब्लम, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974 और एसे इन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं.

जॉर्ज फर्नांडीज ने प्रारंभिक जीवन में कोंकड़ी युवक नामक कोंकण समाचार–पत्र के साथ–साथ कन्नड़ साप्ताहिक रैथवाणी में काम किया था. उनका पत्रकारिता में अनुपम योगदान अंग्रेजी मासिक द अदर साइड और हिंदी मासिक प्रतिपक्ष है. उन्हें लोहिया जी द्वारा प्रकाशित मैनकाइंड व जन की अगली कड़ी कहा जाए, तो ग़लत न होगा. जॉर्ज विश्व नागरिक एवं वैश्विक समाजवादी हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गांधी, लोहिया एवं लिमये की भांति काफी कार्य किया और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई. तिब्बत की आज़ादी, म्यांमार का जनांदोलन और श्रीलंका में तमिल आंदोलन को उनका खुला समर्थन रहा है. म्यांमार के छात्र उनके आवास पर रहकर अध्ययन भी करते रहे हैं और आंदोलन भी. जॉर्ज हमेशा कहते रहे कि मैं दुनिया भर में चल रहे सभी प्रकार के लोकतांत्रिक संघर्षों का पक्षधर एवं मित्र हूं. उनके अस्वस्थ होने से समाजवाद की वैचारिक ताकत क्षीण हुई है, जिसे पुन: ताकतवर बनाने की ज़िम्मेदारी हम समाजवादियों की है. जॉर्ज में वीरता एवं संतत्व, दोनों गुणों का अद्भुत समावेश है. वह समाजवाद के ज्ञाता ही नहीं, अपितु समाजवादी जीवन शैली को अंगीकृत कर लोक जीवन जीने वाले अप्रतिम उदाहरण हैं. ■

(लेखक समाजवादी बौद्धिक/चिंतन सभा के अध्यक्ष हैं.)

समाजवाद और सादगी की प्रतिमूर्ति

शिवपाल सिंह यादव

हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि समाजवाद के प्रतिबद्ध सेनानी एवं संघर्ष की प्रतिमूर्ति जॉर्ज फर्नांडीज 85वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं. राजनीति, पत्रकारिता, समाजवादी विचारधारा और मज़दूर आंदोलन के दृष्टिकोण से जॉर्ज साहब का योगदान बहुआयामी, बहुस्तरीय और बहुमूल्य है. वह उन बड़े नेताओं में अग्रणी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति की प्रखरता एवं जनसंघर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्तुत्य नायक बने. जहां तक मुझे याद है, साठ–सत्तर के दशक में उनका नाम रचनात्मक संघर्ष के पर्याय के रूप में जाना जाता था. वह मज़दूरों की सबसे बुलंद और किसी के भी आगे कभी मंद न पड़ने वाली आवाज़ बन चुके थे. हम लोगों के लिए जॉर्ज साहब प्रारंभ से प्रेरणा के केंद्र रहे हैं. मुझे उन्हें कई बार सुनने, तलैया एवं इटावा में उनकी सभा कराने का सौभाग्य मिला. वह अपने आप में सादगी और ज्ञान की आदमकद प्रतिमा हैं. मुझे आश्चर्य होता है कि लोक जीवन में इतना संघर्ष करने वाला यायावर व्यक्ति इतना विद्वान कैसे हो सकता है. नई पीढ़ी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विशेषकर समाजवादियों को जॉर्ज साहब से लोक जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए. जॉर्ज फर्नांडीज का जन्म तीन जून, 1930 को मंगलूर में जॉन जोसफ फर्नांडीज एवं एलिस मार्था के पुत्र के रूप में हुआ. उनकी मां मार्था जॉर्ज पंचम से प्रभावित थीं, अत: उन्होंने अपने पुत्र का नाम जॉर्ज रख दिया. पिता जोसेफ उन्हें पादरी बनवाना चाहते थे. उन्होंने जॉर्ज को बंगलुरू में धार्मिक शिक्षा भी दिलवाई, किंतु जॉर्ज सेमिनरी छोड़कर 1949 में मुंबई आ गए. यहीं उनकी मुलाकात कालजयी एवं क्रांतिधर्मी चिंतक राम मनोहर लोहिया से हुई. जॉर्ज साहब ने समाजवादी मज़दूर संघ एवं निर्णायक श्रमिक आंदोलन का सिंहनाद किया और देखते ही देखते वह मुंबई के मज़दूर संघों और राजनीति की धुरी बन गए. वह 1961 से 1968 तक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निर्वाचित सदस्य रहे. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1967 में उन्हें कद्दावर नेता और मुंबई का बेताज बादशाह कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री सदाशिव कानोजी पाटिल के विरुद्ध चुनाव में लोकसभा का टिकट दिया. जॉर्ज साहब पाटिल को हराकर सांसद बने. फिर तो पूरे भारत में जॉर्ज फर्नांडीज का नाम गूंजने लगा.

जॉर्ज फर्नांडीज ने 1974 में आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में हड़ताल की घोषणा की. भारत के इतिहास में उससे बड़ी हड़ताल कभी नहीं हुई. लगभग 30 हज़ार मज़दूर नेताओं

उल्लेखनीय है कि बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिन्हें रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था. इसमें चीन के साम्राज्यवादी रवैये का विरोध भी शामिल है. जॉर्ज साहब के बाद यदि चीन के मुक़ाबले कोई पार्टी और नेता आज की तिथि में दिख रहा है, तो वह समाजवादी पार्टी और स्वयं मुलायम सिंह यादव ही हैं. यह दोनों नेताओं के वैचारिक साम्य को दर्शाता है. जब नेताजी ने 29 अगस्त, 2003 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जॉर्ज साहब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए. यह उनका मुलायम सिंह जी के प्रति स्नेह भाव का द्योतक है.

की गिरफ्तारियां हुईं और 17 लाख कर्मचारियों ने उस हड़ताल में हिस्सा लिया था. आपातकाल के दौरान जॉर्ज साहब राम मनोहर लोहिया का अनुसरण करते हुए भूमिगत हो गए और लोकतंत्र के लिए अनवरत लड़ते रहे. उन्होंने वही तौर– तरीके अपनाए, जिन तौर–तरीकों का इस्तेमाल लोहिया जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था. बड़ौदा डाइनामाइट प्रकरण में उन्हें पत्रकार किरीट भट्ट और के. विक्रम राव के साथ 10 जून को गिरफ्तार किया गया. हाथों में हथकड़ी पहने और ललकारते हुए उनकी तस्वीर उस दौर की सबसे चर्चित एवं प्रेरक चित्र थी. आपातकाल के पश्चात वह जेल से रिहा हुए और 10 जून, 1976 मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े. लगभग तीन लाख मतों से जीतकर लोकसभा के सदस्य बने और फिर मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री बने. जॉर्ज साहब ने फेरा के तहत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों कोको कोला और आईबीएम पर कार्यवाही की. वह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में रेल मंत्री भी रहे. उन्होंने 1994 में समता पार्टी बनाई. इसके अलावा वह 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2009 तक देश के रक्षा मंत्री रहे. पोखरण परमाणु परीक्षण और करगिल में जीत जैसी उपलब्धियां उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हासिल हुईं. उल्लेखनीय है कि बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिन्हें रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था. इसमें चीन के साम्राज्यवादी रवैये का विरोध भी शामिल है. जॉर्ज साहब के बाद यदि चीन के मुक़ाबले कोई पार्टी और नेता आज की तिथि में दिख रहा है, तो वह समाजवादी पार्टी और स्वयं मुलायम सिंह यादव ही हैं. यह दोनों नेताओं के वैचारिक साम्य को दर्शाता है.

जब नेताजी ने 29 अगस्त, 2003 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जॉर्ज साहब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए. यह उनका मुलायम सिंह जी के प्रति स्नेह भाव का द्योतक है. वह समाजवादियों को एकत्र करके देश में समतामूलक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सदैव प्रयासरत रहे. उनकी सादगी बेमिसाल रही है. वह जब रक्षा मंत्री थे, तब भी अपने कपड़े स्वयं धोते थे. उनके किरदार में कभी बनावट नहीं आई. सत्ता हो या विपक्ष, वह सदैव एक जैसे रहे. आज वह भले ही पूर्णतया स्वस्थ न हों, लेकिन उनके विचार एवं उनका दर्शन स्वस्थ और प्रासंगिक हैं. जॉर्ज साहब जैसी विभूतियां हमारी धरोहर हैं, हम उनके लंबे एवं नि:रोग जीवन की कामना करते हैं. ■

(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं)

निश्चित रूप से जलयुक्त शिवार अभियान महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित ज़िलों में जल संरक्षण का एक बेहतरीन प्रयोग है. कम लागत में वर्षा जल को संचित करने का यह अनूठा प्रयोग आने वाले दिनों में मराठवाड़ा और विदर्भ की खुशहाली का कारण बनेगा. महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष 26 जनवरी को सूखा प्रभावित मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाक़ों में जलयुक्त शिवार अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत हर साल 5,000 गांवों में सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था जल संरक्षण के प्राकृतिक उपायों के ज़रिये की जाएगी.

जलयुक्त शिवार अभियान

मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए वरदान

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाक़ों में पानी की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौक़े पर जलयुक्त शिवार अभियान की शुरुआत की. सरकार का दावा है कि इस योजना की मदद से महाराष्ट्र वर्ष 2019 तक सूखा मुक्त हो जाएगा. इस अभियान के तहत प्रतिवर्ष पांच हज़ार गांवों को हरित बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि इस अभियान में जन सहभागिता अधिक है. जल संरक्षण के इस अभियान में सिद्धि विनायक जैसे धार्मिक न्यास ने भी करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद की है. मराठवाड़ा और विदर्भ के गांवों को सूखा मुक्त बनाने के लिए कई कॉरपोरेट घरानों ने भी सार्थक पहल की है. मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र के सभी सूखा प्रभावित ज़िलों में इन दिनों पुराने तालाबों, बावड़ियों, कुओं एवं नालों को पुनर्जीवित किया जा रहा है. वहीं कई गांवों में नए नालों, तालाबों एवं कुओं का निर्माण भी हो रहा है. जलयुक्त शिवार अभियान वास्तव में मराठवाड़ा के लिए एक भगीरथ प्रयास है. इस मसले पर प्रस्तुत है चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

मराठवाड़ा की दस दिवसीय सघन यात्रा के दौरान यह संवाददाता ऐसे दर्जनों गांवों में गया, जहां हाल में किसानों ने आत्महत्याएं की थीं. कई वर्षों से बारिश न होने, फ़सल नाक़ाम होने और क़र्ज़ की वजह से काश्तकार ख़ुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं. उस्मानाबाद डाक बंगले पर चौथी दुनिया के इस संवाददाता की मुलाक़ात ज़िला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दीपक चव्हाण से हुई. उन्होंने बातचीत में जलयुक्त शिवार अभियान के बारे में बताया. उस्मानाबाद ज़िले में इस अभियान से जुड़े कार्यों के विषय में अधिक जानकारी के लिए हम दोनों ज़िलाधिकारी आवास पर पहुंचते हैं. ज़िलाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे ने जलयुक्त शिवार अभियान के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. लगभग दो घंटे की बातचीत में उन्होंने बताया कि जल संरक्षण की दिशा में इस अभियान की सफलता न सिर्फ़ महाराष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, बल्कि इससे राजस्थान जैसे उन राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी, जहां जल संकट की स्थिति गंभीर है. जलयुक्त शिवार अभियान के तहत क्या-क्या काम हो रहे हैं, यह देखने के लिए मैं उस्मानाबाद के उन गांवों में गया, जहां नाला खोलीकरण, बांध एवं तालाब निर्माण आदि काम चल रहे थे. मेरे साथ मराठी दैनिक लोकमत, सकाल, महाराष्ट्र टाइम्स, पुण्य नगरी के अलावा दैनिक भास्कर और दूरदर्शन के कई पत्रकार साथी भी थे. हम लोग उस्मानाबाद ज़िले से क़रीब 25 किलोमीटर दूर वाशी तालुका स्थित एक गांव पहुंचे. यहां महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी और पोकलेन की मदद से नाला खुदाई का काम चल रहा था.

पांडुरंग पोले, ज़िलाधिकारी, लातूर

जलयुक्त शिवार अभियान एक भगीरथ प्रयास की तरह है. प्राकृतिक रूप से वर्षा जल के संरक्षण का यह कार्य अद्वितीय है. लातूर ज़िला प्रशासन समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

-पांडुरंग पोले, ज़िलाधिकारी, लातूर

पानी की समस्या हल करने के लिए राज्य सरकार ने जलयुक्त शिवार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. इस योजना में लोगों की सहभागिता भी ज़रूरी है. ज़िला प्रशासन इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर ज़ोर दे रहा है.

-नवल किशोर राम, ज़िलाधिकारी, बीड

मराठवाड़ा में सूखे की समस्या काफी गंभीर है. जलयुक्त शिवार अभियान से सिंचाई और पेयजल की कमी दूर होगी. इस अभियान की मदद से ज़िला प्रशासन उस्मानाबाद को सूखा मुक्त बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है.

-डॉ. प्रशांत नारनवरे, ज़िलाधिकारी, उस्मानाबाद

उस्मानाबाद समेत संपूर्ण मराठवाड़ा प्राचीन दक्कन के पठार पर मौजूद है. यहां की मिट्टी की ऊपरी परत, जिसे काली कपासी कहते हैं, वह बेहद उपजाऊ है. चार-पांच फीट के बाद बेसाल्ट, चूना-पत्थर और स्लेट की परतें शुरू हो जाती हैं. हालांकि, ये सभी काफ़ी मुलायम चट्टानें हैं और इनमें पानी सोखने की ज़बरदस्त क्षमता है. उस्मानाबाद के ज़िला कृषि अधिकारी शंकर तोटावार ने चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत में बताया कि जलयुक्त शिवार अभियान में महाराष्ट्र सरकार के अलावा स्थानीय जनता भी आर्थिक सहयोग करती है. दरअसल, इस अभियान में जन सहयोग का तरीक़ा बेहद दिलचस्प है. मिसाल के तौर पर नाला खोलीकरण या नए नाले बनाने का कार्य चल रहा है. ज़ाहिर है, उसकी लंबाई पांच, छह, आठ या नौ किलोमीटर होगी. जेसीबी और पोकलेन की मदद से वहां मिट्टी की कटाई होती है. खेती के लिहाज़ से यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है. जिन गांवों में यह काम हो रहा है, वहां मिट्टी लेने को इच्छुक किसान ट्रैक्टर की मदद से उस मिट्टी को अपने खेतों में डालते हैं. इसके बदले वे जलयुक्त शिवार अभियान को पैसा देते हैं. इस तरह मिट्टी के बदले पैसे देने से लाखों रुपये की आमदनी जल को संचित करने के लिए मराठवाड़ा समेत प्रदेश के अन्य सूखा प्रभावित ज़िलों में पुराने तालाबों, बावड़ियों एवं नालों में जमा सिल्ट हटाने का काम किया जा रहा है. इसके अलावा काफ़ी संख्या में नए नालों, तालाबों एवं बावड़ियों के निर्माण का कार्य भी तेज़ गति से चल रहा है. मराठवाड़ा ख़ासकर उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी और जालना में जलयुक्त शिवार अभियान की प्रगति सबसे अधिक है, क्योंकि यहां भू-जल स्तर काफ़ी नीचे है. जलयुक्त शिवार अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने सूबे के बड़े उद्योगपतियों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की. महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे के अनुसार, राज्य सरकार हर साल पांच हज़ार गांवों को जलयुक्त शिवार अभियान के तहत हरा-भरा करेगी. वर्ष 2019 तक इस अभियान की मदद से सूबे के 25,000 गांवों को हरित बनाया जाएगा. उसके बाद इन गांवों में सिंचाई और पीने के लिए पानी की किल्लत नहीं रहेगी.

उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष में मराठवाड़ा के 1,682, नागपुर विभाग के 1,077, अमरावती विभाग के 1,200, पुणे विभाग के 900, नासिक विभाग के 951 और कोंकण विभाग के 200 गांवों को इस अभियान के लिए चुना गया है. वर्ष 2016 के गणतंत्र दिवस के मौक़े पर 2,500 गांवों में जल संरक्षण के कार्य शुरू होंगे. मौजूदा चालू वर्ष में राज्य भर में दस हज़ार छोटे बांध बनाए जाएंगे. इस अभियान के लिए छह से सात हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. फिलहाल जलयुक्त शिवार अभियान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हज़ार करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया है. इसके अलावा केंद्र सरकार के एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को क़रीब छह हज़ार करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी. जलयुक्त शिवार अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यों और उनकी गुणवत्ता से संबंधित जानकारियां उपग्रह के माध्यम से ली जाएंगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने धार्मिक न्यासों और कॉरपोरेट घरानों से भी जलयुक्त शिवार अभियान में सहयोग देने की अपील की है. सरकार की इस अपील के बाद श्री सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र के हर ज़िले को एक करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा की. इस प्रकार यह ट्रस्ट राज्य के 34 ज़िलों को 34 करोड़ रुपये देगा. यह राशि हर ज़िले में जलयुक्त शिवार अभियान में ख़र्च की जाएगी. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2014-15 के बीच मराठवाड़ा के सभी आठ ज़िलों में भू-जल स्तर में औसतन दो मीटर की गिरावट दर्ज की गई है.■

अभियान में शामिल गांव (ज़िला उस्मानाबाद)

तालुका	गांवों की संख्या
उस्मानाबाद	129
तुलजापुर	123
उमरगा	96
लोहारा	47
कलंब	97
भूम	96
वाशी	54
परंडा	96
कुल गांवों की संख्या:	737

उस्मानाबाद ज़िले पर एक नज़र

- भौगोलिक क्षेत्र: 7.57 लाख हेक्टेअर
- खेती योग्य ज़मीन: 5.82 लाख हेक्टेअर
- ख़रीफ़ फ़सल का कुल रकबा: 3.93 लाख हेक्टेअर
- रबी फ़सल का कुल रकबा: 4.54 लाख हेक्टेअर
- बागायती खेती (बाग-बागीचे) का कुल रकबा: 0.98 लाख हेक्टेअर
- कुल सिंचित रकबा: 0.98 लाख हेक्टेअर
- गांवों की कुल संख्या: 737
- ग्राम पंचायतों की कुल संख्या: 622
- तालुकों/तहसील/प्रखंड की कुल संख्या: 08
- राजस्व अनुमंडल: 04
- राजस्व क्षेत्र: 42

अभियान में चयनित गांवों और जन-भागीदारी से हुए कार्यों पर एक नज़र

ज़िले का नाम	चयनित गांव	गांवों की संख्या	नाला खुदाई	कुल ख़र्च
औरंगाबाद	228	36	59	2.78 करोड़ रुपये
जालना	209	12	39	0.79 करोड़ रुपये
बीड	271	11	22	2.62 करोड़ रुपये
परभणी	170	99	334	5.38 करोड़ रुपये
हिंगोली	124	10	25	0.88 करोड़ रुपये
नांदेड़	261	66	76	9.84 करोड़ रुपये
लातूर	202	99	194	28.08 करोड़ रुपये
उस्मानाबाद	217	119	85	0.82 करोड़ रुपये

कुल ज़िले: 08, चयनित गांवों की संख्या: 1,682, गांवों की संख्या, जहां जन-भागीदारी से कार्य हो रहे हैं: 452
नाला खुदाई, नाला सफ़ाई आदि कार्य: 834, कुल ख़र्च: 51.15 करोड़ रुपये

वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो पार्टी के साथ–साथ मोदी ने भी मुसलमानों को अपने क़रीब लाने की कोशिश की. उसी कोशिश के तहत उन्होंने उर्दू अख़बारों एवं चैनलों को जो इंटरव्यू दिए, उनमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उनकी नज़र में हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे ही हैं, जैसे यहां की दूसरी कौमें. उन्होंने यहां तक कहा कि जिस दिन मुसलमान उन्हें पहचान लेंगे, वे उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेंगे. ज़फर सरेश वाला ने इस काम में मोदी का भरपूर साथ दिया.

मोदी के काम आ रही है सरेशवाला की दोस्ती

डॉ. क़मर तबरेज़

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब मुसलमानों ने वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मान लिया था, तब गुजरात के ही एक मुस्लिम व्यापारी डॉ. ज़फर यूनुस सरेशवाला ने न सिर्फ़ मोदी का साथ दिया, बल्कि मुसलमानों को उनके क़रीब लाने की भी कोशिश की. ज़फर सरेशवाला को व्यक्तिगत तौर पर इसका फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, लेकिन वह अपनी ही कौम में बुरी तरह बदनाम हो गए. दूसरी तरफ़ एक सच्चाई यह भी है कि नरेंद्र मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, वह मुसलमानों से जुड़ा कोई भी फ़ैसला ज़फर सरेशवाला से विचार–विमर्श किए बगैर नहीं लेते.

वर्ष 1994 या फिर 95 की बात है, लंदन के इंडियन मुस्लिम फेडरेशन ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौक़े पर एक विरोध सभा आयोजित करने की घोषणा की थी. लंदन के एक मशहूर धार्मिक नेता मौलाना ईसा मंसूरी, जो खुद भी गुजराती हैं, ने फेडरेशन के आयोजकों से फोन पर कहा कि वे इस विरोध सभा में ज़फर सरेशवाला को भी आमंत्रित करें, क्योंकि वह एक बड़े व्यापारी हैं और मुसलमानों के मुद्दों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. इससे पहले ब्रिटेन के मुसलमानों ने ज़फर सरेशवाला का नाम नहीं सुना था, लिहाज़ा सरेशवाला को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया. सरेशवाला उस कार्यक्रम में न सिर्फ़ शरीक हुए, बल्कि उन्होंने अपने विचार भी लोगों के सामने रखे. इसके बाद लंदन के मुस्लिम संगठनों के साथ सरेशवाला की नज़दीकियां दिनोंदिन बढ़ती गईं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए न केवल गुजरात स्थित अपनी कंपनी पारसोली कॉरपोरेशन का बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार किया, बल्कि इस्लामी बैंकिंग से संबंधित कई सेमिनार आयोजित कराकर वह इस सिलसिले में प्रमुख मुस्लिम आलिमों (उलेमा) के संदेशों और फतवों को भी लोगों के सामने लेकर आए.

ज़फर सरेशवाला पहली बार अख़बार की सुर्खियों में कब आए, यह वाकया भी बेहद दिलचस्प है. वर्ष 2001 में कुछ असामाजिक तत्वों के ज़रिये कुरान जलाने की एक दु:खद घटना दिल्ली में घटी, जिस पर दिल्ली में मुसलमानों की ओर से जबदजस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था. उस वक्त यहीं के एक अख़बार ने यह बात उजागर की थी कि इस धरना–प्रदर्शन के पीछे ब्रिटेन में रहने वाले एक गुजराती व्यापारी ज़फर सरेशवाला का हाथ है. इसके बाद वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे भड़क गए. एक अख़बार को दिए गए इंटरव्यू में सरेशवाला ने कहा था कि गुजरात दंगों के दौरान उनके घर और कार्यालय को भी आग लगा दी गई थी. उनकी कंपनी के सारे शेयर होल्डर उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें 3.3 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ था. अब सरेशवाला के पास दो ही रास्ते थे. पहला यह कि वह मुल्क छोड़कर ब्रिटेन चले जाएं और दूसरा यह कि हिंदुस्तान में ही रहकर अपना व्यवसाय दोबारा खड़ा करें.

ज़फर सरेशवाला के विरोधियों की मानें, तो उन दिनों उनके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी. दरअसल, गुजरात दंगों के बाद सरेशवाला ने ब्रिटेन की अलग–अलग जगहों पर वहां के भारतीय मूल के मुसलमानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न दंगा विरोधी कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर शिरकत की और हर कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भावनात्मक भाषण दिए, जिसकी वजह से गुजरात में उनके परिवार वालों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जाने लगा. इसलिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सरेशवाला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का फ़ैसला किया. अब सवाल यह था कि मुलाकात कैसे हो? तभी खुशकिस्मती से उनके हाथ एक सुनहरा मौक़ा लग गया. अगस्त 2003 में मोदी लंदन का दौरा करने वाले थे. जब सरेशवाला को यह ख़बर मिली, तो उन्होंने उत्तरी लंदन के हैकनी इलाके में, जहां बड़ी तादाद में गुजराती मुसलमान रहते हैं, के एक संगठन काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम के चेयरमैन मुनाफ जैना को फोन करके अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया और मोदी से मिलने की इच्छा ज़ाहिर की. मुनाफ जैना ने उनसे सहानुभूति जताते हुए कहा कि अगर मोदी से मुलाकात करके उनकी परेशानी ख़त्म हो सकती है, तो वह इसके लिए ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे.

दूसरी तरफ़ भारत में सरेशवाला ने मौलाना ईसा मंसूरी, इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा एवं फिल्म निर्देशक महेश भट्ट को इस बात के लिए राजी किया कि वे किसी तरह नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात करा दें. आख़िरकार सरेशवाला लंदन में अगस्त, 2013 में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने में सफल रहे. इस मुलाकात के बाद सरेशवाला का बयान अख़बारों में छपा. चूंकि वह नरेंद्र मोदी से कभी मिले नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके बारे में ग़लतफहमियां पाल रखी थीं, लेकिन मोदी से मुलाकात के बाद उनकी तमाम ग़लतफहमियां दूर हो गईं. इसके बाद बकौल ज़फर सरेशवाला, नरेंद्र मोदी ने एक बार उन्हें लंदन में फोन करके कहा कि कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे? मुल्क वापस आ जाओ. लिहाजा सरेशवाला पूरी तरह अपने वतन वापस आ गए. भारत वापसी के बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने उन पर अपनी मेहरबानियों की बौछार कर दी, तो उस एहसान का बदला चुकाते हुए सरेशवाला ने भी मुस्लिम दुश्मनी वाले मोदी के दाग को धोने की पूरी कोशिश की. तबसे लेकर आज तक वह लगातार इस कोशिश में लगे हैं और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि मुसलमानों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं.

मोदी से मुसलमानों को बातचीत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में शुरू से ही सरेशवाला यही दलील देते आए हैं कि उनका धर्म उन्हें यही सिखाता है कि अगर किसी समस्या के समाधान के लिए दुश्मन से भी बात करनी पड़े, तो ऐसी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. अब यहां सवाल यह उठता है कि सरेशवाला ने मोदी से मुलाकात करके मुसलमानों की कौन–सी समस्याओं का निराकरण कराया है? अख़बारों को दिए गए अपने इंटरव्यू में सरेशवाला बताते हैं कि 2006 में गुजरात में होने वाले कई एनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने वहां के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को निशाना बनाना शुरू किया, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कराकर इस समस्या का हल कराया था. उसी तरह वह यह भी दावा करते हैं कि वर्ष 2012 में जब गुजरात सरकार के एक विकास कार्यक्रम के चलते पुराने अहमदाबाद के 3,500 हॉकरों की रोजी–रोटी छिन गई, तो मोदी से मिलकर उन्होंने उन हॉकरों के पुनर्वास में मदद की.

वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो पार्टी के साथ–साथ मोदी ने भी मुसलमानों को अपने क़रीब लाने की कोशिश की. उसी कोशिश के तहत उन्होंने उर्दू अख़बारों एवं चैनलों को जो इंटरव्यू दिए, उनमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उनकी नज़र में हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे ही हैं, जैसे यहां की दूसरी कौमें. उन्होंने यहां तक कहा कि जिस दिन मुसलमान उन्हें पहचान लेंगे, वे उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेंगे. ज़फर सरेश वाला ने इस काम में मोदी का भरपूर साथ दिया. सबसे पहले उन्होंने नई दुनिया के एडिटर एवं समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद सिद्दीकी के साथ मोदी के इंटरव्यू की व्यवस्था कराई, जिसके छपने के बाद शाहिद सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी से छुट्टी हो गई. इसके बाद सरेशवाला की ही कोशिशों की वजह से मोदी का इंटरव्यू ईटीवी और आलमी समय पर प्रसारित हुआ.

प्रधानमंत्री बनने के बाद चूंकि नरेंद्र मोदी पर हिंदुस्तानी मुसलमानों का भरोसा बहाल नहीं हो सका है, इसलिए वह सरेशवाला की मदद से मुसलमानों के किसी न किसी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात का दौर जारी रखे हुए हैं. इन मुलाकातों के ज़रिये मोदी यह साबित करना चाहते हैं कि अब मुसलमानों को उनसे कोई शिकायत नहीं है. इन मुलाकातों के दौरान विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने बुनियादी मसलों जैसे दरगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों एवं वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के साथ–साथ मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए क़दम उठाने की दरख्वास्त की.

इन हालिया मुलाकातों के बाद देश के बड़े मुस्लिम संगठनों की तरफ़ से यह सवाल उठाया जाने लगा है कि प्रधानमंत्री अलग–अलग मसलकों एवं संप्रदायों के लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात–ए–इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा–ए–हिंद और मुस्लिम मुशावरत जैसे संगठनों से मुलाक़ात नहीं की. इसके बाद सरेशवाला एक बार फिर हरकत में आ गए और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इंकार कर दिया. इसके बाद 22 मार्च, 2015 को सरेशवाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बिन बुलाए पहुंच गए, जिस पर एमआईएम के सांसद असदउद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया. इसके बाद सरेशवाला को कार्यक्रम से बाहर जाना पड़ा. हालांकि, सरेशवाला ने सफाई पेश की कि बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनके संपर्क हैं और जयपुर के कार्यक्रम में वह उन्हीं के कहने पर गए थे.

बहरहाल, इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद सरेशवाला ने हार नहीं मानी है. वह लगातार इस कोशिश में हैं कि मोदी और मुसलमानों के बीच की दूरी कैसे कम की जाए. ख़बरों के मुताबिक, सरेशवाला ने देश भर के प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं से अलग–अलग मुलाकात की है. उन्हीं में से एक नाम मौलाना वली रहमानी का है, जो मुस्लिम मामलों के जानकार होने के साथ–साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं. सरेशवाला से उनकी मुलाकात 17 मई, 2015 को मुंबई के एक पांच सितारा होटल ताज लैंड इन में हुई, जिसमें सरेशवाला ने रहमानी को यह समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों के मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए. इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के बीच से ही कोई विश्वसनीय नेता मोदी से मुलाकात की पहल करे.

मौलाना वली रहमानी ने भी शर्त रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से वह तभी मिलेंगे, जब इस बात की गारंटी दी जाए कि यह सरकार मुस्लिम मसलों को हल करने के लिए संजीदगी से कोशिश करेगी और उस मुलाकात को चाय–पानी और फोटो सेशन तक सीमित नहीं रखेगी. बहरहाल, इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला. ताजा ख़बर यह है कि दो जून, 2015 को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी के नेतृत्व में मुसलमानों के अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की. हालांकि, इस सिलसिले में ज़फर सरेशवाला का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन मुसलमानों के इतने बड़े प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के पीछे सरेशवाला की भूमिका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है. इस मुलाकात के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे.

मुलाकात के बाद मौलाना इलियासी ने मीडिया से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप मन की बात करते हैं और हम आपसे दिल की बात करने आए हैं. आप जिन दिनों जर्मनी में मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, उन्हीं दिनों कुछ लोग मुल्क के अंदर हिंदुस्तान को तबाह करने की बात कर रहे थे. इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा, अगर आप किसी मसले को लेकर मेरे दरवाजे पर आधी रात को भी दस्तक देते हैं, तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं. इस मुलाकात को लेकर मीडिया चाहे जो कुछ भी कहे, पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पर मुसलमानों का भरोसा बहाल होने लगा है. जहां तक विदेशी मोर्चे पर मोदी के लिए राह आसान करने का सवाल है, तो यह हक़ीक़त है कि प्रधानमंत्री अब तक 20 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें से बांग्लादेश को छोड़कर उन्होंने अन्य किसी मुस्लिम देश का दौरा नहीं किया. इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सरेशवाला किसी बड़े मुस्लिम देश का दौरा करने की राह आसान करें. इस सिलसिले में ख़बर आ रही है कि सरेशवाला इस मुहिम में लग चुके हैं और पिछले दिनों उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), तुर्की और सऊदी अरब के अख़बारों में अपने इंटरव्यू छपवाए हैं, जिनमें मोदी से जुड़ी बातें भी कही गई हैं. लिहाजा आने वाले दिनों में यदि मोदी किसी मुस्लिम देश का दौरा करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे ज़फर सरेशवाला का हाथ ज़रूर है. ■

ज़फर सरेशवाला : एक परिचय

ज़फर सरेश वाला की मानें, तो उनके पूर्वज 250 साल पहले मौजूदा सऊदी अरब से हिजरत करके गुजरात में बस गए थे. उनका संबंध सुन्नी बोहरा समुदाय से है. यह समुदाय दाऊदी बोहरा से अलग है. ज़फर सरेशवाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं. पेशे के लिहाज़ से वह हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के जनक माने जाते हैं. यही नहीं, वह भारत के पहले और एकमात्र मुसलमान हैं, जिनकी कंपनी पारसोली कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है. ज़फर सरेशवाला के पिता मोहम्मद यूनुस सरेशवाला का अक्टूबर 2013 में देहांत हो गया था. ज़फर कहते हैं कि उनके पिता ने भी यही मशविरा दिया था कि वह मोदी के साथ अपने संबंध बरकरार रखें. ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यापमं घोटाला मौत की सुरंग बन गया है

[भारत में घोटालों का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाला अपने आप में अद्भुत है. इस घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हैं, इसका अंदाजा अब तक नहीं लगाया जा सका है. इस मामले से जुड़े 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. मौत का यह आंकड़ा बिहार में अपने समय के बहुचर्चित चारा घोटाले ने भी नहीं छुआ था. व्यापमं घोटाले में आए दिन रहस्यमयी मौत हो रही है, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी है. मौतों का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है. सुशासन का दावा करने वाले शिवराज का क्या यही है सुशासन?]

नवीन चौहान

मध्य प्रदेश का व्यापमं घोटाला दिन-प्रतिदिन उलझता ही जा रहा है. 2012 में इस मामले की जांच शुरू होने के बाद से अब तक मामले से जुड़े तकरीबन 40 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो चुकी है. ऐसा तब हो रहा है, जब इस घोटाले से जुड़े अधिकांश लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इन बिखरी कड़ियों को जोड़कर मामले के असली आरोपियों तक पहुंचने का जैसे-जैसे समय आ रहा है, वैसे ही मामले से जुड़े लोगों की संदेहास्पद मौतें होती जा रही हैं. इन मौतों से एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या इन हत्याओं के पीछे कोई साजिश है? मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने अब तक हुई मौत की वजहों को जानने की कोशिश नहीं की है, जबकि मरने वालों में से अधिकांश रैकेटियर(दलाल) थे, जो जांच में मुख्य कड़ी साबित हो सकते थे, जिनकी गवाही के जरिये इस मामले के आकाओं तक पहुंचा जा सकता था. मामले में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों पर आरोप लगे हैं. ऐसे में जांच में और भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता था. इसी वजह से घोटाले से जुड़े लोगों की मौतें हो रही हैं और उनकी मौत का रहस्य गहराता जा रहा है. जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, वे अपने बयान में उन लोगों का नाम ले रहे हैं, जो मर चुके हैं. अमूमन ऐसा तब किया जाता है, किसी मामले को गलत दिशा देना हो, जैसा कि इस मामले में हो रहा है.

एसआईटी प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रेश भूषण ने स्वीकार किया है कि आरोपियों की मौत से जांच प्रभावित हो रही है, जबकि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि व्यापमं घोटाले में संदिग्धों की मौत आशाराम बापू मामले में गवाहों की मौतों जैसी ही है. इस महाघोटाले में कई नामचीन लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद अभी भी कई बड़े लोग गिरफ्त से बाहर हैं. लिहाजा, उन्हें बचाने के लिए साक्ष्य नष्ट किए जाने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ किए जाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि जेल में बंद प्रमुख आरोपियों की भी हत्या हो सकती है. एसटीएफ ने अब तक हुई मौतों की वजह जानने की कोशिश नहीं की और न ही इन मौतों के बीच किसी तरह का लिंक ढूंढने की. इसके साथ ही आरोपियों की मौत के बाद उनसे जुड़े मामले की जांच भी बंद कर दी गई. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसआईटी इस मामले की जांच केवल लकीर की फकीर बनकर करेगी. यदि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होने के बावजूद जांच का दायरा सीमित रहेगा, तो मामले की निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करना बेमानी है. विपक्षी दल लंबे समय से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी द्वारा जांच के पक्ष में बयान देते रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

बात यहीं आकर नहीं थम रही है. इस मामले में व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, प्रशांत पांडे और आनंद राय पर भी लगातार हमले हो रहे हैं. ग्वालियर के आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि अब तक उनके ऊपर 13 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं. उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है, बावजूद इसके हर बार हमलावर उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं. हाल ही में जब वे ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक से मिलकर घर वापस लौट रहे थे, उस दौरान एक मोटर साईकिल सवार ने उनकी साईकिल पर जोरदार टक्कर मारी. उनका सुरक्षा गार्ड उनके साथ था. व्यापमं घोटाले के ही एक अन्य आरोपी के संबंध में आशीष के बयान 20 मई को दर्ज होने थे. उन पर हुए तात्कालिक हमले को उस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी तरह डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट अपने परिवार के साथ मऊ गए थे. मऊ से लौटते वक्त उनकी कार में एक अज्ञात डंफर ने टक्कर मारी. हालांकि टक्कर में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत को चोटें आईं. इसके बाद उन्होंने इंदौर में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाकर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रशांत पांडेय को दी गई सुरक्षा हटा ली गई थी. उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जो एक्सएल सीट कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को दी, जिसके आधार पर उन्होंने भोपाल में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर घोटाले में जुड़े होने का आरोप लगाया था, वह एक्सएल सीट उन्होंने एसटीएफ को नहीं दी थी. दिल्ली में रहने वाले प्रशांत पांडेय ने मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठे प्रभावी लोगों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाइकोर्ट में अपनी सुरक्षा के संबंध में याचिका दायर की थी. 20 फरवरी, 2015 को हाइकार्ट ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसी तरह एक अन्य व्हिसिल ब्लोअर इंदौर के डॉ आनंद राय को भी लगातार धमकियां मिलती रहती हैं, उन्हें भी सुरक्षा दी गई है.

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले के 55 मामलों में 2500 लोग आरोपी हैं. अब तक 1980 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. साढ़े पांच सौ आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है. जांच जारी है. ऐसे में एक दिन यह तथ्य सामने आता है कि इस घोटाले से जुड़े चालीस लोगों की साल 2012 से 2015 के बीच संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं. तीन साल के अंदर व्यापमं घोटाले से जुड़े चालीस लोगों की मौतें ढेरों सवाल खड़े करती है. देश के इतिहास में आज तक ऐसा किसी घोटाले में नहीं हुआ है कि मामले से जुड़े लोगों की लगातार मौतें होती रहें और प्रशासन इस पर मौन रहे. लोगों की मौत की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. जांच रुक सी गई है, क्योंकि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए लोग उन लोगों का नाम ले रहे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है. पूछताछ के दौरान कुछ लोग मर चुके अलग-अलग लोगों के नाम ले रहे हैं और कुछ मर चुके किसी एक व्यक्ति का. इस पर एसटीएफ प्रमुख चंद्रेश भूषण का कहना है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जांच अब आगे कैसे बढ़ेगी. कोई नया सुराग नहीं मिल रहा है. लोगों की मौत होने की बात जब से सामने आई है, तब से उन लोगों के मन में भी किसी का नाम लेने से होने वाले अंजाम का डर बैठ गया है. लोग इस बात से डरे हुए हैं कि यदि वह किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो अगला नंबर कहीं उनका ही न हो जाए.

पिछले दिनों रीवा के फार्मासिस्ट विजय सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक लॉज में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए. प्राथमिक जांच में उनकी मौत जहर की वजह से होना पाया गया है. उसी तरह प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश की मौत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में भी जहर पाया गया था. इसी तरह इंदौर की छात्रा नम्रता दामोर अचानक लापता हो गई और कुछ दिनों बाद उसका शव उज्जैन के निकट रेल की पटरियों पर मिला. उसके साथ बलात्कार की भी पुष्टि हुई. इसी तरह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ सांकले की मौत भी पहेली बनी हुई है. उन्होंने डीन रहते जबलपुर मेडिकल कॉलेज से उन 93 लोगों को बाहर निकाला था, जिन्होंने व्यापमं घोटाले के जरिये एमबीबीएस में प्रवेश पाया था. डॉ सांकले की मौत कैरोसिन छिड़कर आग लगाने से हुई है, जबकि वो डॉक्टर थे और दर्द रहित मौत को गले लगा सकते थे. इसलिए उनकी मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं. इसी तरह ग्वालियर में रामेंद्र सिंह भदौरिया का शव उन्हीं के घर में फंदे से लटका हुआ मिला. उनकी मौत को असफल प्रेम संबध से जोड़ दिया गया. ग्वालियर के ही ललित कुमार गोलारिया ने मुरैना के निकट सांक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली. उनकी जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ, लेकिन इन सभी मामलों को समग्र और एकीकृत रूप से जोड़कर नहीं देखा गया. ऐसे में जांच प्रकिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है. यदि इस मामले की जांच राज्य सरकार वाकई में करना चाहती है, तो उसे इसकी जांच सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुशासन का दावा करने वाली शिवराज सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है. ■

navinonline2003@gmail.com

व्यापमं घोटाले से जुड़े लोग, जो अब नहीं रहे

1. अंशुल सचान,
2. अनुज पांडेय
3. विक्रम सिंह
4. अरविंद शाक्य
5. कुलदीप मारावी
6. अनंत राम टैगोर
7. आशुतोष तिवारी
8. ज्ञान सिंह(भिंड)
9. प्रमोद शर्मा(भिंड)
10. विकास पांडेय(इलाहाबाद)
11. विकास ठाकुर(बड़वानी)
12. श्यामवीर सिंह यादव
13. आदित्य चौधरी
14. दीपक जैन(शिवपुरी)
15. ज्ञान सिंह(ग्वालियर)
16. बृजेश राजपूत(बड़वानी)
17. नरेंद्र सिंह राजपूत(झांसी)
18. आनंद सिंह यादव(फतेहपुर)
19. अनुरुद्ध उइके(मंडला)
20. ललित कुमार पशुपतिनाथ जायसवाल
21. राघवेंद्र सिंह(सिंगरौली)
22. आनंद सिंह(बड़वानी)
23. मनीष कुमार समाधिया(झांसी)
24. दिनेश जाटव
25. ज्ञान सिंह(सागर)
26. शैलेश यादव(लखनऊ) (पोस्टमॉर्टम में जहर पाया गया), 25 मार्च 2015
27. विजय सिंह पटेल (छत्तीसगढ़ में काकेर में एक लॉज में मृत पाया गया) 28 अप्रैल 2015
28. नम्रता दामोर (इंदौर) (रेल की पटरियों पर मृत पाई गई, बलात्कार की पुष्टि)
29. रामेंद्र सिंह भदौरिया का शव उन्हीं के घर में फंदे से लटका हुआ मिला . 8 जनवरी 2015
30. बंटी सिंह सिकरवार
31. ललित कुमार गोलारिया (मुरैना के सांक नदी में कूदकर आत्महत्या की). जेब से सुसाइड़ नोट बरामद. 15 जनवरी 2015
32. डॉक्टर डीके सांकले (जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के डीन) संदिग्ध हालत में जलकर मौत.4 जुलाई 2014

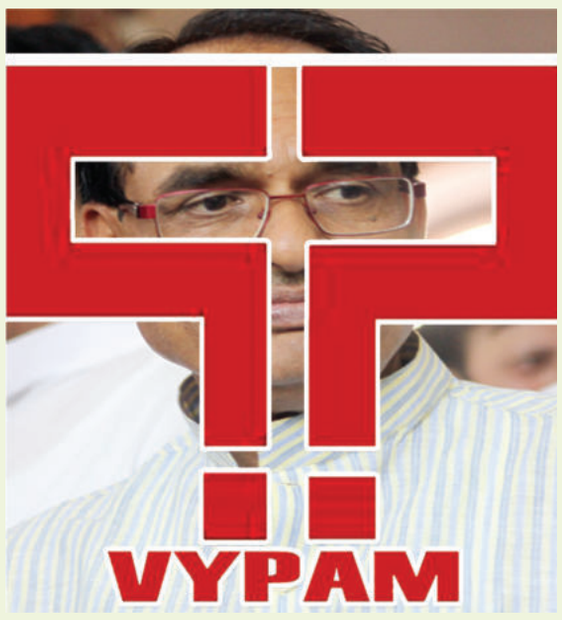

हज कमेटी ने भ्रष्टाचार का नया रास्ता तलाशा

वसीम अहमद

वर्ष 2015 में एक लाख 36 हज़ार 20 भाग्यशाली लोग हज यात्रा पर जायेंगे. इनमें से 36 हज़ार हाजी निजी टूर से और शेष हज कमेटी के अंतर्गत जायेंगे. हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के निवास, सफर और अन्य व्यवस्था से संबंधित समस्याओं की देखभाल करती है. इस काम में जेद्दाह में भारतीय कॉन्सलेट इसकी सहायता करता है. अतीत में हज कमेटी ऑफ इंडिया पर जिम्मेदारियों में कोताही, विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष सरकार से मिली करोड़ों रुपये की सब्सिडी में हेराफेरी का आरोप लगता रहा है. पिछले साल सरकार ने 691 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी. इस सब्सिडी का मक़सद था हाजियों पर आर्थिक बोझ कम करना. इसके बावजूद हाजी से एक लाख 80 हज़ार रुपये वसूल किये गये थे, जबकि इस सब्सिडी के बाद हाजियों से ली जाने वाली राशि बहुत हद तक कम होनी चाहिए, लेकिन कम होने के बजाए प्रत्येक वर्ष इसमें तेज़ी से बढ़ोत्तरी होती जा रही है. 2015 में हाजियों से प्राप्त की जाने वाली राशि के बारे में दिल्ली हज हाउस के चेयरमैन परवेज़ मियां से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि इस वर्ष दो लाख तक वसूल किये जा सकते हैं. हाजियों से जो राशि वसूल की जाती है, उनमें से 2100 रियाल उन्हें मक्का में निजी ख़र्चों के लिए वापस कर दिये जाते थे, लेकिन इस वर्ष केवल 1500 रियाल ही दिये जायेंगे और इसके बाद जो राशि बच जाएगी, उसको मक्का, मदीना और और मिना में निवास और अन्य चीज़ों पर ख़र्च किया जाएगा. सरकार की ओर से सब्सिडी के नाम पर जो राशि दी जाती है, उसका फ़ायदा हाजियों को नहीं मिलता है, क्योंकि हाजियों को एयर इंडिया से सफर कराया जाता है और एयर इंडिया मौके का फ़ायदा उठाते हुए हज के मौसम में अपना किराया बहुत बढ़ा देता है. इस बढ़ाये गये किराये को सब्सिडी की राशि से वसूल किया जाता है. इस प्रकार से सब्सिडी की सभी राशि एयर इंडिया के खाते में चली जाती है. अगर हज कमेटी और कॉन्सलेट इसको लेकर गंभीर होते तो अन्य एयरलाइंस को कॉन्ट्रैक्ट देकर कम क़ीमत पर हाजियों को यात्रा कराने की जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन वह ऐसा न करके सब्सिडी के पैसों में घोटाले का रास्ता

खुला रखना चाहती हैं. अभी हाल ही में तेलंगाना की राज्य हज कमेटी की ओर से अपील की गई थी कि उसे अपने हाजियों को सऊदी एयरलाइंस से सस्ती दरों पर यात्रा कराने की अनुमति दी जाये, जिसको सेंट्रल हज कमेटी ने नामंजूर कर दिया. हज की राशि में होने वाले घोटाले पर एक बार जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि हज जैसी पवित्र यात्रा के नाम पर घोटाले किये जाते हैं. उनके बयान के बाद पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी ने हज कमेटी में होने वाले भ्रष्टाचार पर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, लेकिन यह मामला दब गया और किसी कार्रवाई की ख़बर नहीं मिली. अगर सरकारी सब्सिडी का सही प्रयोग हो तो हज पर आने वाले ख़र्चों में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है. बहरहाल, हाजियों को जहां व्यवस्था को लेकर अनगिनत समस्याओं का सामना करना होता है, वहीं आर्थिक दृष्टि से भी उन पर अनावश्यक बोझ डाल दिया जाता है. जैसा कि हज 2015 के लिए हज कमेटी ने एक ऐसा अतार्किक निर्णय लिया है, जिस कारण उसकी पारदर्शिता और ज़्यादा संदिग्ध हो गई है. इस निर्णय के कारण दारूल उलूम देवबंद से लेकर बरेली मकतबा-ए-फिक्र के मदरसे अशरफुल उलूम तक ने हज कमेटी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. दरअसल, यह निर्णय हज की एक महत्वपूर्ण रस्म 'कुरबानी' को लेकर है, जिसे मिना में कंकरी मारने के बाद अंजाम दिया जाता है. उसको अदा करने में हाजियों को धार्मिक दृष्टि से अधिकार प्राप्त है कि जिसने हज-ए-उफराद का अहराम बांधा है, वह कुरबानी नहीं दे और जिसने तमत्तो का अहराम बांधा है, अगर वह ग़रीब है तो कुरबानी की जगह रोज़े रख ले. यह एक धार्मिक मामला है, जिसका सही स्पष्टीकरण उलेमा करा सकते हैं और इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय हज कमेटी या कॉन्सलेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन पिछले दिनों हज कमेटी ने अपने इस निर्णय से धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करके देवबंद से लेकर बरेलवी उलेमा तक को अपना कड़ा विरोधी बना लिया. इस निर्णय में हज कमेटी ने कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक हज पर जाना चाहते हैं, उनके लिए कुरबानी की राशि हज कमेटी के खाते में जमा करानी होगी. इसका मतलब यह हुआ कि हज कमेटी के तहत एक लाख 20 हाजियों को प्रत्येक कुरबानी 469 रियाल के हिसाब से यह राशि जमा करनी होगी और जो ऐसा नहीं करेंगे, उनका पुष्टीकरण रद्द किया जा सकता है.

हज कमेटी ने हाजियों से पैसा कमाने के लिए एक और रास्ता तलाश कर लिया है और वह है सूटकेस की उपलब्धता का रास्ता. विदेश मंत्रालय ने हज कमेटी से जाने वाले सभी हज यात्रियों के लिए निर्धारित वज़न के अनुसार दो सूटकेस उपलब्ध कराने का निर्णय किया है. इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी को दी गई है और प्रत्येक हज यात्री से 5100 रुपये वसूल करने का निर्णय किया गया है. हैरानी की बात यह है कि जिस सूटकेस की क़ीमत बाज़ार में मुश्किल से एक हज़ार से 1200 रुपये तक है, उसकी क़ीमत हज कमेटी ने 5100 रुपये लगाई है. ज़ाहिर है, इस लूट पर कई राज्य हज कमेटियों ने विरोध किया. इस विरोध की वजह से सूटकेस की क़ीमत में कमी तो नहीं की गई, लेकिन हाजियों को मक्का पहुंचने के बाद जो 2100 रियाल दिये जाते हैं, अब उसी राशि से सूटकेस की रक़म काट ली जायेगी. ज़ाहिर है उन्हें मक्का पहुंचने के बाद केवल 1500 रियाल ही दिये जायेंगे, जिसमें उन्हें अपने सभी ख़र्चे पूरे करने होंगे. अगर वह खजूर, मुसल्लाह और तस्बीह आदि ख़रीदना चाहेंगे तो उसी राशि में से ख़रीदना होगा. इस सिलसिले में यह बात कही जा रही है कि इस जबरन क़ानून में हज कमेटी का कहीं न कहीं आर्थिक फ़ायदा है और हो सकता है कि जिस कंपनी को सूटकेस बनाने का ठेका दिया जाता है, उस कंपनी से सेंट्रल हज कमेटी को अच्छा-ख़ासा कमीशन मिल जाए. हालांकि हज कमेटी का गठन हाजियों की परेशानियों को दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन मामला इसके बिल्कुल उलट दिखाई देता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गठबंधन का नेता पद बड़ा मसला बन गया है. नीतीश कुमार और जद (यू) का मानना है कि चुनाव सिर पर हैं और बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम की घोषणा कर दी जानी चाहिए. ऐसा न करने से भ्रांति फैल रही है. लेकिन, लालू प्रसाद और उनके खास लोग इसके घोर विरोधी हैं. उनका मानना है कि चुनाव लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाए और गठबंधन के नेता की घोषणा चुनाव बाद की जाए. राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले नीतीश कुमार को गठबंधन के नेता के तौर पर पेश करने से मना कर दिया है.

मुख्यमंत्री निवास या हम कार्यालय

जीतन राम मांझी सीएम हाउस पर जिस अवैध और अनैतिक तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं. मसलन, कोई महादलित किसी की हत्या कर दे और पुलिस उसे पकड़ने जाए तो क्या यह कह कर उस कार्रवाई को रोका जा सकता है कि वो महादलित है? क्या कोई महादलित भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच न हो? कोई महादलित कानून और नैतिकता की धज्जियां उड़ाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई न हो. कोई पूर्व मुख्यमंत्री सीएम हाउस पर अवैध और अनैतिक तरीक से कब्जा जमा कर वहां से पार्टी कार्यालय चलाए तो क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यहां सवाल पिछड़े, दलित, महादलित, सवर्ण या अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं है, सवाल नैतिकता और कानून का है, जिसके हिसाब से जीतन राम मांझी गलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

सरोज सिंह

विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर आम और लीची सियासी मोहरे बन जाएं तो आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की राजसत्ता के लिए नेताओं का कितना कुछ दांव पर लगा है. सूबे के मुख्यमंत्री निवास यानी एक अणे मार्ग में आम और लीची पर सरकारी पहरे की खबर जैसे ही देश और दुनिया में सुर्खियां बनी, एक चर्चा साथ-साथ चल पड़ी कि लोकतंत्र में नैतिकता की जगह अब बची भी है या नहीं. नैतिकता की बहस ने इस बात को भी चर्चा में ला दिया कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम के लिए आवंटित मकान एक अणे मार्ग और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्व सीएम के लिए आवंटित मकान 12 स्टैंड रोड में क्यों नहीं रह रहे हैं. इस चर्चा का भी विश्लेषण करेंगे, पर पहले आम और लीची के ताजा विवाद और उस पर हो रही राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं. बकौल जीतनराम मांझी 5-6 दिन पहले पत्नी ने कहा था कि उसने लीची तोड़ने के लिए एक आदमी को भेजा था. जब वह लीची तोड़ने गया तो सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया. सीएम हाउस में तैनात एक माली को इस बात का बुरा लगा. उसने सोचा कि मालकिन लीची मांग रही हैं और उसे नहीं मिले, यह अच्छा नहीं है. वह गया और जबरदस्ती लीची तोड़ लाया. बाद में मुझे पता चला कि उस माली को लीची तोड़ने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है.

गौरतलब है की फरवरी में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भी मांझी मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं, जबकि नीतीश 7 सर्कुलर रोड स्थित एक सरकारी आवास में रह रहे हैं. अब ऐसे में फलों व सब्जियों की रखवाली के लिए एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की तैनाती की, तो मामला तुल पकड़ लिया. हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात से इंकार किया है और कहा कि मुझे तो आवाम की चिंता है, आम की नहीं. अगर पता होता कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आम की इतनी चिंता है, तो मैं कब का तोड़वा कर भिजवा देता. नीतीश ने कहा कि जिन्हें आम खाना है, वे खूब खाएं, कटहल पर पहरेदारी जैसी ओछी हरकत नहीं करता और मांझी आम और लीची तोड़ लें, मैं अपने वेतन से उसकी कीमत का भुगतान कर दूंगा.

विवाद बढ़ा, तो राज्य पुलिस ने आनन-फानन में आंतरिक जांच करवा डाली. एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने जानकारी दी कि किसी सुरक्षाकर्मी ने पूर्व मुख्यमंत्री या उनके परिजन को आम और लीची तोड़ने से रोका नहीं है. वहां आम, लीची और कटहल की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और यह कोई नई बात नहीं है. पिछले साल भी 11 मई से 31 जुलाई तक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. इस साल यह काम 15 मई से शुरू हुआ है. एडीजी की सफाई के बाद तो यह साफ हो गया कि मामला प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक है और इसमें देर भी नहीं हुई. जीतन राम मांझी ने कहा कि इतने सुरक्षा बल अगर गांधी सेतू में लगाए जाते तो बिहार की जनता को जाम से मुक्ति मिलती. श्री मांझी ने महादलित कार्ड खेलते हुए कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कोई महादलित अणे मार्ग में आम व लीची खाए. नीतीश कुमार को इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए. दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हमें तो आम नहीं, अवाम की चिंता है. कुछ लोग मोह में फंस गए हैं. इसका इलाज तो जनता ही करेगी. कुछ ही महीने की बात है, जनता जिसे चाहेगी, वही अणे मार्ग में रहेगा. सुशील मोदी ने भी मौका नहीं गंवाया और कहा कि नीतीश आम की चटनी तक के लिए श्री मांझी को तरसा रहे हैं. नीतीश को बर्दाश्त नहीं कि महादलित सीएम आवास में लगे फलों को चखें. इन सियासी बयानबाजियों से निकलें, तो इस ताजा विवाद के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि महादलितों के वोटों का कैसे ज्यादा से ज्यादा ध्रूवीकरण हो, इसका कोई भी मौका जीतन राम मांझी नहीं छोड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री आवास छोड़ने की पहले उन्होंने शर्त रखी थी कि नीतीश कुमार सात सर्कुलर रोड वाला अपना बंगला हमें दे दें, तो मैं एक अणे मार्ग खाली कर दूंगा. उनका तर्क था कि चूंकि नीतीश कुमार उस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से रह रहे हैं और चूंकि वह अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए वह सात सर्कुलर रोड छोड़ दें और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं उसमें चला जाता हूं, लेकिन सरकार ने उनके लिए 12 स्टैंड रोड का बंगला आवंटित कर रखा है, जिसको सजाने-संवारने में अभी तक लगभग एक करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं. अब इस ताजा विवाद के बाद श्री मांझी ने कहना शुरू कर दिया है कि चूंकि 12 स्टैंड रोड वाल बंगला अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैं अणे मार्ग में हूं, जिस दिन वह तैयार हो जाएगा, मैं उसमें चला जाऊंगा, लेकिन वह साथ ही साथ यह भी जोड़ दे रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को भी सात सर्कुलर रोड वाला बंगला छोड़ देना चाहिए. जानकार बताते हैं कि चुनाव तक श्री मांझी मुख्यमंत्री आवास से हटने वाले नहीं हैं. उनको लगता है कि वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए बंगला छोड़ना ठीक नहीं है. गौरतलब है कि जीतनराम मांझी की पार्टी हम का सारा काम इन दिनों मुख्यमंत्री आवास से ही हो रहा है. इसी आवास में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक होती है. हम के पोस्टर और बैनर से मुख्यमंत्री आवास के कई कमरे पटे पड़े हैं. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि नैतिकता का तकाजा तो यही है कि जीतन राम मांझी को इस्तीफा देने के बाद ही बंगला खाली कर देना चाहिए था. नीतीश कुमार ने ऐसा करके एक मिसाल कायम किया था, लेकिन श्री मांझी मोह में फंस गए हैं. उनको कम से कम मुख्यमंत्री निवास की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए. मुख्यमंत्री आवास को तो उन्होंने हम का पार्टी कार्यालय बना कर रख दिया है. नीरज कहते हैं कि बिहार की जनता इन चीजों को बहुत ही गौर से देख रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि सूबे की जनता वोट के माध्यम से एक अणे मार्ग की गरिमा को बहुत जल्द बहाल करेगी. नीरज कहते हैं कि मांझी को कम से कम इस मामले में नीतीश कुमार का अनुसरण करना चाहिए था. खैर, आम और लीची का सीजन तो एक महीने में खत्म हो जाएगा और अगले साल उन पेड़ों पर फिर फल आ जाएंगे, लेकिन चुनावी फायदे के लिए ओछे विवाद पैदा करने से कहीं न कहीं बिहार की गरिमा को धक्का लगता है. पूरा देश बिहार के चुनावों पर पैनी नजर बनाए हुए है. ऐसे में अगर सियासी मोहरे आम और लीची बनेंगे, तो फिर जगहंसाई बिहार की ही होगी. इसलिए बिहार के राजनेताओं को इस चुनाव में ऐसी चीजों का तो ख्याल रखना ही होगा. ■

नीतीश कुमार-लालू प्रसाद यादव

कभी पास, कभी दूर

चौथी दुनिया ब्यूरो

जनता परिवार के छह दलों के विलय को लेकर बिहार में तो अर्से से आशंका जताई जा रही थी, पर इस कसरत के इस अंत की उम्मीद नहीं थी. हालात ऐसे होते जा रहे हैं, जिनमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं विरोधी दलों के गठबंधन की उम्मीद भी स्वार्थ और अहम की राजनीति का शिकार होती जा रही है. हिंदी पट्टी में जनता परिवार के सबसे बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव के कुछ बोलने के पहले ही यह तो साफ़ हो गया था कि विलय अभी महीनों (सालों भी हो सकता है) संभव नहीं है, पर उम्मीद थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की सत्रह साल के बाद की दोस्ती इस सूबे में भाजपा का कोई ठोस विकल्प देगी, लेकिन वे विकल्प देने के बजाय खुद ही अखाड़े में एक-दूसरे को चुनौती देने लगे हैं. हालांकि, उम्मीद की लौ अब तक पूरी बुझी नहीं है.

जद (यू) को 2010 में राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. उस चुनाव में यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का अंग था. भाजपा के हिस्से में 91 सीटें आई थीं. जबकि लोजपा को तीन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सीट मिली थी. जद (यू) अपनी इन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राजद प्रमुख किसी भी क़ीमत पर जद (यू) से अधिक सीटें चाहते हैं. गत संसदीय चुनाव के नतीजों के आधार पर उन्होंने अपना राजनीतिक दावा-पत्र तैयार किया है. उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में राज्य विधानसभा के 33 निर्वाचन क्षेत्रों में राजद एक नंबर की और 110 क्षेत्रों में दो नंबर की पार्टी रही है. सो, 143 सीटों पर उसका सहज दावा बनता है. उस चुनाव में जद (यू) केवल 18 सीटों पर एक नंबर की पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस तेरह सीटों पर पहले स्थान पर थी. राजद का कहना है कि इसी ढंग से सीटों का बंटवारा हो. चूंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसके साथ बड़े भाई जैसा सुलूक हो और बड़ा हिस्सा भी चाहिए. राजद के इस तर्क को नीतीश कुमार कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सो, जद (यू) ने इसे स्वीकार नहीं किया है. कांग्रेस को भी राजद का यह तर्क स्वीकार करने में परेशानी है. लेकिन जद (यू) एवं कांग्रेस इस मायने में राजद से भिन्न हैं कि उन्होंने अब तक मीडिया की कोई मदद नहीं की और मीडिया में जाने से दोनों ने ही कमोबेश संयम बरता है. एक फॉर्मूला यह भी सामने आया कि जद (यू) और राजद विधानसभा की सौ-सौ सीटें आपस में बांट लें, शेष सीटें कांग्रेस और वाम दलों (यदि वे गठबंधन में शामिल होते हैं तो) को दे दी जाएं. राज्य में विधान परिषद की चौबीस सीटों पर चुनाव होने हैं और उसमें इसी फॉर्मूले का पालन किया जा रहा है. हालांकि, वाम दल परिषद चुनाव में राजद-जद (यू)-कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं हुए.

इस फॉर्मूले को ज़मीन पर उतारने के लिए जद (यू) अपनी कई सीटों की कुर्बानी दे रहा है. चूंकि विधान परिषद की सीटों की कमी-बेशी से सरकार के बनने-बिगड़ने का कोई संबंध नहीं होता है, सरकार में बड़े भाई की दावेदारी पर भी कोई असर नहीं पड़ता, लिहाजा इसे जद (यू) ने स्वीकार कर लिया और अपने लोगों को संदेश भी दे दिया. लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के इस फॉर्मूले पर जद (यू) तैयार नहीं है. वस्तुत: भाजपा विरोधी गठबंधन में कई पेंच हैं. विधानसभा की सीटों को लेकर तो पेंच बार-बार फंसना तय है. मसला केवल सीटों की संख्या को लेकर ही नहीं है, बल्कि कौन-सी सीट किसके पाले में जाए, यह भी ज़िला स्तर पर विवाद का कारण बन जा सकता है.

गठबंधन का नेता पद बड़ा मसला बन गया है. नीतीश कुमार और जद (यू) का मानना है कि चुनाव सिर पर हैं और बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम की घोषणा कर दी जानी चाहिए. ऐसा न करने से भ्रांति फैल रही है. लेकिन, लालू प्रसाद और उनके खास लोग इसके घोर विरोधी हैं. उनका मानना है कि चुनाव लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाए और गठबंधन के नेता की घोषणा चुनाव बाद की जाए. राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले नीतीश कुमार को गठबंधन के नेता के तौर पर पेश करने से मना कर दिया है. यह अब तक राजद और जद (यू) के आंतरिक हलकों में चर्चा का विषय था, पर रघुवंश बाबू ने इसे सतह पर ला दिया है. पटना के राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि गठबंधन के मुतल्लिक राजद की ओर से प्रक्षेपास्त्र भले ही रघुवंश प्रसाद सिंह छोड़ रहे हैं, पर उसके पीछे लालू प्रसाद या उनके परिवार या राजद के कुछ बड़े नेताओं का हाथ ज़रूर है. लालू प्रसाद की भूमिका और खामोशी इसी शंका को बल दे रही है.

गठबंधन के पेंच जीतन राम मांझी और बागी राजद सांसद पप्पू यादव से भी गहरे जुड़े हैं. राजद प्रमुख बिहार में भाजपा विरोधी व्यापक गठबंधन में जीतन राम मांझी की ज़रूरत बार-बार रेखांकित कर नीतीश कुमार की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं. यही राजनीतिक स्थिति पप्पू यादव की है. राजद प्रमुख मधेपुरा के इस सांसद को देखना तो दूर, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते. हालांकि, नीतीश कुमार और उनके दल के किसी बड़े नेता ने पप्पू यादव को तरजीह देने जैसा कोई बयान अब तक नहीं दिया है, पर राजद से निष्कासन के बाद वह जद (यू) के कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में हैं. हाल में पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ़ की, तो जद (यू) के कुछ नेताओं ने कहा भी कि यदि उनका भरोसा जद (यू) की नीति और विचारधारा में है, तो उनका स्वागत है. ऐसे बयान जिन लोगों की ओर से आए हैं, वे नीतीश कुमार के खास माने जाते रहे हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा विरोधी राजनीति सुरंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है. सबसे घातक यह है कि इसे सुरंग में जाने से रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं हो रही है. यदि हो भी रही है, तो नेताओं की शर्तों पर, आधे-अधूरे मन से. दिग्गज समाजवादी मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार और अपनी सरकार के दायरे में फंसकर विलय को रास्ते में ही प्राय: छोड़ दिया है, तो लालू प्रसाद अपनों के प्रत्यक्ष-परोक्ष नीतीश विरोध और वंश की अपेक्षाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. अब गठबंधन का विचार भी डूबता नज़र आ रहा है. देखिए, आगे क्या होता है! ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान देने से विकास होगा

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दर को 25 बेसिस प्वॉइंट घटा दिया है और अब यह 7.25 फ़ीसद है. प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच समन्वय की कमी दिखती है. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि यह समय सही नहीं है. असल में उन्होंने एक मजबूत बयान दिया है कि वह अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और नीचे नहीं ले जा सकते. उनका एक मजबूत दृष्टिकोण है. हमारे पास अरविंद सुब्रह्मण्यम के रूप में एक आर्थिक सलाहकार हैं, वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं. इन सबको रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ बैठकर एक ऐसा रास्ता तलाशना चाहिए, जिससे निवेश आए, ग्रोथ हो, क्योंकि इसके बिना सरकार वह सब नहीं हासिल कर सकती, जो पाना चाहती है.

अख़बारों में आ रहा ताजा विवाद दूषित मैगी नूडल्स का है. इस कहानी के दो पहलू हैं. एक यह कि मैगी नूडल्स के कुछ बैच आवश्यक मानकों के अनुसार न हों, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए उसके ब्रांड एंबेसडर पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए. इसके विपरीत यह सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे इन बैचों की जांच लगातार करते. उन्हें इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और संबंधित लोगों को निलंबित कर दिया जाना चाहिए. महाराष्ट्र में ऐसा कोई बैच नहीं पाया गया है. जाहिर है, पूरी ग़लती ब्रांड की नहीं है और इसलिए ब्रांड एंबेसडर की ग़लती ढूंढने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. वे लोग प्रतिष्ठित और क्षमतावान लोग हैं, वे जानबूझ कर ऐसा काम नहीं करेंगे. एक और पक्ष है, जो थोड़ा चिंतित करता है कि नेस्ले एक स्विस कंपनी है और स्विस मानक बहुत ही उच्च होते हैं. ऐसी संभावना नहीं है कि वह (नेस्ले) अपने मानकों को कमज़ोर करेगी, लेकिन ये मल्टी नेशनल कंपनियां भारत के कमज़ोर मानकों को लेकर थोड़ी लापरवाही भी बरतती हैं. यहां पर पर्यवेक्षण, विनियमन एवं कार्यान्वयन थोड़ा ढीला है, इसलिए हर कोई लाभ लेने की कोशिश करता है. सरकार मामले की तह तक पहुंच कर उचित कार्रवाई करे, तो बेहतर होगा. बिहार की मुजफ्फरपुर अदालत द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाने की कोशिश करना हास्यास्पद है. दिल्ली उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपने हाथ में इस मामले को लेकर उचित दिशा-निर्देश देना चाहिए.

एक अन्य रोचक बात पढ़ने को मिली. फायर ब्रांड आरएसएस मैन विनय कटियार, जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे हैं, ने कहा है कि 1991 में चंद्रशेखर सरकार एक महीने और बनी रहती, तो राम मंदिर मुद्दे का हल हो जाता और मंदिर बन जाता. यह सही बात है. इस पर एक श्वेत-पत्र भी है, जिसका हवाला अक्सर श्री लालकृष्ण आडवाणी देते रहे हैं. हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों की सहमति से एक सौहार्द्रपूर्ण समाधान बस होने ही वाला था. अब उसके बाद नरसिम्हा राव ने क्यों उस पर अमल नहीं किया और उस श्वेत-पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया, पता नहीं. लेकिन इससे हुआ यह कि मामला खटाई में पड़ गया. डेढ़ साल बाद छह दिसंबर, 1992 को उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया. उसके बाद से आज 23 सालों बाद भी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती चली गई. इसे देश की हानि के रूप में देखा गया. अभी भी दोनों पक्षों के अच्छी सोच वाले लोगों को एक साथ बैठकर एक फॉर्मूला विकसित करना चाहिए.

जाहिर है, चंद्रशेखर फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा, क्योंकि अब वह ढांचा मौजूद नहीं है. मुसलमान पहले से ही अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन यदि मौजूदा सरकार विकास के लिए खुद को समर्पित मानती है, तो उसे किसी तरह से इस भावनात्मक मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए. हम सभी जानते हैं कि विकास तब तक नहीं होगा, जब तक दो समुदाय आपस में टकराव पर समय खर्च करते रहें और व्यवहारिक मुद्दों की जगह भावनात्मक मुद्दे पर ज़ोर देते रहें. सीरिया या इराक या यमन या सऊदी अरब में क्या हुआ, इसे हम देख सकते हैं. राजनीतिक नेतृत्व का काम गुस्सा नीचे लाना है, न कि वास्तविक या काल्पनिक, छोटे या बड़े मतभेद को बढ़ावा देना, जो कि चीजों को बदतर बना देता है. मैं आशा करता हूं कि विनय कटियार अध्ययन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या समझौता हुआ था और उसे अब कैसे आगे ले जाया जा सकता है. यह देश की अस्सी फ़ीसद आबादी के हित में है. यह मुद्दा कोई ऐसा अप्रिय मोड़ न ले, जो देश के लिए अच्छा न हो.

एक अन्य रोचक बात पढ़ने को मिली. फायर ब्रांड आरएसएस मैन विनय कटियार, जो राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे हैं, ने कहा है कि 1991 में चंद्रशेखर सरकार एक महीने और बनी रहती, तो राम मंदिर मुद्दे का हल हो जाता और मंदिर बन जाता. यह सही बात है. इस पर एक श्वेत-पत्र भी है, जिसका हवाला अक्सर श्री लालकृष्ण आडवाणी देते रहे हैं. हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों की सहमति से एक सौहार्द्रपूर्ण समाधान बस होने ही वाला था.

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दर को 25 बेसिस प्वॉइंट घटा दिया है और अब यह 7.25 फ़ीसद है. प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच समन्वय की कमी दिखती है. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि यह समय सही नहीं है. असल में उन्होंने एक मजबूत बयान दिया है कि वह अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और नीचे नहीं ले जा सकते. उनका एक मजबूत दृष्टिकोण है. हमारे पास अरविंद सुब्रह्मण्यम के रूप में एक आर्थिक सलाहकार हैं, वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं. इन सबको रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ बैठकर एक ऐसा रास्ता तलाशना चाहिए, जिससे निवेश आए, ग्रोथ हो, क्योंकि इसके बिना सरकार वह सब नहीं हासिल कर सकती, जो पाना चाहती है. मैं शेयर बाज़ार या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी केवल तभी आएगा, जब ये सारी पहल हो. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अभी भी निवेशकों के सिर पर लटक रही एक तलवार है. मैट एक अन्य चिंता का कारण है. यह सरकार जिस आर्थिक नीति को आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें विश्वास की कमी है. हम लोग समाजवादी सोच के हैं, इसलिए बाज़ारवाद के बड़े प्रशंसक नहीं हैं. लेकिन चूंकि यह सरकार चीन, जापान एवं अमेरिका को लुभाना चाहती हैं, तो फिर पहले अपना घर ठीक करना होगा. आप यहां उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसे और जिस आर्थिक वातावरण में भारत के उद्यमी काम करते हैं, वैसे वातावरण में विदेशी निवेशक काम करेंगे. भारत में हर कोई रिश्वतखोरी से लेकर कठोर क़ानून और खराब कार्यान्वयन का अभ्यस्त है. यहां यह सब एक प्रणाली बन चुका है. विदेशी निवेशक इस सबमें विश्वास नहीं करते. वे गारंटी चाहते हैं. इसके अलावा यहां किसी भी चीज में क़ानून की कोई स्पष्टता नहीं है. मुझे नहीं मालूम कि ऐसा करने के लिए सरकार को कौन रोक रहा है. लेकिन, यह तय है कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं, उसे वित्त मंत्री नहीं समझ रहे हैं या यह सब क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं हैं. रिजर्व बैंक के गवर्नर निश्चित तौर पर सरकार से अलग विचार रखते हैं. जितनी जल्दी घरेलू मोर्चे पर चीजों को ठीक कर लिया जाए, उतना ही बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुख्यात डाकू मुस्तकीम कैसे मारा गया-2

देखने दो सबको, शेर मारा जा रहा है

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह कर ना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

इमामुद्दीन को लेकर मुस्तकीम सुबह पांच बजे अकबरपुर से रूरा आया, मोटर साइकिल से. यहां उसने मोटर साइकिल छोड़ दी तथा बस से डेरापुर पहुंचा. डेरापुर से उसने फिर बस पकड़ी, जिससे वह गलुआपुर उतरा. वहां उतर कर उसने मेवालाल के यहां से पान बंधवाया तथा स्कूल के नल से हाथ-मुंह धोया. गलुआपुर से दो फर्लांग की दूरी पर दस्तमपुर है, जहां से वह खडंजे के रास्ते चला. उन दोनों के पास सामान के नाम पर एक झोला था, जिसे मुस्तकीम लिए हुए था. सुबह के आठ बजे थे. झोला उसने इमामुद्दीन को दिया तथा स्वयं शौच के लिए चला गया. फारिग होकर मुस्तकीम फिर दस्तमपुर गांव की ओर बढ़ा. गांव से पहले महुए का एक पेड़ है, जहां से एक पगडंडी मुसलमानों के घर की तरफ़ जाती है, जो मस्जिद के पास जाकर समाप्त होती है. मुस्तकीम के भाई मकबूल ने इसी मस्जिद के हाते में एक झोंपड़ी डाल रखी है. इमामुद्दीन को मुस्तकीम इसलिए ला रहा था कि वह उसे मकबूल का घर दिखा दे.

जब मुस्तकीम महुए के पेड़ से पगडंडी की तरफ़ बढ़ा, तो उसे सामने के मुख्य रास्ते से साइकिल पर एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर व एक सिपाही आते दिखाई दिए. उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उससे सौ गज पीछे आते इमामुद्दीन ने झिझक कर सड़क छोड़ दी. जब इमामुद्दीन झिझक कर रास्ते से कुछ हटा, तो आदत के मुताबिक सब-इंस्पेक्टर हरिराम पाल ने टोका, कहां से आ रहे हो? झोले में क्या है? जवाब मुस्तकीम ने दिया, हम लोग दस्तमपुर जा रहे हैं. इस पर श्री पाल ने गाली दी तथा तलाशी देने के लिए कहा. झोला इमामुद्दीन के हाथ में था. वह झोले से कपड़े निकाल रहा था कि सिपाही को रिवाल्वर दिखाई दे गई. उसने झपट कर झोला छीनना चाहा कि मुस्तकीम आ गया तथा उसमें व हरिराम पाल में कुश्ती शुरू हो गई. इधर सिपाही ने इमामुद्दीन को पकड़ लिया. मुस्तकीम ने हरिराम को बहुत मारा तथा बाद में बंदूक से भी उसकी पिटाई की. ज़मीन पर लगकर बंदूक का कुंदा टूट गया. सब-इंस्पेक्टर हरिराम पाल चीख-चीखकर गांव वालों को मदद के लिए पुकार रहे थे, पर गांव वाले दूर से ही तमाशा देखते रहे. तभी पास में ही शौच कर रहा दुबला-पतला गंगा चरण भागकर आया तथा मुस्तकीम से भिड़ गया. इसी समय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के शौच के लिए मैदान जा रहे थे. उन्हीं में गंगा चरण का लड़का रामपाल भी था. सभी दौड़कर आए और उन्होंने मुस्तकीम को बांध लिया. इसके बाद गांव वालों तथा सब-इंस्पेक्टर हरिराम पाल व सिपाही राजेंद्र सिंह सेंगर ने दोनों की जमकर पिटाई की. इसमें इमामुद्दीन का पैर टूट गया. जब इमामुद्दीन से बार-बार पूछने पर भी पता नहीं चला कि ये लोग कौन हैं, तो उसकी फिर पिटाई शुरू हुई. पर मुस्तकीम ने दारोगा को बुलाया तथा कहा, तुम असलियत जानना चाहते हो? मैं बाबा मुस्तकीम हूं. इतना सुनते ही गांव वाले और दारोगा सन्न रह गए. यह ख़बर आग की तरह चारों तरफ़ फैली तथा आसपास के गांव वाले इकट्ठे होने लगे. लेकिन गांव के जो लोग देखने आए, उन्हें दारोगा ने मां-बहन की गाली देकर भगा दिया. इसी बीच उन्होंने गांव के एक आदमी को डेरापुर थाने भेजा. थाने वालों ने चार सिपाही भेज दिए. हालांकि, थानाध्यक्ष ने इसे मज़ाक ही समझा.

अब मुस्तकीम पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में था और उसने समझ लिया था कि अब उसका अंत निकट आ गया है. लेकिन, अब भी वह दहाड़ रहा था. उसने दारोगा से कहा कि मेरे साथ जो लड़का है, यह निर्दोष है, इसे मत मारिए. यह बाल-बच्चों वाला है, इसे मैं रास्ता दिखाने के लिए लाया हूं. उसने दारोगा को उसके बच्चों की कसमें दिलाईं. दारोगा हरिराम पाल ने कसम खाकर कहा कि वह न उस लड़के इमामुद्दीन को मारेगा और न मुस्तकीम को. मुस्तकीम ने बार-बार दोहराया कि उसे तो मार ही दिया जाएगा, पर लड़के को न मारा जाए. इसके बाद उसने दारोगा से कहा कि उसके पास रुपये हैं, जिन्हें वह ग़रीबों में बांटने के लिए रखे हुए था. उसने दारोगा से कहा कि इन्हें वह ग़रीबों में बांट दे. दारोगा ने मुस्तकीम की तलाशी ली, तो सौ-सौ के नोटों का क़रीब छह इंच मोटा बंडल मिला. गांव वालों के अंदाज़ से एक लाख से ज़्यादा रुपये थे. मुस्तकीम ने कहा कि अस्सी हज़ार हैं. उसके पास से चार अंगूठियां, एक घड़ी व एक गले की जंजीर भी निकली. इस सबको दारोगा ने रख लिया. सिपाही ने जब मुस्तकीम को गाली दी, तो उसने डपट कर कहा, गाली मत दो, जबान अपनी अंदर रखो और दारोगा से कहा कि असल खानदान के तुम भी हो, मैं भी हूं, मुझे मार दो, पर इसे मत मारो.

जब दारोगा गांव वालों को बताने लगा कि मुस्तकीम उसे मार डाल रहा था, तो मुस्तकीम ने दारोगा से कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता, तो पहले ही मार देता. मेरे पास ऑटोमेटिक रिवाल्वर थी. मैंने आज तक गड़रियों को नहीं मारा, पता लगा लो. वह बार-बार अपना ताबीज चूम रहा था तथा कह रहा था, या अल्लाह! मुझसे क्या खता हो गई? मेरा वक्त आ गया, इसीलिए मैं यहां पकड़ा गया. जब दारोगा व सिपाही ने मुस्तकीम को वहीं मारना चाहा और इस इरादे से गांव वालों को भगाने लगे, तो मुस्तकीम ने कहा, देखने दो सबको, शेर मारा जा रहा है. मैंने आज तक ग़रीबों को नहीं सताया, बहू-बेटियों की इज्जत की है और जब भी लूटा है, अमीरों को लूटा है. लेकिन, उसी जगह मारने की दारोगा की कोशिश गांव वालों ने असफल कर दी. इधर सिपाही सेंगर घबरा रहा था कि और पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई. ■

जब दारोगा गांव वालों को बताने लगा कि मुस्तकीम उसे मार डाल रहा था, तो मुस्तकीम ने दारोगा से कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता, तो पहले ही मार देता. मेरे पास ऑटोमेटिक रिवाल्वर थी. मैंने आज तक गड़रियों को नहीं मारा, पता लगा लो. वह बार-बार अपना ताबीज चूम रहा था तथा कह रहा था, या अल्लाह! मुझसे क्या खता हो गई? मेरा वक्त आ गया, इसीलिए मैं यहां पकड़ा गया. जब दारोगा व सिपाही ने मुस्तकीम को वहीं मारना चाहा और इस इरादे से गांव वालों को भगाने लगे, तो मुस्तकीम ने कहा, देखने दो सबको, शेर मारा जा रहा है. मैंने आज तक ग़रीबों को नहीं सताया, बहू-बेटियों की इज्जत की है और जब भी लूटा है, अमीरों को लूटा है. लेकिन, उसी जगह मारने की दारोगा की कोशिश गांव वालों ने असफल कर दी.

क्रमशः

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री वाली मानसिकता से बाहर आइए

“भारत के सामने हमेशा चुनौती रही है कि हमने कमीशन के चक्कर में, खासकर राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक तंत्र ने हमेशा बाहर से सामान खरीदा और उसमें जमकर कमीशन खाया. पहले सेना एक पवित्र गाय की तरह देखी जाती थी, लेकिन अब सेना के भीतर भ्रष्टाचार की ख़बरें बहुत ज़्यादा बाहर आनी शुरू हो गई हैं. पिछले दस सालों से ऐसा हो रहा है, तब हमें पता चल रहा कि सेना में किस स्तर तक घूसखोरी है और सेना की ज़िम्मेदारी लेने वाले लोग ही सेना को खोखला करने में लगे हुए हैं. इसलिए आवश्यक यह है कि श्री मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री की मानसिकता से ऊपर उठें और देश के रक्षा मंत्री की तरह संयत व्यवहार करें, देश की सेनाओं को मजबूत करें, देश के सैनिकों में उत्साह भरें और अफसरों की कमी की वजह से जिस सेना को कमांड करने वाली टीम न हो, उस टीम को कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में सोचें.”

देश में सरकार चलाने वाले नेता अभी तक देश चलाने के मूड में नहीं आ पाए हैं. इस सरकार में तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं. एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह हैं और तीसरे मनोहर पर्रिकर हैं, जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं. यह अलग बात है कि गोवा एक बड़ा राज्य नहीं है और वहां का काम संभालते-संभालते उन्हें देश के रक्षा मंत्री का काम उनके साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी शासन चलाने की कला में मुख्यमंत्री के मनोविज्ञान से धीरे-धीरे उबर रहे हैं. मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश हथेलियों जैसा होता है, जिसमें 30, 40, 50, 60, 70, 80 ज़िले होते हैं, छोटा दायरा होता है. तीन करोड़, छह करोड़, सात करोड़, आठ करोड़ जैसी आबादी होती है और ज़्यादातर लोगों को वे नाम से जानते हैं तथा प्रदेश का शासन आसानी से चला लेते हैं. किसी भी घटित-अघटित स्थिति में वे मौक़े पर भी पहुंच सकते हैं. पर जब सवाल देश का हो, तो 125 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 29 राज्य प्रधानमंत्री को मिलते हैं और हालात ऐसे होते हैं कि वह चाहे, तो भी हर जगह नहीं जा सकता. इसके लिए उसे किसी भी तरह की शासन प्रणाली विकसित करनी होती है. भारत जैसे देश में 65 सालों के अनुभव के बाद एक शासन प्रणाली का विकास हुआ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शासन प्रणाली के चक्र को बदला है. उन्होंने मंत्रिमंडल अवश्य बनाया और मंत्रियों को राजनीतिक ज़िम्मेदारी भी दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि मंत्रालयों के सचिव उनसे सीधे संपर्क रखें और उन्हें सीधे रिपोर्ट दें. उन्हें निर्देश भी सीधे ही मिलेंगे, यह इसका अनकहा हिस्सा है. नतीजे के तौर पर इस समय देश में राजनीतिक ज़िम्मेदारी नहीं है, नौकरशाही वाली ज़िम्मेदारी है. राजनीतिक ज़िम्मेदारी का और नौकरशाही की ज़िम्मेदारी का सबसे बड़ा फ़र्क़ यह होता है कि किसी भी स्थिति में, जिसमें लोगों का नुक़सान हो, लोगों को दुःख पहुंचे या प्रशासनिक असफलता सामने आए, तब मंत्री अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेकर त्याग-पत्र दे देता है. लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था. लेकिन, जब ज़िम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स की हो, तो सिवाय इसके कि उस बड़े ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह, जो सचिव स्तर पर होता है, का तबादला कर दिया जाए. और कोई सजा उसे नहीं दी जा सकती. सचिव की ज़िम्मेदारी भी तय नहीं है, जबकि राजनेता की ज़िम्मेदारी परंपरागत और अलिखित रूप से तय होती है. इसलिए सारे देश में शासन चलाने वाले नौकरशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पालन कर दिया या क़दम आगे बढ़ाया और कहीं कोई ऊंच-नीच हो गई, तो उनके ख़िलाफ़ जांच बैठ सकती है और उनकी पदोन्नति पर इसका असर पड़ सकता है. इसलिए वे कोई भी फ़ैसला नहीं ले रहे हैं और इस फ़ैसला न लेने की कला का वे सीना तान कर समर्थन भी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की हवा निकालने या उस अभियान की हत्या करने का ज़िम्मा अगर किसी के ऊपर जाता है, तो देश के नौकरशाहों पर जाता है. और, यह एक उदाहरण है कि कैसे नौकरशाही एक अच्छी योजना को लागू नहीं करती.

दूसरा उदाहरण रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का है. रक्षा मंत्री आजकल जब बोलते हैं, तो सिवाय हंसी उड़ाने के कुछ नहीं बोलते. पिछले रक्षा मंत्री चाहे वे सफल रहे हों या असफल, उन्होंने राजनीतिक शब्दावली का कभी प्रयोग नहीं किया और मीडिया के साथ उनका इंट्रेक्शन कम से कम होता था. सेनाएं अपना काम करती थीं. रक्षा मंत्री उनका जवाब या किसी भी आरोप का जवाब, चाहे वे अंदर से लगाए गए हों या बाहर से, नहीं देता था. क्योंकि, अपेक्षा की जाती है कि रक्षा मंत्री का काम देश को बाहरी दुश्मनों से बचाना है और यह बचाव प्रेस के ज़रिये भाषण देकर नहीं होता है. इसके लिए सेनाओं को मजबूत करना होता है. रक्षा मंत्री शेख चिल्ली की तरह बयान दाग रहे हैं और वह अभी भी एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री की मानसिकता से नहीं उबर पाए हैं. उन्हें लगता है कि जिस तरह गोवा में उनकी तारीफ़ होती थी और उस तारीफ़ का कारण उनका हाफ पैंट पहन कर सब्जी खरीदना होता था या हाफ पैंट पहन कर गोवा में कहीं खड़े होकर कॉफी पीना होता था, वैसी तारीफ़ उन्हें यहां भी मिलेगी. लेकिन, अगर वह यही सारे काम दिल्ली में करना चाहें या उस मानसिकता की वजह से दिल्ली में तारीफ़ पाना चाहें, तो यह असंभव है, क्योंकि दिल्ली या देश को एक ऐसा रक्षा मंत्री चाहिए, जो अपनी सेनाओं को इतना मजबूत करे कि दुश्मन उसकी खुफिया जानकारी पाते ही परेशान हो जाए. दुर्भाग्य की बात यह है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर देश की सेनाओं को बदहाली से नहीं उबार पा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शासन प्रणाली के चक्र को बदला है. उन्होंने मंत्रिमंडल अवश्य बनाया और मंत्रियों को राजनीतिक ज़िम्मेदारी भी दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि मंत्रालयों के सचिव उनसे सीधे संपर्क रखें और उन्हें सीधे रिपोर्ट दें. उन्हें निर्देश भी सीधे ही मिलेंगे, यह इसका अनकहा हिस्सा है. नतीजे के तौर पर इस समय देश में राजनीतिक ज़िम्मेदारी नहीं है, नौकरशाही वाली ज़िम्मेदारी है.

वह सिर्फ़ यह कहते घूम रहे हैं कि हमने यूपीए की डील रद्द कर दी और हम 36 राफेल विमान खरीद रहे हैं. ऐसे में, सवाल यह उठता है कि जिस विमान को दुनिया भर ने ठुकरा दिया हो और जो कंपनी बंद हो गई हो, उस कंपनी को 36 विमानों का ऑर्डर देकर आपने दोबारा ज़िंदा कर दिया. लेकिन, आपने उस कंपनी के ऊपर यह दबाव नहीं डाला कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और विमानों का निर्माण हिंदुस्तान में करे. उसी तरह पाकिस्तान को लगभग तीन बार मनोहर पर्रिकर धमकी दे चुके हैं और वह धमकी ऐसी कि जिसे सुनकर सेना के अफसर भी हंस देते हैं. क्या रक्षा मंत्री को यह पता है कि हमारे पास कितने दिनों तक लड़ने का गोला-बारूद है? क्या रक्षा मंत्री को यह पता है कि जो जानकारियां उनके पास नहीं हैं, वे जानकारियां हमारे दुश्मनों के पास हैं? और, वे दुश्मन भी उनके बयान को सुनकर हंस लेते होंगे. जिस सेना की जिस कमज़ोरी की बात क्लासीफाइड फाइल्स में नहीं है, वह सारी जानकारी ख़तरनाक है और वह हमारे दुश्मनों के पास है. पर रक्षा मंत्री को अपना और देश का मज़ाक उड़वाने से कोई गुरेज नहीं. होता यह कि वह सेना को मजबूत करने की बात करते. जिस टेक्नोलॉजी को सेना पसंद करती है, उसे हिंदुस्तान में लाकर यहां इंडियनाइज वेपन या भारतीय शोध के ऊपर आधारित हथियार बनवाते और अपनी सेना को दुनिया के मुक़ाबले खड़ा करने की बात करते, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया.

भारत के सामने हमेशा चुनौती रही है कि हमने कमीशन के चक्कर में, खासकर राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक तंत्र ने हमेशा बाहर से सामान खरीदा और उसमें जमकर कमीशन खाया. पहले सेना एक पवित्र गाय की तरह देखी जाती थी, लेकिन अब सेना के भीतर भ्रष्टाचार की ख़बरें बहुत ज़्यादा बाहर आनी शुरू हो गई हैं. पिछले दस सालों से ऐसा हो रहा है, तब हमें पता चल रहा कि सेना में किस स्तर तक घूसखोरी है और सेना की ज़िम्मेदारी लेने वाले लोग ही सेना को खोखला करने में लगे हुए हैं. इसलिए आवश्यक यह है कि श्री मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री की मानसिकता से ऊपर उठें और देश के रक्षा मंत्री की तरह संयत व्यवहार करें, देश की सेनाओं को मजबूत करें, देश के सैनिकों में उत्साह भरें और अफसरों की कमी की वजह से जिस सेना को कमांड करने वाली टीम न हो, उस टीम को कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में सोचें. मुझे लिखने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री की मानसिकता से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अभी उसी मानसिकता में कैद हैं, जहां पर धमकियां देना बहुत बड़ी वीरता का लक्षण माना जाता है.

मैंने भारत के कई प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की. मैंने पाया कि पहले के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं मुख्यमंत्रियों को लेते थे, जिन्हें लेना अति आवश्यक हो जाता था. अन्यथा वे मुख्यमंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेते थे. शायद इसका सीधा कारण यही होगा कि मुख्यमंत्री राज्य की मानसिकता से देश की मानसिकता में ढलने में काफी वक्त ले लेते हैं. उनका एक तरह का मनोविज्ञान हो जाता है, एक तरह की समझ हो जाती है. देवेगौड़ा जी और वीपी सिंह को छोड़ दें, तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जो कभी मुख्यमंत्री रहा हो. तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. नरेंद्र मोदी जी के सामने यह अवसर है कि जिस जनता ने उन्हें विशाल बहुमत की भेंट दी, उस जनता की भावनाओं का न केवल वह ख्याल रखें, बल्कि उन मुद्दों के ऊपर अपनी उंगली रखें, जो मुद्दे सचमुच मुद्दे हैं. वे मुद्दे, जिनका रिश्ता पेट से हो, रोजी-रोटी से हो, भ्रष्टाचार से हो और विकास से हो, न कि भावनात्मक मुद्दे. हालांकि यह मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा ढांचा नरेंद्र मोदी को ताकत भी दे सकता है और उन्हें कमज़ोर भी कर सकता है. मुझे लगता है कि भारत के रक्षा मंत्री को राजनीतिक तौर पर थोड़ा और परिपक्व होना चाहिए और उस परिपक्वता को बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मदद करनी चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

भारत के लिए नई अंग्रेजी वर्णमाला

क्यू-क्वांटिटेटिव इजिंग (केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति). अगर इसे उलट दिया जाए, तो विनिमय दर प्रभावित होगी. इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, यह भूमंडलीकरण की वजह से है. अगर आप भूमंडलीकरण से किनाराकशी अख्तियार करेंगे, तो आप उत्तर कोरिया की तरह अलग-थलग पड़ जाएंगे.

आर-यमन और नेपाल में कारगर रेस्क्यू या बचाव कार्य.

एस-स्वच्छ भारत न कि साक्षी महाराज.

मेघनाद देसाई

ए-एशिया की बारी है. चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया और सिंगापुर का दौरा. इस पर जवाहर लाल नेहरू (जो इंडोनेशिया के बैनडंग में अफ्रीकी एशियाई कांफ्रेंस के लिए गए थे) के बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. अब का एशिया पहले से अधिक शक्तिशाली और अलग है.

बी-बांग्लादेश के साथ समझौता. न केवल सीमा समझौता बिल सर्वसम्मति से पास हो गया (जिसके लिए सुषमा स्वराज के संसदीय कौशल की प्रशंसा की जानी चाहिए), बल्कि यह सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है.

सी-यूपीए शासन के विपरीत पूरे साल के दौरान करप्शन या घोटाले का कोई मामला सामने नहीं आया. यह सोच ही अद्भुत है कि मौजूदा समय न केवल यूपीए-2 से, बल्कि 1947 के बाद से अब तक के समय से कितना अलग है. आपको याद होगा कि फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने नेहरू के शासनकाल में भ्रष्टाचार को उजागर किया था.

डी-डेफिसिट या घाटे को नियंत्रण में रखना. वह भी पी चिदंबरम के अनिश्चित अंतरिम बजट की विरासत के बाद. भाजपा ने यूपीए-2 की कारगुजारी के लिए उसकी आलोचना नहीं की. अरुण जेटली ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और बजट घाटे को नियंत्रण में रखा.

ई-ईंधन सब्सिडी को एफीसिएंट या सुचारू तरीके से ख़त्म करना. सरकार ने पेट्रोल की क़ीमतों में आई गिरावट को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया. पेट्रोल उपभोक्ता न तो पुनर्वितरण की बुनियाद पर और न पर्यावरण की बुनियाद पर सब्सिडी के हक़दार हैं.

एफ-बीमा, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में एफडीआई के लिए रास्ता साफ़ करना. आपसी मतभेद और ग़लतफहमी के बावजूद राजनीतिक दलों में बेहतर समझ पैदा हुई है कि कैसे देश की भलाई के लिए एफडीआई का इस्तेमाल किया जाए.

जी-जीएसटी बिल, जो एक दशक के विचार मंथन के बाद संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हो जाना चाहिए था. जी से जीडीपी में वृद्धि भी है, जो यूपीए-2 के पिछले तीन वर्षों से अधिक है. यह जी-20 के देशों में सबसे अधिक जीडीपी में से एक है.

एच-हरियाणा में जीत.

आई-इंफ्लेशन या महंगाई में कमी लाना.

जे-जन धन योजना.

के-जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराना और गठबंधन सरकार चलाना.

एल-पेट्रोल की क़ीमतों में कमी के लिए गुडलक या अच्छी किस्मत.

एम-मेक इन इंडिया. हालांकि, इस पर अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन इसमें अवधारणा यह है कि घरेलू और विदेशी निर्माता भारत की क्षमता का इस्तेमाल कर सकें.

एन-नीति आयोग ने बेअसर हो चुके योजना आयोग का स्थान लिया. यह भी अपने शुरुआती दौर में है, जिसे अपनी उपयोगिता साबित करनी है.

ओ-अप्रवासी भारतीय (ओवरसीज इंडियन), जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क में बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया. ऐसा ही दृश्य हमने कनाडा में भी देखा. जब प्रधानमंत्री ब्रिटेन आएंगे, तो हम इससे कई गुना उत्साह देखेंगे.

पी-पार्लियामेंट या संसद, जिसने बहुत सारे स्थगनों के बावजूद पिछले पांच वर्षों की तुलना में बेहतर तरीके से काम किया.

क्यू-क्वांटिटेटिव इजिंग (केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति). अगर इसे उलट दिया जाए, तो विनिमय दर प्रभावित होगी. इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, यह भूमंडलीकरण की वजह से है. अगर आप भूमंडलीकरण से किनाराकशी अख्तियार करेंगे, तो आप उत्तर कोरिया की तरह अलग-थलग पड़ जाएंगे.

आर-यमन और नेपाल में कारगर रेस्क्यू या बचाव कार्य.

एस-स्वच्छ भारत न कि साक्षी महाराज. हमें अधिक से अधिक स्वच्छता और कम से कम साक्षी महाराज की ज़रूरत है.

टी-एक ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन, जो (अपने से पहले के प्रधानमंत्री, जो बेशक ईमानदार थे और जो बेईमान सहकर्मियों में घिर गए थे, के विपरीत) देश के लोगों से ट्वीटर, फेसबुक और मन की बात के माध्यम से बात (टॉक) कर सकता है. और जब आवश्यकता होती है, तो संसद में भी अपनी बात रखता है. टी से ट्रेन सुविधाओं में सुधार भी होता है, जिसका ज़िक्र सुरेश प्रभु ने रेल बजट में किया था.

यू- एक बिल्कुल अनोखी (णर्पीीिरश्र) बात कि किसी सरकारी सूत्र द्वारा कोई खुलासा या गॉसिप बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से टीवी चैनलों को चर्चा के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा है.

वी-विकास, जैसे सबका साथ-सबका विकास.

डब्ल्यू- मौसम (थशरींहशी), जिसकी वजह से अविश्वसनीय क्षति हो सकती है, जैसे बेमौसम बरसात, बहुत अधिक गर्मी, मॉनसून में देरी, जो बेहतरीन योजनाओं को भी पटरी से उतार सकती है. 60 से अधिक वर्षों के बाद भी (जिसमें से अधिकांश समय कांग्रेस के शासन में गुज़रा है) भारत को मॉनसून से डर लगना ही चाहिए.

एक्स-मतदाताओं की ताक़त, जो जानते हैं कि किसी भी पार्टी को ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए, आम चुनाव और राज्यों के चुनाव में अलग-अलग पार्टी को वोट देकर. यह मतदाता ही है, जो सबको आश्चर्यचकित कर देता है.

वाई-यंग इंडिया, जो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, बेहतर काम की उम्मीद लगाए हुए है.

जेड-भ्रष्टाचार के लिए जीरो सहिष्णुता. ■

feedback@chauthiduniya.com

डिहाइड्रेशन चाहे हल्का–फुल्का हो या गंभीर, हर स्टेज में एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है. थोड़ी–सी सतर्कता डिहाइड्रेशन की बड़ी परेशानी से बचा सकता है. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे गर्मी में बाहर से आकर तुरंत पानी न पीएं बल्कि थोड़ी देर रुककर नॉर्मल पानी पीना चाहिए बहुत ठंडा नहीं. सुबह–सुबह उठकर पानी पीना भी बहुत फायदेमंद रहता है. धूप में अधिक निकलने से परहेज करना चाहिए. अगर धूप में निकलना बहुत ही आवश्यक हो तो भरपेट पानी पीकर ही निकलना चाहिए. इससे धूप की तीव्रता का असर कम होता है और डिहाइड्रेशन की आशंका कम हो जाती.

गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचें

मोनिशा भटनागर

गर्मियों में जब तापमान अपने चरम पर होता है तब सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या होती है, शरीर में पानी की कमी हो जाना. पानी की कमी से कई समस्याएं हो जाती हैं, जैसे शरीर में चर्बी बढ़ना, पाचन क्रिया कमजोर होना, अंगों का ठीक प्रकार से काम न कर पाना, शरीर में विषाक्तता का बढ़ना, जोड़ों और पेशियों में दर्द होना लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा होने वाली समस्या है डिहाइड्रेशन. शरीर से जब अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को डिहाइड्रेशन कहा जाता है. डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से अवशिष्ट पदार्थों का विष शरीर में फैल जाना. अधिक दस्त आना, उल्टी होना, अधिक पसीना बहना, फूड पॉयजनिंग का असर, तेज बुखार होना, लू लगना, अधिक शारीरिक श्रम, धूप में अधिक देर चलना आदि के कारणों से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है. डिहाइड्रेशन के तीन प्रकार होते हैं, जिन्हें माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन तथा सीवियर डिहाइड्रेशन के नामों से जाना जाता है. माइल्ड डिहाइड्रेशन की स्थिति में रोगी के शरीर से लगभग तीन प्रतिशत पानी की कमी हो जाती है. रोगी को इस स्थिति में प्यास अधिक लगती है तथा अधिक कमजोरी महसूस होने लगती है. रोगी के हाथ–पैर झुनझुनाने लगते हैं तथा उसे नींद नहीं आती. यह स्थिति अधिक खतरनाक नहीं होती. मॉडरेट डिहाइड्रेशन की स्थिति में रोगी के शरीर से लगभग दस प्रतिशत पानी की कमी हो जाती है. रोगी का मुंह सूखने लगता है तथा उसमें लगातार कमजोरी बढ़ने लगती है. पल्स रेट अधिक हो जाती है तथा रोगी को लगातार चक्कर आने लगते हैं. यह स्थिति रोगी के लिये काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है. सीवियर डिहाइड्रेशन की स्थिति में रोगी के शरीर से लगभग पंद्रह प्रतिशत तक पानी की कमी हो जाती है. रोगी का ब्लडप्रेशर कम हो जाता है तथा पल्स बहुत ही कमजोर पड़ जाती है. इस स्थिति में रोगी बेहोश भी हो सकता है. इसका असर उसके दिमाग तथा किडनी पर पड़ता है.

कई लोगों को यह नहीं पता होता कि एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए या फिर लगातार पानी नहीं पीते रहने से क्या नुकसान हो सकते है? कई बीमारियां जैसे बुखार, उल्टी, ब्लैडर इंफेक्शन, पथरी इत्यादि होने पर शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है. ऐसे में पानी की जरूरत शरीर को हर समय रहती है फिर चाहे रोगी को प्यास लगे या न लगे. कई बार लोग सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं जबकि प्यास न लगने पर भी दिन में आठ गिलास पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग पानी के बजाय सॉफ्ट ड्रिंक, बीयर, कॉफी, सोडा इत्यादि पीते हैं लेकिन ये चीजें तरल पदार्थों में शमिल होने के बावजूद इनके पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. डिहाइड्रेशन से व्यक्ति के सोचने–विचारने, चीजों को संतुलित करने रक्त संचार इत्यादि में कमी आ जाती है. शराब पीने वाले लोगों, जिनको अकसर हैंगओवर हो जाता है या जो लोग बिना पर्याप्त मात्रा में पानी पिए प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, को डिहाइड्रेशन की समस्या होने की आशंका ज्यादा होती है. ऐसे लोगों के लिए पानी की कमी और भी अधिक नुकसानदायक हो सकती है.

विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मियों में अपने भोजन को भी पानी का अच्छा स्रोत बनाना अच्छा उपाय है. गर्मियों में अधिक मात्रा में पानी तो पीना ही चाहिए लेकिन साथ ही इस बात पर ध्यान दें कि ठोस खाने से भी पानी मिलता है जो शरीर में पानी के स्तर को संतुलित रखता है. गर्मियों में भोजन के रूप में सलाद खाया जा सकता है.

डिहाइड्रेशन चाहे हल्का–फुल्का हो या गंभीर, हर स्टेज में एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है. थोड़ी–सी सतर्कता डिहाइड्रेशन की बड़ी परेशानी से बचा सकता है. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे गर्मी में बाहर से आकर तुरंत पानी न पीएं बल्कि थोड़ी देर रुककर नॉर्मल पानी पीना चाहिए बहुत ठंडा नहीं. सुबह–सुबह उठकर पानी पीना भी बहुत फायदेमंद रहता है. धूप में अधिक निकलने से परहेज करना चाहिए. अगर धूप में निकलना बहुत ही आवश्यक हो तो भरपेट पानी पीकर ही निकलना चाहिए. इससे धूप की तीव्रता का असर कम होता है और डिहाइड्रेशन की आशंका कम हो जाती. विशेषज्ञ कहते हैं गर्मियों में अपने भोजन को भी पानी का अच्छा स्रोत बनाना अच्छा उपाय है. गर्मियों में अधिक मात्रा में पानी तो पीना ही चाहिए लेकिन साथ ही इस बात पर ध्यान दें कि ठोस खाने से भी पानी मिलता है जो शरीर में पानी के स्तर को संतुलित रखता है. गर्मियों में भोजन के रूप में सलाद खाया जा सकता है. सलाद में 95 प्रतिशत मात्रा में पानी होता है. इसमें बेहतर मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद होता है, जिसमें वसा जरा सा भी नहीं होती और क्लोरीन भी बिल्कुल कम होता है. इसमें पोषक तत्व जैसे ओमेगा–3, उच्च फाइबर, लौह और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होते हैं. सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर अदि खाए जाते हैं. इसके अलावा सब्जियों में ब्रोकली में पोषाहार के साथ 89 प्रतिशत मात्रा में पानी होता है. इसके गैर–दाहक लक्षण भी शरीर को गर्मी से लड़ने में सक्षम बनाते है. गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक नींबू पानी और आम पन्ना का सेवन करना चाहिये तथा गरिष्ट भोजन का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए. गर्मी के मौसम में दूध या दूध से बने पदार्थ दही, लस्सी आदि का सेवन अधिकतर करते रहना चाहिये. पानी के पर्याप्त मात्रा में सेवन से कई बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है.

डिहाइड्रेशन होने के आम लक्षण है जी मिचलाना, उल्टियां होना, जुबान का सूखना, सांस सही से ना ले पाना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी व चक्कर आना आदि. डिहाइड्रेशन के रोगी को पहचानने के लिए पेट की त्वचा को चुटकी से दबा कर छोड़ें और उसे ध्यान से देखें. अगर वह धीरे–धीरे सामान्य अवस्था में लौटती है तो यह डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति में त्वचा को चुटकी मे दबा कर छोड़ने पर वह जल्द ही एकदम पहले जैसी हो जाती है. ऐसे में तुरंत पानी में थोड़ा सा नमक और शक्कर मिलाकर घोल बनाएं और पी लें.कच्चे दूध की लस्सी बनाकर पीने से भी डिहाइड्रेशन में लाभ होता है.छाछ में नमक डालकर पीने से भी इस समस्या से राहत मिलेगी. डिहाइड्रेशन होने पर नारियल का पानी पिएं. ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में घोलकर पीने से भी डिहाइड्रेशन की समस्या से निजात पाया जा सकता है. एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम आठ गिलास पानी पीना चाहिए जिससे शरीर में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों के विष को नष्ट किया जा सके.■

feedback@chauthiduniya.com

जंग में सब जायज है : एमी

अरुण तिवारी

एमी एलिजाबेथ थोर्प का जन्म 22 नवंबर 1910 को अमेरिका के मिनियापोलिस में हुआ था. उनके पिता जॉर्ज सी थोर्प अमेरिकी नौसेना में अधिकारी थे. उनकी मां मिनेसोटा राज्य के स्टेट सीनेटर की बेटी थीं. एक संभ्रांत परिवार में जन्म लेने के कारण एमी के लिए बचपन से ही कई बातें काफी आम थीं. जैसे अमेरिका के कुलीन वर्ग के लोगों और बड़े अधिकारियों का अक्सर उनके घर आना होता था. अमेरिका के कई अधिकारी उन्हें बचपन से ही जानते थे. एमी के भीतर अपनी किशोरावस्था से ही इस बात का फायदा उठाने की फितरत भी थी.

उनकी इस फितरत और इच्छा को देखते हुए जल्दी ही उनके माता पिता ने उन्हें सामाजिक कार्यों में लगा दिया जिससे कि वे लोगों के बीच मशहूर हो सकें. एमी ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया. लगभग 20 साल की एमी अपने से दोगुने बड़े उम्र के विदेशी राजनयिकों के साथ रूमानी संबंध रखने के लिए जानी जाने लगीं. अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक 20 साल की लड़की के कई विदेशी राजनयिकों के साथ रूमानी संबंध हैं.

1936 में वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश दूतावास में दूसरे नंबर के पद काबिज अर्थर पार्क के साथ एमी ने विवाह कर लिया. दोनों के विवाह की चर्चा न सिर्फ अमेरिका में हुई बल्कि अर्थर के ब्रिटेन में भी काफी मशहूर होने के कारण यह खबर ब्रिटेन में सुर्खियों में रही. लेकिन चार साल के भीतर ही एमी दो बार गर्भवती हुईं और अर्थर को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था. एमी स्वच्छंद खयालों की लड़की थीं. वे अर्थर से इस बात के लिए झगड़ा किया करती थीं कि अगर वे अगर गर्भवती हैं तो अर्थर को उनका ख्याल रखना चाहिए. अर्थर काम की मजबूरियों के कारण ज्यादा दिनों तक घर पर रुक नहीं पाते थे. दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गईं. हालांकि इस दौरान कई बार एमी ने कोशिश की कि वे भी अर्थर के काम में उनकी मदद कर सकें. जब स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था तो उस दौरान कई बार एमी ने अर्थर की मदद भी की थी. वे अर्थर के साथ यूरोप के कई देश गईं और वहां पर अधिकारियों को अपने मोहपाश में बांध कर कई खुफिया जानकारियां अर्थर को उपलब्ध करवाईं.

एमी के पति अर्थर ने 1945 में आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद एमी ने अपने सबसे करीबी रहे चार्ल्स से शादी कर ली. इसके बाद दोनों तब तक साथ रहे जब एमी की साल 1963 में गले के कैंसर की वजह से मौत हो गई.

विलियम स्टीफेंसन ने एमी की तारीफ की है. विलियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के खास आदमियों में थे और ब्रिटिश सिक्योरिटी कॉनफेडरेशन की कमान संभालते थे. वे लिखते हैं कि एमी की काबिलियत का बखूबी इस्तेमाल ब्रिटेन ने तब किया जब उन्हें एनिग्मा मशीन के बारे में जानकारी लेने का काम दिया गया था. यह काम उन्हें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने सौंपा था. एमी ने इस बात की खुफिया जानकारी दी थी कि आखिर कैसे एनिग्मा मशीन के जरिये धुरी राष्ट्र एक दूसरे को जानकारियां भेजते हैं. एनिग्मा मशीन के जरिये सूचनाओं का आदान–प्रदान पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों द्वारा किया जाता था.

जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो एमी पोलैंड से अमेरिका वापस लौट आईं. स्टीफेंसन ने उनके बारे में लिखा है कि एमी के रूमानी संबंध जर्मनी, इटली और जापानी अधिकारियों के साथ भी थे. इन अधिकारियों के जरिये उन्हें मित्र राष्ट्रों को ऐसी गुप्त सूचनाएं दीं जिनके आधार पर मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका पर हमला किया था.

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एमी ने अपने रूमानी संबंधों पर खुल कर चर्चा की थी. उन्होंने कहा कि मैंने खुफिया जानकारियां निकलवाने के लिए शारीरिक संबंध बनाए. यह एक आम महिला के लिए सम्माननीय तरीका नहीं हो सकता है. मैं जिन परिस्थितियों के साथ डील करती थी वैसी परिस्थितियों में कोई भी आम महिला पीछे हट जाएगी, क्योंकि उसे यह काम सम्मानीय नहीं लगता. लेकिन मैं ये काम इसलिए करती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि इससे मैं हजारों जिंदगियां बचा सकती हूं. और युद्ध कभी भी सम्माननीय तरीकों से नहीं जीते जाते. युद्ध जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ती है. कई बार गलत रास्ते भी अख्तियार करने पड़ते हैं क्योंकि आप वहां सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हजारों मासूस लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं.

एमी के पति अर्थर ने 1945 में आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद एमी ने अपने सबसे करीबी रहे चार्ल्स से शादी कर ली. इसके बाद दोनों तब तक साथ रहे जब एमी की साल 1963 में गले के कैंसर की वजह से मौत हो गई.

एमी की भले ही मौत हो गई हो लेकिन उनके कारनामों की वजह से उन्हें अमेरिका में अभी याद किया जाता है. उन्हें लोग याद करते हैं. न सिर्फ इसलिए कि वे एक खूबसूरत महिला थीं बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल न जाने कितनी जानें बचाने के लिए किया. एक आम समाज में यह माना जा सकता है कि एमी लक्ष्य पूरा करने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करती थीं लेकिन उनके उद्देश्यों पर शायद ही किसी को संदेह हो.■

feedback@chauthiduniya.com

रोहिंग्या मुसलमान

नफरत की राजनीति के शिकार हैं

रोहिंग्या के खिलाफ चल रहे सुनियोजित दंगों की वजह से विश्व में न केवल म्यांमार की छवि धूमिल हुई है, बल्कि इस देश के बड़े नेताओं की चुप्पी ने भी उनके अंतरराष्ट्रीय क़द को छोटा कर दिया है. मिसाल के तौर पर नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित आंग सांग सुकी ने इन घटनाओं को लेकर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. वहीं विपक्ष अपनी चुनावी रोटी सेंकने के लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बना कर दक्षिणपंथी बुद्धों को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना को हवा दे रहा है. बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने बर्मा सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों को जल्द से जल्द नागरिकता देने की मांग की है. साथ ही देश में चल रहे नरसंहार रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए भी कहा है.

शफीक आलम

मई 2012 में म्यांमार के राखाइन प्रान्त में एक बौद्ध महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद रोहिंग्या मुसलमानों और बहुसंख्यक स्थानीय राखाइन बौद्धों के बीच हिंसा भड़क उठी थी. देखते ही देखते इसने ऐसा भयावह रूप अख्तियार कर लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को यह कहना पड़ा कि म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान दुनिया के सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यकों में से एक हैं. 28 मई, 2012 की शाम को एक रखाइन महिला जब राम्ब्री शहर से अपने गांव लौट रही थी तो कुछ लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. इसका आरोप रखाइन बौद्धों ने रोहिंग्या मुसलमानों पर लगाया. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. 3 जून, 2012 को एक भीड़ ने तौन्गप नामी स्थान पर एक बस पर हमला कर दिया. उनको यह संदेह था कि बस में दुष्कर्म के आरोपी जा रहे हैं. इस हमले में 10 मुसलमान मारे गए, जिसके विरोध में मुसलमानों ने भी बौद्धों पर हमले किए और यहीं से इस देश में दंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अब तक जारी है.

इन दंगों में केवल राखाइन प्रान्त के रोहिंग्या मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले मुसलमान भी इसकी ज़द में हैं, लेकिन इन दंगों से जो सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं, वे रोहिंग्या मुसलमान हैं. वर्ष 2012 की अपनी रिपोर्ट में ह्यूमन राइट वाच (एचआरडब्लू) ने कहा था कि बर्मा के सुरक्षाकर्मी हिंसा को रोकने में न केवल बुरी तरह से नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ हिंसक अभियान भी छेड़ दिया. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को माना था. इसका नतीजा यह हुआ कि एक लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को उनके घरों से निकाल कर सरणार्थी कैम्पों में अमानवीय स्थिति में ज़िन्दगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया. इन कैम्पों की हालत इतनी खस्ता है कि लोग यहां से किसी तरह निकल जाना चाहते हैं. वे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ न केवल उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, बल्कि मौक़ा मिलने पर वहां पलायन करने की भी कोशिश कर रहे हैं. इस कोशिश में बहुतों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं और बहुत सारे समुद्र में नावों के ऊपर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कोई देश उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहां त्रासदी केवल यह नहीं है कि रोहिंग्या को कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी त्रासदी यह भी है कि वे अपने घरों से केवल कुछ दूरी पर कैम्पों में रह सकते हैं, लेकिन अपने घरों को नहीं लौट सकते.

हालांकि राखाइन प्रान्त में पहले भी रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्धों के बीच दंगे होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा दंगों के पीछे अगर किसी सोची-समझी साजिश को नकार दिया जाए, तब भी कम से कम यह ज़रूर कहा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर दंगों के लिए पहले से माहौल तैयार हो रहा था. ज़ाहिर है कि ऐसे दंगे रातोंरात नहीं होते. इसके लिए पहले से माहौल तैयार किया जाता है. इस सिलसिले में रखाइन बौद्धों में यह धारणा आम की जा रही थी कि वे अपने ही पूर्वजों के प्रान्त में अल्पसंख्यक बन जाएंगे और रोहिंग्या बहुसंख्यक बन जाएंगे. वर्ष 1982 में रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित करने के पीछे यही सोच थी. वर्ष 1982 में जनरल ने विन की सरकार ने बर्मा का नागरिकता कानून लागू किया था, जिसमें

रोहिंग्या को अप्रवासी की हैसियत देकर उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया था. नतीजा यह हुआ कि रोहिंग्या मुसलमान बहुत सारी नागरिक सेवाओं से वंचित हो गए. समय-समय पर सैनिक शासन उनक शोषण भी करती रही. कई अन्य समीक्षक यह मानते हैं कि इस देश में मुसलामनों और बौद्धों के बीच मौजूद वैमनस्य तालिबान द्वारा बामियान में बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने के बाद से शुरू हो गया था. अब सवाल यह उठता है कि ये रोहिंग्या कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या मौजूद संकट का कोई समाधान है?

यह माना जाता है कि रोहिंग्या बंगाल (मौजूदा बांग्लादेश) से अंग्रेजों के समय में और उनसे पहले भी यहां आकर आबाद होते रहे हैं. अंग्रेजों ने उन्हें मुख्यत: 18वीं और 19वीं सदी में खेती के लिए बसाया था. रोहिंग्या दो और मौकों पर यहां आकर आबाद हुए थे. पहले 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी के समय और दूसरे 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के समय, लेकिन वर्मा के पश्चिमी भाग में रहने वाले इस अल्पसंख्यक समुदाय के यहां बसने के समय को लेकर विवाद है. बर्मा की सरकार यह कहती है कि रोहिंग्या हाल में ही यहां आबाद हुए हैं. लिहाज़ा, उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ रोहिंग्या का कहना है कि वे यहां सैकड़ों वर्षों से आबाद हैं और यहीं के नागरिक हैं, जिन्हें सरकार प्रताड़ित कर रही है. ख्याल रहे कि बांग्लादेश में फ़िलहाल कई हज़ार रोहिंग्या पिछले 20 वर्षों से शरण लिए हुए हैं, लेकिन यहां भी त्रासदी यह है कि उन्हें सरकारी तौर पर शरणार्थी की हैसियत नहीं दी गई है. यहां के कैम्पों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है. अब रोहिंग्या की तरफ से यह खौफ ज़ाहिर किया जा रहा ही कि बांग्लादेश उन्हें बंगाल की खाड़ी के किसी टापू पर स्थानांतरण पर विचार कर रहा है. ज़ाहिर है, ऐसे में यह देश भी क्षेत्र के दूसरे देशों की तरह और अधिक लोगों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है. खासतौर पर उस वक़्त, जब बंगलादेश में आतंकवादी गतिविधियों में रोहिंग्या लोगों के भी शमिल होने का आरोप है.

बहरहाल, तीन साल बाद एक बार फिर रोहिंग्या त्रासदी पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं. इस बार हजारों रोहिंग्या मानव तस्करों की जाल में फंसकर इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरे दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के समुद्र में फंसे हुए हैं. उनमें से बहुतों की समुद्र के ऊपर ही मौत हो गई. फ़िलहाल अन्तराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया ने कई महीनों से नावों पर और जहाजों पर ज़िन्दगी गुजारने को मजबूर लोगों को शरण दे दी है, लेकिन वहां भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है. अवैध प्रवासियों और मानव तस्करी की समस्या से जूझ रहे पड़ोसी देश थाइलैंड मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के देशों का शिखर सम्मलेन बुलाने की मांग कर रहा है.

रोहिंग्या के खिलाफ चल रहे सुनियोजित दंगों की वजह से विश्व में न केवल म्यांमार की छवि धूमिल हुई है, बल्कि इस देश के बड़े नेताओं की चुप्पी ने भी उनके अंतरराष्ट्रीय क़द को छोटा कर दिया है. मिसाल के तौर पर नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित आंग सांग सुकी ने इन घटनाओं को लेकर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. वहीं विपक्ष अपनी चुनावी रोटी सेंकने के लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बना कर दक्षिणपंथी बुद्धों को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना को हवा दे रहा है. बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने बर्मा सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों को जल्द से जल्द नागरिकता देने की मांग की है. साथ ही देश में चल रहे नरसंहार रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के लिए भी कहा है. हालांकि म्यांमार किसी तरह के सुनियोजित नरसंहार से इंकार कर रहा है, लेकिन उस देश से जो ख़बरें आ रहीं हैं, उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता.

म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए यह ज़रूरी है कि देश में स्थिरता बनी रहे. अब अगर देश में ऐसे ही हालात रहे तो 2010 में देश में लोकतंत्र की बहाली की जो शुरुआत हुई है, उसको झटका लग सकता है और देश एक बार फिर निरंकुश सैनिक शासन के शिकंजे में आ सकता है. वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमानों की दयनीय हालत का कोई आतंकवादी संगठन फायदा उठा सकता है. इसलिए पूरी दुनिया को इस मानवीय त्रासदी से निपटने के लिए म्यांमार पर दबाव डालना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

घाना गैस स्टेशन विस्फोट, 200 मरे

पश्चिमी अफ़्रीकी देश घाना की राजधानी अक्रा में गैस स्टेशन में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 200 हो गई. अक्रा के नक्रुमाह सर्कल स्थित गोउल फिलिंग स्टेशन में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश के दौरान विस्फोट के बाद आग लग गई. घाना फायर सर्विस (जीएफएस) ने कहा कि स्टेशन के भूमिगत टैंकों में रखा ईंधन बाढ़ के दौरान बहने लगा और नजदीकी घर में आग लग गई, जिससे स्टेशन में विस्फोट हुआ. समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य अस्पताल में सबसे अधिक 37 शव रखे गए हैं, जहां घायलों का इलाज चल रहा है. विस्फोट की वजह का पता नहीं चल पाया है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई पीड़ितों ने भारी बारिश के कारण गैस स्टेशन में शरण ले रखी थी. शहर में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. आपातकालीन सेवा के कर्मचारी घटनास्थल पर शवों को निकालने का काम कर रहे हैं. आंतरिक मंत्री मार्क वोयोनगो ने घटना को राष्ट्रीय आपदा करार दिया. राष्ट्रपति जॉन द्रामी महामा ने तीन-दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया है.

बीमार हैं हेल्मुट कोल

जर्मन एकीकरण के सूत्रधार कहे जाने वाले पूर्व चांसलर हेल्मुट कोल को आंत की सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा गया है. जर्मन पत्रिका डेर श्पीगल के मुताबिक़ 85 वर्षीय कोल हाइडेलबर्ग के एक क्लीनिक में दाख़िल हैं. कोल 1982 से 1998 तक जर्मनी के चांसलर रहे और वह आधुनिक जर्मनी में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे. उनके कार्यकाल में ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था. कोल की तबियत के बारे में उनके कार्यालय और क्लीनिक की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन श्पीगल ने कोल के करीबी सूत्रों के हवाले से उनकी स्थिति को नाज़ुक बताया है. बुंटे मैगज़ीन के मुताबिक, आंत के ऑपरेशन के बाद कोल लंबे समय तक बेहोश रहे. मैगज़ीन ने बताया कि कोल ने मई में कूल्हे बदलवाए थे और इस महीने उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना था.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अगर मैं अपने वस्त्र दे दूंगा तो मुझे नग्न होना पड़ेगा. फिर उसने सोचा–मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है. साधु–संन्यासी भी बिना वस्त्र के रहते हैं. उसने अपनी धोती दे दी. बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया. निरंजन अपने घर की ओर चल पड़ा. वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था कि मैंने अपने आधे मन को जीत लिया. तभी निरंजन ने देखा कि दूसरी ओर से महाराज प्रसेनजित चले आ रहे हैं. निरंजन की बात सुनकर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी बात का क्या अर्थ है?

सद्गुरु प्रकाशमान सूर्य की भांति हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

अपनी अध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मनुष्य किस प्रकार शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो सकता है?

आध्यात्म के मार्ग में कोई भी व्यक्ति मात्र सुनकर या पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकता. कोई भी ज्ञान यदि वह व्यवहार में नहीं आता तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है. ज्ञान को व्यवहार में लाना कठिन है. इसके लिए आस्था और शक्ति का होना अनिवार्य है. सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण एवं कृपा याचना से इस मार्ग में भक्त का चलना संभव होता जाता है. इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए. मैं योगी बनूंगा, सिद्ध बनूंगा, भक्त बनूंगा, कुंडली जगाउंगा, मुक्ति प्राप्त करूंगा, बिना इन शब्दों का अर्थ जाने हुए इनमें फंसना मूर्खता होगी. आवश्यक यह है कि हम केवल ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखें और बाबा से निरंतर प्रार्थना करें कि वे अपना स्वरूप हमें प्रकट करें. साथ ही इस तत्व को भी हम समझें कि वास्तव में हम कर्ता नहीं हैं. प्रत्येक कार्य को करने में अपने कर्तापन का त्याग करना आवश्यक है. यह कर्तापन हमारे अहंभाव के कारण आता है और धीरे–धीरे जाता है. इसमें समय लगता है.

पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आचरण का महत्व क्या धर्मग्रंथ पढने से वास्तविक ज्ञान मिलता है?

क्या हम जो धर्मग्रंथ आदि पढते हैं, उसमें लिखी बातों पर अमल कर पाते हैं. अगर नहीं, तो वह मात्र बुद्धि–विलास है और जहां विलास है वहां ज्ञान कभी नहीं हो सकता. अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है.

आध्यत्मिक क्षमता सद्गुरुओं द्वारा प्रदत्त

करोड़ो प्रकार के विभिन्न प्राणी–जिनमें मानव सबसे उन्नत है, जीवन के अलग–अलग गलियारों में चलते रहते हैं– राजपथ पर पहुंचने के लिए इसका अर्थ यह है कि विभिन्न लोग जीवन की संकीर्ण गलियों के भीतर दुख और कष्ट के बोझ उठाते हुए उस आध्यात्मिक राजपथ को ढूढ़ते रहते हैं, जो कि प्रशस्त, समतल और दिव्य है. कुछ लोग कम समय में पहुंचते हैं. कुछ लोग गलियों की कठिनाइयों में उलझे रह जाते हैं.

सद्गुरु मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का विकास करने में पूर्णतया समर्थ हैं. फिर उनके संपर्क में आने पर भी मनुष्य की चेतना के विकास की गति इतनी धीमी क्यों होती है?

सद्गुरु प्रकाशमान सूर्य की भांति हैं. जैसे सूर्य के प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अवरोध न हो और वह सीधा पड़े तो सब जल जाएगा. सद्गुरु मनुष्य की चेतना पर पड़े हुए असंख्य पर्दों को एक साथ नहीं हटाते, क्योंकि इस स्थिति को झेल पाना आसान नहीं है. श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर जब अपना विराट रूप दिखाया था, तो उस दिव्य दृष्टि के होने के बावजूद भी अर्जुन श्रीकृष्ण के विराट रूप को देखकर घबरा गये थे. इसीलिए सद्गुरु मनुष्य की चेतना पर पड़े हुए अनगिनत परदों को क्रमशः हटाते हुए उसे धीरे–धीरे आत्मानुभूति के योग्य बनाते हैं. इसमें समय लगता है. आध्यात्मिक खजाना भरपूर है, लेकिन उसे ग्रहण करने की पात्रता या क्षमता बिरलों में ही होती है. वास्तविकता तो यह है कि यह क्षमता भी सद्गुरु ही प्रदान करते हैं, लेकिन एकाएक नहीं. इसमें जन्म–जन्मान्तर भी लग जाते हैं.

लोग असली मार्ग की दिशा कब ढूढ़ पाते हैं?

कर्म–फल के अनुसार जब उचित समय आता है. जब मुसीबत आने पर वह अपने जीवन के बारे में विचार करना आरम्भ करता है. करोड़ो प्रकार के विभिन्न प्राणी–जिनमें मानव सबसे उन्नत है, जीवन के अलग–अलग गलियारों में चलते रहते हैं. राजपथ पर पहुंचने के लिए इसका अर्थ यह है कि विभिन्न लोग जीवन की संकीर्ण गलियों के भीतर दुख और कष्ट के बोझ उठाते हुए उस आध्यात्मिक राजपथ को ढूढ़ते रहते हैं, जो कि प्रशस्त, समतल और दिव्य है. कुछ लोग कम समय में पहुंचते हैं. कुछ लोग गलियों की कठिनाइयों में उलझे रह जाते हैं. कुछ गलियों के ऊबड़–खाबड़ रास्ते में गिरते पड़ते चलते हैं. कुछ आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते हैं. कुछ चल नहीं पाते और थक कर बीच में बैठ जाते हैं, कुछ किसी सराय में रुक जाते हैं. कुछ मायावी बाजार से आकर्षित होकर रह जाते हैं. समय के क्रम में जो जन्म–जन्मान्तर से उस राजपथ के द्वार पर पहुंचते हैं, तो बिना द्वारपाल के अनुमति के अंदर घुस नहीं पाते. वे द्वारपाल ही सद्गुरु हैं. एक बार सदगुरु जिसका दरवाजा खोलकर आध्यात्मिक राजपथ में प्रवेश देते हैं, वह फिर वापस नहीं लौटता. उसे फिर राजपथ पर चलना ही पड़ता है. इस राजपथ में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि राजपथ के अंत में मालिक या ईश्वर बैठा है. पहले वह उनको अस्पष्ट रूप से देख पाता है, फिर धीरे–धीरे उनका रूप स्पष्ट होने लगता है. आध्यात्मिक रास्ता और उसमें प्रगति करना सद्गुरु के बिना असंभव है.

सबूरी क्या है?

अच्छी और बुरी दोनों परस्थितियों को अविचलित भाव से ग्रहण करने को ही सबूरी कहते हैं, संस्कार हमारे भीतर जड़ जमाए हुए हैं और इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो हमारे आनुवंशिकी कूट(genetic code) में चली जाती हैं. ये संस्कार आसानी से खत्म नहीं होते हैं. जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो इन संस्कारों को और मजबूत करते रहते हैं. इन संस्कारों की जड़ों को काटने का उपाय है–सकारात्मक विचारों को अपनाना. सकारात्मक विचार की तरह नकारात्मक विचार फलते–फूलते रहते हैं. किसी व्यक्ति को पहले ही अगर हम पूर्वाग्रह के साथ नहीं देखकर सामान्य रूप से देखेंगे तो धीरे–धीरे हम पाएंगे कि वह उतना बुरा नहीं है, जितना कि हम उसे समझ रहे हैं. इस प्रकार सकारात्मक सोच के साथ प्रतिक्रिया रहित होकर धीरे–धीरे संस्कारों को काटना ही सबूरी कहा जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

मंदिरों में पड़ा सोना देशहित में लगे

यह जानकर खुशी हुई कि भारत के पद्मनाभस्वामी मंदिर, शिरडी के साईं मंदिर व सिद्धि विनायक मंदिर सिर्फ तीन मंदिरों में ही तीन हजार टन से अधिक सोने का भंडार है. यह सोना भक्तों ने भगवान के चरणों में समर्पित किया है. इस सोने का इस्तेमाल केवल देश हित में ही किया जाना चाहिए. कानून बनाकर केन्द्र सरकार यह सोना रिजर्व बैंक में रखे तथा इस धन का उपयोग नए बिजली घर बनाने, सड़क, अस्पताल, उच्च शिक्षा केन्द्र, गरीबों के लिए आवास बनाने तथा सौर ऊर्जा उपकरणों पर 75% सब्सिडी देने में किया जाए.

–राजकिशोर पांडेय,
लखीमपुर, उत्तर प्रदेश.

शिक्षा में सुधार की जरूरत

विगत दो दशकों में उच्च शिक्षा का जिस तरह बाजीकरण हुआ है, उससे देश के तमाम उद्योगपति एवं राजनेता रातों रात शिक्षाविद बन गए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से मुनाफा कमाना है. ऐसी शिक्षा संस्थाएं डिग्री बांटने तक सीमित है, जिसके कारण आज डिग्री व पीएचडी दारक योग्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे. तभी तो 60 फीसद विश्वविद्यालय के तथा 80 फीसद डिग्री कॉलेज से निकले युवा तकनीकि कौशल तथा भाषा की दक्षता के अभाव में रोजगार से वंचित रह जाते हैं, अत: आज राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढांचागत सुधार, शोध की शुचिता एवं मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति करके हो उच्च शिक्षा की छवि को सुधारा जा सकता है.

–सत्य प्रकाश,
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

वादा निभाए सरकार

मोदी सरकार के एक साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि वे लोगों के अच्छे दिन लाएंगे. भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार में एक नारा दिया था कि अच्छे दिन वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार के एक साल बीत जाने के बाद भी लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि अच्छे दिनों के इंतजार में बूरे दिन जरूर आ गए. एक साल में महंगाई कम होने के बजाए बढ़ी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी सरकार बनने पर महंगाई कम करने, कालाधन लाने समेत कई ऐसे वादे किए थे जिनको 100 दिन में पूरा करने को कहा था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार में बात ज्यादा काम कम हो रहा है. इसलिए मोदी सरकार को बात कम काम ज्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए.

–रवि प्रकाश, *पालम, दिल्ली.*

कितने कामयाब होंगे राहुल गांधी

कवर स्टोरी– राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति बदल गई है(01 जून –07 जून 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तजेक है. मैं मनीष कुमार से सहमत हूं कि पिछले दस सालों में वह जितना संसद में बोले, उससे कहीं ज़्यादा बजट सत्र में उन्होंने अपनी बात रखी. राहुल गांधी छुट्टी से लौटने के बाद संसद से लेकर सड़क तक लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला कर रहे हैं. राहुल गांधी मोदी सरकार पर कई सारे ऐसे तंज कस रहे हैं, जो बिल्कुल निशाने पर लग रहे हैं, उनका एक तंज सूट–बूट की सरकार तो हिट हो गया. जिस पर मोदी सरकार की पूरी टीम को सफाई देनी पड़ी. राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात पर हमला बोला और कहा कि मोदी ने महमोहन सिंह से पाठशाला ली. अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी की बदली राजनीति और रणनीति कांग्रेस को कितनी सफलता दिलाती है.

–कृष्णकांत ओझा, *बक्सर, बिहार.*

जनता का हित सर्वोपरि हो

जब तोप मुकाबिल हो– प्रधानमंत्री जी, देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं (01 जून –07 जून 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. यह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और भाजपा किसी भी प्रश्न को गंभीरता से लेने की जगह उसे वाद–विवाद में उलझाने की वृत्ति का शिकार हो गई हैं. राहुल गांधी पूरे देश में घूम–घूम कर मोदी सरकार की नीतीयों और मोदी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं और भाजपा अपने कामों का प्रचार कर रही है और कांग्रेस को कोस रही है. दोनों ही पार्टिया किसी मुद्दे पर बहस के बजाय विवाद पैदा करने में लगी हुई हैं. जनता के दुखों और उनकी परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, किसान आत्महत्या को कैसे रोका जाए और बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले इसको लेकर किसी को चिंता नहीं है, लेकिन सरकारे दावा करती हैं कि उन्होंने जनता को सारी सुविधाएं मुहैया करा दी. सच्चाई यह है कि गरीब भूखों मर रहा है. उसके पास न रहने को घर है और न खाने को खाना. छत्तीसगढ़ में एक शख्स की भूख से तड़प–तड़प कर मौत हो जाती है और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं मिला. इससे शर्म की बात क्या हो सकती है. इसलिए राजनेताओं को चाहिए कि वाद–विवाद छोड़कर जनता के हितों के लिए कार्य करें.■

–शिवशंकर यादव, *उत्तर प्रदेश.*

ग़रीबों की सेवा

चौथी दुनिया ब्यूरो

गौतम बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा कि देश में अकाल पड़ा है. लोग अन्न एवं वस्त्र के लिए तरस रहे हैं. उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है. आप लोगों के शरीर पर जो वस्त्र हैं, उन्हें दान में दे दें. यह सुनकर कुछ लोग उठकर चले गए. कुछ कहने लगे, यदि वस्त्र इन्हें दे दें तो हम क्या पहनेंगे? उपदेश समाप्त हुआ. सभी श्रोता चले गए, पर निरंजन बैठा रहा. वह सोचने लगा–मेरे शरीर पर एक वस्त्र है. अगर मैं अपने वस्त्र दे दूंगा तो मुझे नग्न होना पड़ेगा. फिर उसने सोचा–मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है. साधु–संन्यासी भी बिना वस्त्र के रहते हैं. उसने अपनी धोती दे दी. बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया. निरंजन अपने घर की ओर चल पड़ा. वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था कि मैंने अपने आधे मन को जीत लिया. तभी निरंजन ने देखा कि दूसरी ओर से महाराज प्रसेनजित चले आ रहे हैं. निरंजन की बात सुनकर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी बात का क्या अर्थ है? निरंजन ने उत्तर दिया कि महाराज! महात्मा गौतम बुद्ध दुखियों के लिए दान में वस्त्र मांग रहे थे. यह सुनकर मेरे एक मन ने कहा कि शरीर पर पड़ी एकमात्र धोती दान में दे दो, लेकिन दूसरे मन ने कहा कि यह भी दे दोगे तो पहनोगे क्या? दान देने वाले मन की विजय हुई. मैंने धोती दान में दे दी. यह सुनकर प्रसेनजित ने अपना परिधान उतारकर निरंजन को दे दिया. निरंजन ने उसे भी महात्मा बुद्ध के चरणों में डाल दिया. बुद्ध ने निरंजन को हृदय से लगाते हुए कहा कि जो अपना सब कुछ दान कर देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

साहित्यिक बिग बॉस का घर

अनंत विजय

हाल के दिनों में जिस तरह से साहित्यिक चर्चाओं के लिए व्हाट्सएप और अन्य चैट साइट का उपयोग किया जा रहा है, वह हिंदी साहित्य के लिए खासा उत्साहजनक है. इस माध्यम पर साहित्यकारों और रचनाकारों के अलग–अलग समूह हैं. किसी समूह पर खास तौर पर कविता पर बात होती है, तो कोई समूह कहानी को केंद्र में रखकर विमर्श चलाता है. इनसे इतर कई समूहों में साहित्य की हर विधाओं पर बात होती है. व्हाट्सएप पर चलने वाले इन साहित्यिक समूहों में से कई में तो जबरदस्त अनुशासन है और वहां रचनाओं के लिए दिन नियत होते हैं कि अमुक दिन कहानी, तो अमुक दिन आलोचना पर बात होगी. ऐसे ही एक समूह रचनाकार में एक दिन यात्रा वृतांत पर भी बातचीत हुई थी. यात्रा वृतांत साहित्य की ख़त्म होती विधाओं में से एक है.

जिस तरह से पत्र साहित्य समकालीन परिदृश्य से लगभग ओझल हो गया है, उसी राह पर यात्रा वृत्तांत चल पड़ा है. ऐसे में किसी साहित्यिक समूह में उस पर बात होते देखना आश्वस्तिकारक है. इंटरनेट के माध्यम से जुड़े इन साहित्यिक समूहों पर होने वाली चर्चाओं को देख–पढ़कर लगता है कि यह मंच कई शहरों में चलने वाले कॉफी हाउस की तरह है, जहां साहित्यिक मुद्दों पर गर्मागर्म बहस हुआ करती थी. विश्व साहित्य में कॉफी हाउस का अहम स्थान रहा है. भारत में कॉफी हाउसों के बंद होने के बाद इस तरह के मंच की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की जा रही थी, जहां साहित्यिक मुद्दों पर विमर्श हो सके. चैट साइट्स पर चलने वाले कई साहित्यिक समूहों में सदस्य खुलकर अपने विचार रखते हैं. कई बार तो विमर्श इतना तीखा हो जाता है कि कमज़ोर पड़ने वाला शख्स व्यक्तिगत भी होने लगता है.

इस तरह के कई साहित्यिक समूहों के सदस्यों से बातचीत करने पर दो–तीन बातें उभर कर सामने आने लगी हैं. पहली बात तो यह है कि चैट साइट्स पर चलने वाले इन साहित्यिक मंचों पर कॉफी हाउस जैसा लोकतंत्र नहीं है. यहां साफ़गोई से बात करने वाले पसंद नहीं किए जाते हैं. ज़्यादातर लेखक साफ़ बात करने वाले को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें नकारात्मक सोच का करार देने की मुहिम चलाने में जुट जाते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि इन समूहों का जो तेज पहले होता था, जो वैचारिक उष्मा शुरुआत में होती थी, वह धीरे– धीरे क्षीण होने लगती है और उन पर तारीफ़ का मंच बनने का ख़तरा मंडराने लगता है. सबकी तारीफ़ करते रहो और लोकप्रिय बने रहो, का मंत्र अपनाने वाले बहुत सुकून में रहते हैं. इन साहित्यिक समूहों में अपनी आलोचना सुनने का माद्दा नहीं है. वहां मौजूद रचनाकार और कलमकार रचनाओं की आलोचना को व्यक्तिगत आलोचना मान लेते हैं और फिर उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं.

वे इस फिराक में भी रहते हैं कि आलोचना करने वालों से कैसे बदला चुकाया जाए या उन्हें किस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए. इस तरह के हालात देखते हुए वरिष्ठ आलोचक निर्मला जैन की बात पर यकीन करने का दिल होता है. निर्मला जैन ने एक बार कहा था कि हिंदी के रचनाकार अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं. एक शब्द भी उनके ख़िलाफ़ बोलकर दुश्मनी मोल लेने का ख़तरा पैदा हो जाता है. लेकिन, फिर वही बात कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना छोड़ देना आख़िर कितना उचित होगा? दरअसल, यह समस्या पूरे हिंदी साहित्य की होती जा रही है, जो कि व्हाट्सएप जैसे माध्यमों के मार्फत चलने वाले समूहों में प्रतिबिंबित होती है. साहित्य में तो यह स्थिति आ गई है कि अगर आपने किसी की रचना की तारीफ़ कर दी, तो आपकी समझ रामचंद्र शुक्ल जैसी है और अगर आपने कमज़ोर जगह पर हाथ रख दिया, तो आपको साहित्य की समझ ही नहीं है. फिर आपको वैचारिक से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर घेरने का गंदा खेल शुरू हो जाता है.

इन सबसे इतर भी इन साहित्यिक समूहों की एक दुनिया है. कमोबेश व्हाट्सएप पर चलने वाले ये समूह एक तरह से देखें, तो लोकप्रिय सीरियल बिग बॉस की तरह हैं, बिग बॉस के घर की तरह हैं. बिग बॉस के घर में जिस तरह की गतिविधियां चलती हैं, उसी तरह की गतिविधियां यहां भी चलती हैं. यहां भी साजिशें होती हैं, गुटों की राजनीति होती है, सबकी अपनी–अपनी पसंद होती है, नापसंद होती है, मोहब्बतें भी पनपती हैं, खुलेआम फ्लर्ट भी होता है, उखाड़ने–पछाड़ने का खेल भी खेला जाता है. कई लोग बेहद सक्रिय होते हैं, तो कुछ निष्क्रिय. कई लोग आक्रामक और उग्र होते हैं, तो कई शांत स्वभाव के. बस फ़र्क़ सिर्फ़ इतना होता है कि यहां कैमरा नहीं लगा होता है. समूह के सदस्यों के गुटों की पहचान करने वालों को लगातार की जाने वाली पोस्ट पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर ध्यान रखना होता है. समूह के सदस्य अगर कुछ पोस्ट करते हैं, तो उसे पसंद–नापसंद करने वालों के नाम से उनके गुटों का अंदाज़ लगाया जा सकता है.

इसी तरह से कई बार लोग अलग से व्यक्तिगत मैसेज भेजकर भी अपनी रचनाओं के समर्थन में टिप्पणी करने का आग्रह करते हैं. आग्रह न मानने पर पहले तो दो–तीन बार खुशामदनुमा अनुरोध करते हैं फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं. बेवजह का विरोध, व्यक्ति आक्षेप से लेकर कटाक्ष और अपमानजनक टिप्पणियों का दौर शुरू हो जाता है. इन सबके बीच समूह का एडमिन बिग बॉस की तरह बर्ताव करता है. पहले तो वह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, हर किसी को खुश रखने की जुगत में रहता है. ज़रूरत पड़ने पर डांट–फटकार भी लगाता है. असाधारण परिस्थितियों में किसी सदस्य को पहले चेतावनी देता है और अगर स्थितियां नहीं संभलती हैं, तो उसे समूह से बाहर भी कर देता है. बिग बॉस की तरह इन समूहों के एडमिन को भी सदस्यों के आरोप झेलने पड़ते हैं. कई बार किसी को बढ़ावा देने का आरोप, तो कई बार चुप रहने का. इस तरह से देखा जाए, तो व्हाट्सएप पर चलने वाले ये साहित्यिक समूह खूब लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन कई बार ये प्रतिभाहीनता को बढ़ावा भी देते हैं. प्रतिभाहीनता को बढ़ावा इस अर्थ में कि इनमें तू पंत–मैं निराला वाली प्रवृत्ति ज़्यादा हावी होती जा रही है. इस वजह से कॉफी हाउसों में चलने वाली बहसों से यहां की बहस का स्तर भी निम्न रहता है, बहुधा वैचारिक उष्मा की आंच भी महसूस नहीं होती.■

निर्मला जैन ने एक बार कहा था कि हिंदी के रचनाकार अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं. एक शब्द भी उनके ख़िलाफ़ बोलकर दुश्मनी मोल लेने का ख़तरा पैदा हो जाता है. लेकिन, फिर वही बात कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना छोड़ देना आख़िर कितना उचित होगा? दरअसल, यह समस्या पूरे हिंदी साहित्य की होती जा रही है, जो कि व्हाट्सएप जैसे माध्यमों के मार्फत चलने वाले समूहों में प्रतिबिंबित होती है. साहित्य में तो यह स्थिति आ गई है कि अगर आपने किसी की रचना की तारीफ़ कर दी, तो आपकी समझ रामचंद्र शुक्ल जैसी है और अगर आपने कमज़ोर जगह पर हाथ रख दिया, तो आपको साहित्य की समझ ही नहीं है. फिर आपको वैचारिक से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर घेरने का गंदा खेल शुरू हो जाता है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

तल्ख हालात में प्रेम की सुगबुगाहट

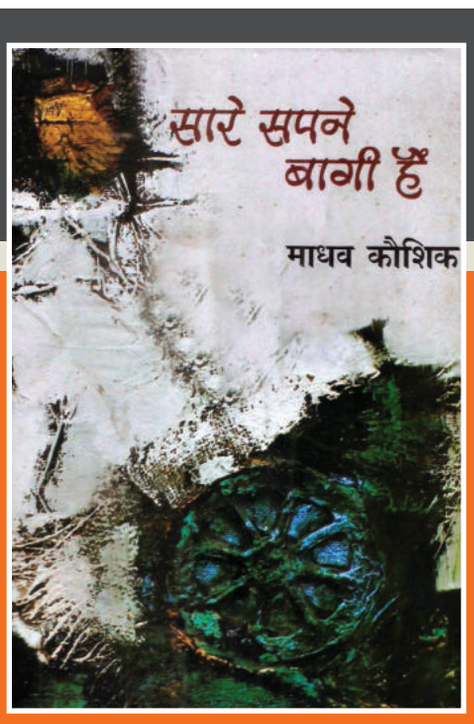

समीक्ष्य कृति
सारे सपने बागी हैं (ग़ज़ल संग्रह)

ग़ज़लकार
माधव कौशिक

प्रकाशक
वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली

मूल्य: 125 रुपये

कुमार कृष्णन

ग़ज़ल लेखन की कला और उसकी बारीकियों की गहराई को जान लेना ही ग़ज़ल लेखन की शर्त नहीं है. छंदानुशासन के भीतर जो इसका सौंदर्यबोध होता है, वह बिंब, प्रतीक और संकेतों के अर्थपूर्ण समन्वय की कला है. हिंदी में ग़ज़ल लेखन की जो परंपरा विकसित हुई है, वह कई मायनों में हिंदी कविता के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ग़ज़ल के नाम पर कुछ अर्थहीन और प्रभावहीन ग़ज़लें लिखी जा रही हैं. हालांकि, यह परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कोई विधा विकास और साहित्य में स्थापित होने के लिए अग्रसर होती है, तो उस विधा को कुछ नकारात्मक लेखन का भी सामना करना पड़ता है. इस नकारात्मक लेखन का प्रभाव हिंदी ग़ज़ल पर भी पड़ा है. शायद यही कारण है कि छंद को न जानने वाले आलोचक कथ्य का ही खूंट पकड़ कर हिंदी ग़ज़ल के पीछे हथियार लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ग़ज़ल लेखन के सकारात्क पक्ष काफी मजबूत हैं.

हिंदी ग़ज़लकारों में कुछ नाम अत्यधिक चर्चा में हैं, जिन्हें हिंदी ग़ज़ल की स्थापना की कड़ी में देखा जा सकता है. माधव कौशिक का नाम भी हिंदी के एक महत्वपूर्ण ग़ज़लकार के रूप में लिया जाता है. इसका प्रमुख कारण यह है कि माधव कौशिक ने हिंदी ग़ज़ल पर काफी काम किया है. उनके कई ग़ज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. उन्हीं ग़ज़ल संग्रहों में से एक ग़ज़ल संग्रह–सारे सपने बागी हैं, हाल ही में वाणी प्रकाशन से छपकर पाठकों के समक्ष आया है. संग्रह में कुल 96 ग़ज़लें हैं, जो विभिन्न भावों, संकेतों और बिंबों से लैस हैं. साथ ही इन ग़ज़लों में कहन का सौंदर्य और पाठ में सहज लयात्मकता है. मिसाल के तौर पर:–

अपने दिल का हाल सुनाना कम से कम
आंखों में आंसू लाना कम से कम

मिलने वाली चीजें खुद मिल जाती हैं
अपने दामन को फैलाना कम से कम

उक्त वर्णित शेरों में माधव कौशिक की प्रगतिशील चिंता तो है ही, साथ ही दु:ख, तकलीफ और मजबूरियों का तल्ख एहसास है तथा ये नई सोच के साथ तकलीफ के विरुद्ध समाज को डटे रहने की प्रेरणा भी देते हैं. हिंदी ग़ज़ल के प्रसिद्ध आलोचक अनिरूद्ध सिन्हा द्वारा इन ग़ज़लों के बारे में की गई टिप्पणी देखिए, माधव कौशिक की ग़ज़लों में सादगी है. ये समाज की बोलती– बतियाती तस्वीरें हैं, जिनमें एक मध्यवर्गीय जीवन का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत होता है.

सचमुच में सपने सारे बागी हैं की अधिकांश ग़ज़लें मध्यवर्गीय जीवन की व्याख्या करते हुए मुश्किलों से लड़ने की दलीलें भी पेश करती हैं. आज का जीवन सचमुच में भीतर से लहूलुहान है. इसी लहूलुहान जीवन और रिश्तों के बीच माधव कौशिक कहते हैं:–

वे–यकीनी ने हमें अंदर से अंधा कर दिया
गर यकीं हो तो पहाड़ों का जिगर हिलता भी है

बावजूद इसके माधव कौशिक की ग़ज़लों का कैनवॉस काफी बड़ा है, जिसमें धूप, नदी, बारिश, घटा, रंग– बिरंगे फूल तथा जीवन उत्सव के कई चित्र मिलते हैं. कारण यह है कि माधव कौशिक अवसाद की चादर ओढ़कर पाठकों के समक्ष नहीं आते हैं, बल्कि अपनी खुली आंखों में कुछ बेहतर चित्र लेकर भी प्रस्तुत होते हैं. एक बानगी देखिए:–

जीवन का क्या कोई मानक होता है
खुशबू का आरंभ अचानक होता है

बेहतर है कोई चिंगारी निकले क्यों
हिंसा का परिणाम भयानक होता है

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सपने सारे बागी हैं की ग़जलों में एक साथ रोमांच, रहस्य, जीवन, भविष्य की कल्पना और विद्रोह की सुगबुगाहट है. इन ग़ज़लों से गुजरने के बाद पाठकों को आत्मबल मिलेगा. ऐसी आशा है.■

feedback@chauthiduniya.com

> गूगल ने अभी क्रोम का एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे क्रोम कस्टम टैब्स कहते हैं. इस फीचर की मदद से यूजर्स क्रोम टैब्स को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में ऐप्स की मदद से कस्टमाइज कर सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ऐप आपको क्रोम ब्राउजर खोलने के लिए कहता है, तो क्रोम में वो डाटा सेव हो जाएगा.

गूगल का नया एंड्रॉयड एम

गूगल के नए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एम(M) को लेकर लोग उत्साहित हैं. इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कई नए फीचर्स को लेकर बातें हो रही हैं. इसके फीचर्स काफी हद तक यूजर्स फ्रेंडली हैं. इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ट फीचर्स, इसके आने के बाद आपको पसंद आ सकते हैं.

1. ऐप परमीशन–
एंड्रॉयड एम के सबसे अच्छे फीचर्स में से एक है ऐप परमीशन. एंड्रॉयड एम के साथ गूगल ने ऐप परमीशन को बढ़ा दिया है. इस फीचर के बाद ऐप नहीं बल्कि यूजर तय कर पाएगा की कैसी परमीशन के साथ ऐप इंस्टॉल करना है. आसान शब्दों में कहें तो कोई ऐप फोन का कितना डाटा इस्तेमाल कर पाएगा और कितना नहीं ये यूजर पर निर्भर करेगा. इसी के साथ, यूजर्स सेटिंग्स के जरिए सभी ऐप्स परमीशन मैनेज कर पाएंगे.

2. नाओ ऑन टैप–
गूगल ने एक नया फीचर नाओ ऑन टैप भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पेश किया है. यह पूरी जानकारी एक टैप पर उपलब्ध होगी. इसमें सब कुछ जैसे यूजर्स ने क्या किया, क्या हिस्ट्री रही, क्या लोकेशन है सब कुछ एक टैप पर उपलब्ध होगा.

3. वेब एक्सपीरियंस–
गूगल ने अभी क्रोम का एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे क्रोम कस्टम टैब्स कहते हैं. इस फीचर की मदद से यूजर्स क्रोम टैब्स को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में ऐप्स की मदद से कस्टमाइज कर सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ऐप आपको क्रोम ब्राउजर खोलने के लिए कहता है, तो क्रोम में वो डाटा सेव हो जाएगा. अगली बार भी उसी जगह से क्रोम ब्राउजर को खोल सकते हैं.

4. नया रैम मैनेजर–
नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नया रैम मैनेजर भी आ गया है. इसका मतलब कौन सा ऐप फोन की कितनी मेमोरी का इस्तेमाल करता है ये नए तरीके से होगा. इसके अलावा, यूजर्स को ये भी पता चलेगा की तत्कालीन इस्तेमाल करने वाले ऐप्स कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी पता होगा.

5. नया ऐप ड्रॉअर–
एंड्रॉयड एम के साथ नया ऐप ड्राअर भी आएगा. ये विजेट पिकर की तरह होगा. अब ऐप्स को स्क्रीन पर साइड वाइज की जगह वर्टिकली स्क्रॉल किया जाएगा. इसके अलावा, कलर और रीडिजाइनिंग पुरानी ही लगेगी.

6. फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट–
यह नया फीचर स्कैनर्स के साथ काम करने के लिए बनाया गया है. फिलहाल सैमसंग गैलेक्सी एस6, एसटीसी वन एम9 जैसे स्मार्टफोन्स में पहले से ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है. अब एंड्रॉयड एम में ये टेक्नोलॉजी आने से उम्मीद की जा सकती है कि अब सस्ते डिवाइसेस में भी ये तकनीक आएगी.

7. एंड्रॉयड पीवाई(PY)

ये भले ही एप्पल झङ्कध की कॉपी लगे, लेकिन गूगल का एंड्रॉयड पीवाई कुछ नया है. ये भी एप्पल पीवाई की तरह एनएफसी के जरिए काम करता है. इसका मतलब ये है कि एनएफसी पर काम करने वाले सभी पोर्ट्लस पर ये काम कर सकेगा. एंड्रॉयड पे की मदद से मोबाइल पेमेंट्स हो सकेंगी. ये एंड्रॉयड किटकैट 4.4 या उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले किसी भी डिवाइस पर काम कर सकेगा. हालांकि, भारतीय यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

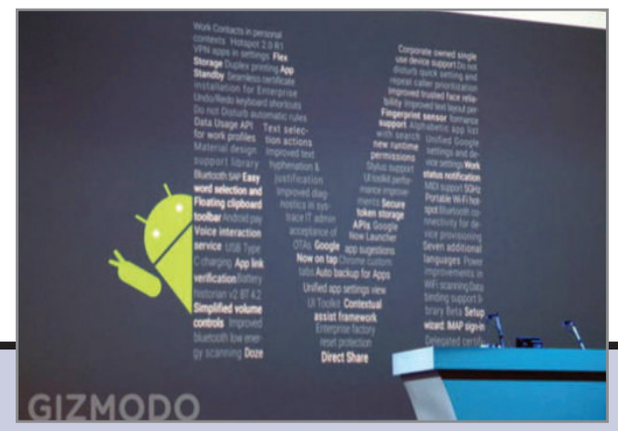

क्या होता है एनएफसी–
नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) शॉर्ट रेंज में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने में मदद करता है. आसान शब्दों में लिमिटेड दूरी में तेज स्पीड के साथ एनएफसी की मदद से वायरलेस डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं. ये फाइल शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस और बाकी ट्रांसफर के लिए काफी उपयोगी साबित होता है. खबरों के अनुसार, एप्पल ने डच चिपमेकर के साथ डील कर इस बार आईफोन में एनएफसी का इस्तेमाल किया है. ये वन टच पेमेंट्स के लिए किया गया है.

8. रिवर्सिबल यूएसबी सी पोर्ट्स–
एप्पल मैकबुक में यूएसबी सी पोर्ट आने के बाद गूगल ने भी अब एंड्रॉयड एम के साथ यूएसबी सी टाइप पोर्ट्स का सपोर्ट फीचर दे दिया है. यूएसबी सी टाइप पोर्ट्स दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं. आसान शब्दों में कहें तो पोर्ट में किसी भी तरफ से केबल लगाई जाए वो काम करेगी. खबरों की मानें तो नेक्सस फोन ही वो पहले फोन्स हैं जिनके साथ ये पोर्ट्स आए हैं.

9. बेहतर बैटरी लाइफ–
गूगल ने प्रोजेक्ट वोल्टा के तहत इस बार एंड्रॉइड की बैटरी को और बेहतर बनाया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि इस बार पावर कन्जम्पशन बेहतर होगा और बैटरी लाइफ बढ़ेगी. मल्टीटास्किंग के बाद भी बैटरी पावर कम नहीं होगी. इसके अलावा, फास्ट चार्जिंग फीचर और ऐप्स के द्वारा बैटरी खर्च करने की समस्या कम होगी.■

सुजुकी की फुल फेयर्ड जिक्सर एसएफ

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड ने भारतीय बाजार में अपनी फुल फेयर्ड जिक्सर एसएफ लॉन्च कर दी है. यह 155सीसी बाइक जिक्सर का फुल फेयर्ड वर्जन है. इसमें फ्रंट डिजाइन के अलावा वे सारे फीचर्स मौजूद हैं, जो पिछले जिक्सर मॉडल में दिए गए थे. कंपनी ने इस बाइक में कई स्पेशल फीचर्स, जैसे स्पॉर्टी डुअल मफ्लर और ट्रेंडी स्मार्टफोन के सरूप डिजिटल स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने इस बाइक में एडवांस सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया है, जिसमें कंपनी ने सुजुकी ईको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. ये फ्यूज एफिशियंसी और परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करती है. इंजन की बात करें तो इसमें 155 सेमी क्यूब, 4 स्ट्रोक का एक सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने बाइक की कीमत 83,499 रुपये रखी है.■

सैमसंग गैलेक्सी कोर 4जी स्मार्टफोन लॉन्च

सैमसंग ने एक नया 4जी स्मार्टफोन लॉन्च किया है. कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है. इस फोन को खरीदने पर आपको मिलता है एयरटेल का 3जी फ्री 4जी डाटा. सैमसंग गैलेक्सी कोर प्राइम 4जी स्मार्टफोन TDD-LTE (2300) 4जी नेटवर्क सपोर्ट करता है. इस फोन का 3जी वेरिएंट पहले से ही भारतीय बाजार में बेचा जा रहा है. फोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो यह एंड्रॉयड के 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. साथ ही यह फोन डुअल सिम सपोर्ट करता है. फोन में कंपनी ने 4.5 इंच का डिस्प्ले दिया है, जो 480 x 800 पिक्सल रेजोल्यूशन देता है. पावर की बात करें तो सैमसंग के इस फोन में 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड कोर प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 1 जीबी रैम दी गई है. इसमें 8 जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 64 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन में लेड फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है. कनेक्टिविटी की बात करें, तो इस फोन में 3जी, जीपीआरएस, वाई–फाई 802.11 b/g/n, माइक्रो–यूएसबी, एनएफसी, जीपीएस और ब्लूटुथ के ऑप्शन्स दिए गए हैं. इसमें 2000 एमएएच की बैटरी है. सैमसंग गैलेक्सी कोर 4जी प्राइम की कीमत 9,999 रपये हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बेहतरीन लैपटॉप है मैकबूक प्रो

एप्पल ने भारत में 15 इंच रेटिना डिस्पले के साथ नया लैपटॉप मैकबूक प्रो लॉन्च किया है. यह लैपटाप 2.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर इंटेल कोर आई7 प्रोसेसर से लैस है. एप्पल के इस नए लैपटॉप में दमदार प्रोसेसर के साथ ही 16जीबी का रैम लगा है, जो बेहतरीन प्रासेसिंग स्पीड की गारंटी देता है. इस दमदार लैपटॉप की कीमत 1,59,900 रुपये रखी गई है. 9 घंटे की बैट्री लाइफ वाले इस लैपटॉप के दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं. इनमें से एक में 256जीबी फ्लैश स्टोरेज की सुविधा है, जबकि दूसरा वेरिएंट 2.5 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर इंटेल कोर आई7 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 16जीबी रैम के साथ 512जीबी की स्टोरेज क्षमता है. दूसरे वेरिएंट की कीमत 1,99,900 रुपये है.

मैकबुक के साथ ही एप्पल ने 27–इंच का आईमैक पीसी पीसी भी लॉन्च किया है. इसमें 5के रेटिना डिस्पले लगा है, जो 14.7 मिलियन पिक्सल का डिस्पले देता है. आईमैक में 3.3 गीगाहर्ट्ज का क्वॉड कोर इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर लगा है. इसकी स्टोरेज क्षमता 1टीबी और इसमें 8जीबी का रैम लगा हुआ है. आई मैक की कीमत 1,79,900 रुपये है.■

ऑडी का नया मॉडल क्यू7

ऑडी नई क्यू 7 को नवंबर 2015 में भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. ऑटो कार इंडिया वेबसाइट के मुताबिक, शुरुआत में क्यू7 को आयात किया जाएगा. कंपनी भारत में क्यू7 3.0 टीडीआई इंजन के साथ बेचेगी. यह इंजन 268 बीएचपी, 3.0 लीटर वी6 टर्बो–डीजल इंजन के साथ उतारेगी. यह क्वॉट्रो ऑल–वील ड्राइव एक 8–स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है. क्यू7 के पिछले अवतार में एयर सस्पेंशन था और इस लिहाज से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मॉडल में भी यह खूबी होगी. जहां तक फीचर्स की बात है, नई क्यू7 में ऑडी का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा. इस कार में फुल लैदर सीट्स, फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 19 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम हो सकता है. इसकी कीमत पुरानी कार से ज्यादा होगी. संभवत: यह 65 लाख रुपये के आस–पास हो सकती है.■

> भारत में क्यू7 3.0 टीडीआई इंजन के साथ बेचेगी. यह इंजन 268 बीएचपी, 3.0 लीटर वी6 टर्बो–डीजल इंजन के साथ उतारेगी.

> पांचवी बार फीफा अध्यक्ष निर्वाचित होने के महज चार दिन बाद ब्लाटर का इस्तीफा देना और उनका हृदय परिवर्तन होना बहुत से सवाल खड़े करता है. लेकिन उनके इस्तीफे के बाद फीफा में आधारभूत परिवर्तन करने का मौका मिला है. उनके इस्तीफे के बाद फुटबॉल की दुनिया में लोगों ने राहत की सांस ली है. फुटबॉल को ब्लाटर के चंगुल से मुक्ति मिली है. चार दशक तक फीफा को हर रूप में प्रभावित करने वाले ब्लाटर का इस्तीफा फुटबॉल के भविष्य के लिए अच्छा है. उनके इस्तीफे के बाद फीफा को खोई हुई विश्वसनीयता का एक अंश वापस मिल गया है और यह उम्मीद जगी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल बोलने का समय समाप्त हो गया है.

खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला

चौथी दुनिया ब्यूरो

अब तक दुनियाभर के खेलों में मैच फिक्सिंग के मामले सामने आते थे, लेकिन पहली बार मेजबानी फिक्सिंग का मामला सामने आया है. 2022 में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी फिक्स थी. कतर को मेजबानी दिए जाने का समर्थन करने के लिए फीफा के सदस्यों ने करोड़ों अमेरिकी डॉलर की रिश्वत ली थी. इस बात का खुलासा हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने किया है. आश्चर्यजनक रूप से साल 2010 में ज्यूरिख में संपन्न हुई मेजबानों की चुनाव प्रक्रिया में कुल 22 में से 14 वोट कतर के पक्ष में पड़े थे. जनवरी 2011 में फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लाटर कतर की राजधानी दोहा में एशियाई खेलों के आयोजन के पहले एक कार्यक्रम में पहुंचे और 2022 के फुटबॉल विश्व कप के सर्दियों में होने की उम्मीद जताई. 2018 और 2022 दोनों विश्व कप के लिए मेजबानों के चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों ने मई 2011 में सिर उठाना शुरू किया, जब संडे टाइम्स अखबार ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की.

एक व्हिसिल ब्लोअर फेड्रा अलमजीद ने दावा किया था कि कतर के पक्ष में वोट डालने के लिए फीफा की कार्यकारी समिति को पैसे दिए गए. इसके बाद सितंबर 2013 में यूरोपीय फुटबॉल की संचालक संस्था यूएफा के 54 सदस्यीय दल ने पारंपरिक रूप से जून–जुलाई महीनों में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट के समय को बदलने का समर्थन किया. इसके बाद इसी साल नवंबर में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड कप के आयोजन से जुड़े निर्माण कार्यों में हो रहे मानवाधिकार हनन का खुलासा किया. इसे लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की. इसके बाद पिछले साल जून में ब्राजील में आयोजित हुए विश्व कप के दौरान फीफा पर 2022 का नया मेजबान चुनने का दबाव बढ़ गया, तब अमेरिकी वकील मिशेल गार्सिया की अध्यक्षता वाले दल ने फीफा पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी थी. गार्सिया की फाइनल रिपोर्ट को कानूनी पेंच में उलझा कर फीफा ने सार्वजनिक नहीं होने दिया. पिछले साल नवंबर में फीफा ने ही स्विस अटॉर्नी के पास कुछ लोगों के खिलाफ 2018 और 2022 विश्व कप मेजबानी मामले में संभावित गड़बड़ी की शिकायत दर्ज की. 24 फरवरी को फीफा विश्व कप टास्क फोर्स ने प्रस्ताव दिया कि 2022 मुकाबले कतर में ही सर्दी के मौसम में नवंबर–दिसंबर में आयोजित किए जाएं, लेकिन कतर से मेजबानी वापस लिए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया.

27 मई, 2015 को स्विस अधिकारियों ने फीफा के ज्यूरिख मुख्यालय पर छापे मारे और 17 सालों से फीफा प्रमुख रहे ब्लाटर के साथ काम करने वाले कई वरिष्ठ अधिकारियों को साजिश और भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया, जिनमें फीफा के पूर्व उपाध्यक्षों जेफ़री वेब और यूगेनियो फिगोरेडे के अलावा एडुआर्डो ली, जूलियो रोका, कोस्टस टक्कास, राफेल एस्कुवेल और होसे मारिया मारिन भी शामिल हैं. उनके अलावा, कुछ अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. उनमें हाल के दिनों तक फीफा के उपाध्यक्ष और उत्तरी–मध्य अमरीका व कैरेबियन फुटबॉल परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष, जैक वार्नर और दक्षिण अमरीकी फुटबॉल परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष निकोलस लियोज़ भी शामिल हैं. इसके बाद फीफा के पूर्व शीर्ष अधिकारी चक ब्लेजर ने कोर्ट में रिश्वत लेने की बात स्वीकार की है. ब्लेजर के इस बयान से इस मामले में और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि उसने फीफा पदाधिकारियों के साथ मिलकर 1998 और 2010 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए रिश्वत ली थी. विश्व कप 1998 की मेजबानी फ्रांस को मिली थी, जिसने मोरक्को को दौड़ में पछाड़ा था. वहीं 2010 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था. ख़बरों के अनुसार, पिछले 24 सालों में 15 करोड़ डॉलर कथित तौर पर घूस या कमीशन के रूप में फीफा अधिकारियों ने लिए हैं. यदि चक के बयान में सच्चाई है तो 1998 में ब्लाटर के फीफा अध्यक्ष बनने के बाद उनकी मौन स्वीकृति के तहत फीफा में रिश्वत का यह काला खेल शुरू हो गया था.

पूरी दुनिया अब फीफा में फैले भ्रष्टाचार के लिए 17 साल तक अध्यक्ष रहे सेप ब्लाटर को ही जिम्मेदार ठहराया है. जब वह 1998 में फीफा के अध्यक्ष बने थे तब भी उन पर अपने पक्ष में वोट खरीदने के आरोप लगे थे. फीफा में भ्रष्टाचार की गंदी संस्कृति के जन्मदाता ब्लाटर ही है. हालांकि उन पर अब तक भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी अब तक अंजान बने हुए थे. इस बात के भी सबूत हैं कि ब्लाटर को 14.2 करोड़ स्विस फ्रैंक की रिश्वत के लेनदेन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने फीफा में भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये. अब, जब रिश्वतखोरी का खुलासा हो रहा है तो फीफा के दर्जनों अधिकारी हिरासत में लिए जा रहे हैं. उनमें से अधिकांश ब्लाटर के करीबी हैं. रिश्वतखोरी के बारे में जानकारी होने के बावजूद कुछ न करना ब्लाटर को भ्रष्टाचारियों का सहयोगी बनाता है.

पांचवी बार फीफा अध्यक्ष निर्वाचित होने के महज चार दिन बाद ब्लाटर का इस्तीफा देना और उनका हृदय परिवर्तन होना बहुत से सवाल खड़े करता है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद फीफा में आधारभूत परिवर्तन करने का मौका मिला है. उनके इस्तीफे के बाद फुटबॉल की दुनिया में लोगों ने राहत की सांस ली है. फुटबॉल को ब्लाटर के चंगुल से मुक्ति मिली है. चार दशक तक फीफा को हर रूप में प्रभावित करने वाले ब्लाटर का इस्तीफा फुटबॉल के भविष्य के लिए अच्छा है. उनके इस्तीफे के बाद फीफा को खोई हुई विश्वसनीयता का एक अंश वापस मिल गया है और यह उम्मीद जगी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल बोलने का समय समाप्त हो गया है. फीफा में अक्सर पारदर्शिता की बात की जाती है, लेकिन ब्लाटर की सारी कार्यप्रणाली अंधेरे में रही है. यहां फेयरप्ले के नाम पर अब तक केवल लफ्फाजी हो रही थी. फीफा में नई शुरुआत का रास्ता अब खुल गया है. फीफा एक बार फिर से अपनी खोज कर सकता है, पुराने नियमों को ताक पर रख सकता है और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है.

इस पूरे मामले का सकारात्मक पहलू भी है. बुरी तरह बंटे यूरोपीय फुटबॉल संगठनों के इर्द–गिर्द जमा विपक्ष एक बार फिर से इकट्ठा हो सकता है. उसे अब इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी और दिखाना होगा कि बेहतर फीफा कैसा हो सकता है. सभी को ईमानदारी से यह स्वीकार करना होगा कि आखिरकार फीफा है. यह स्वीकार करना होगा कि फीफा स्विस कानूनों के मुताबिक छोटा और गैर मुनाफे वाला संगठन नहीं है, बल्कि अरबों कमाने वाली एक बड़ी कंपनी है. यह स्वीकार करना भी एक बड़ी शुरुआत होगी. उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ब्लाटर का इस्तीफा फीफा क्रांति की शुरुआत है, लेकिन यह तो समय ही बताएगा. फिलहाल फीफा को एक ऐसे शख्स की जरूरत है, जो मौके की नज़ाकत को समझे, फीफा को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाले और उसका कायाकल्प कर दे.■

feedback@chauthiduniya.com

फीफा के ब्लाटर युग का अंत

पांचवी बार फीफा का अध्यक्ष चुने जाने के मात्र चार दिन बाद ही सेप ब्लाटर ने पद छोड़ दिया. ब्लाटर से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे यूरोपीय बिना दांत के शेर साबित हुए और ब्लाटर पांचवीं बार फीफा अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए. सन 1975 में फीफा में ब्लाटर के प्रवेश के पहले भी वह कई खेल संस्थानों में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके थे. एडीडास कंपनी के मालिक एडोल्फ डासलर की मदद से ब्लाटर ने फीफा में एंट्री की और 1981 में महासचिव चुने गए. 17 सालों तक ज्वाओ आवेलांजी की अध्यक्षता में महासचिव की भूमिका निभाने के बाद ब्लाटर ने फीफा अध्यक्ष का पद संभाला.

सन 1998 के चुनाव में आवेलांजी के पद का उत्तराधिकारी बनने के लिए उन्होंने तत्कालीन यूईएफए अध्यक्ष और अग्रणी दावेदार लेनार्ट जोहान्सन को पिछाड़ा. इसके बाद अफवाहें उड़ीं कि ब्लाटर ने अपने पक्ष में मत खरीदे थे. ब्लाटर पर आर्थिक प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप लगातार लगते रहे. अध्यक्ष पद पर चुने जाने के एक साल बाद ही उनके सहकर्मी फीफा के महासचिव मिशेल जेन–रुफिनेन ने उन पर मार्केटिंग खर्च में करीब 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नुकसान का आरोप जड़ा, लेकिन ब्लाटर न केवल आंतरिक जांच और स्विस कोर्ट में लॉ–सूट से बच निकले, बल्कि उन्होंने जेन–रुफिनेन को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया. साल 2000 में जर्मनी को फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी दिलाने में ब्लाटर का अहम योगदान माना जाता है. इस बीच ब्लाटर संगठन में अपनी जगह और पक्की करने के लिए समर्थन जुटाते रहे. 2002 में उन्हें फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया. इस दौरान कतर से फीफा के कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद बिन हम्माम उभरे. 2007 में ब्लाटर को लगा कि बिन हम्माम अध्यक्ष की गद्दी के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन जब साल 2011 में बिन हम्माम ब्लाटर के खिलाफ अध्यक्ष की कुर्सी के लिए मुक़ाबले में खड़े हुए, तो अचानक उन पर घूसखोरी के कई आरोप जड़ दिए गए. इसके बाद न केवल उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ली, बल्कि फीफा से उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया.

कौन हो सकता है वैकल्पिक आयोजक

ब्लाटर के अचानक इस्तीफे और अमेरिका तथा स्विस अधिकारियों द्वारा 2022 विश्व कप की मेजबानी दिये जाने की प्रक्रिया की जांच के बाद से कतर की मेजबानी वापस लिये जाने तक की मांग उठने लगी है. इंग्लैंड फुटबाल के प्रमुख ग्रेग डाइके ने कहा कि फीफा पर 17 सालों तक राज करने वाले ब्लाटर के इस्तीफ के बाद कतर को नर्वस हो जाना चाहिए. लेकिन कतर विश्व कप के आयोजकों ने सभी आरोपो का निराधार बताते हुए कहा कि विश्वकप की दावेदारी प्रक्रिया पर उसके पास छिपाने के लिये कुछ भी नहीं है. लेकिन इस संबंध में ब्रिटेन के हाउस कॉमंस में उठे सवाल पर सरकार ने कहा कि यदि फीफा इसकी मेजबानी के लिए हम पर गौर करता है तो हमारे पास सुविधाएं है. हमने 2018 विश्व कप के लिए बहुत प्रभावशाली दावेदारी की थी हालांकि हमें सफलता नहीं मिली. जबकि 2022 के विश्वकप की मेजबानी के लिए अमेरिका तैयार दिख रहा है.■

कौन होगा ब्लाटर का उत्तराधिकारी

अमेरिका इस बार फीफा अध्यक्ष के लिए दिलचस्पी ले रहा है. रिकॉर्ड तीन बार से अमेरिकी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे भारतीय मूल के अमेरिकी सुनील गुलाटी फीफा अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने पिछले कुछ दशक में अमेरिकी फुटबॉल के विकास में अहम योगदान दिया है. हाल ही में संपन्न हुए अध्यक्ष के चुनाव में गुलाटी ने राजकुमार अली का समर्थन किया था. गुलाटी और अमेरिका ने ब्लाटर का विरोध किया था. उनके अलावा यूरोपीय फुटबॉल संघ(यूएफा) के अध्यक्ष माइकल प्लैतिनी शामिल हैं. इनके अलावा दक्षिण कोरिया के चुंग मोंग जून भी फीफा अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो गए हैं. वह फीफा उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं. इन सभी के अलावा हाल ही में फीफा अध्यक्ष पद के चुनाव में ब्लाटर को चुनौती देने वाले प्रिंस अली भी अध्यक्ष पद की दौड़ में एक बार फिर शामिल हैं.■

क्यों की अमेरिका ने जांच

साल 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी की वोटिंग में अमेरिका कतर के सामने पिछड़ गया था. वोटिंग के चौथे और अंतिम दौर में अमेरिका को कुल 22 में से 8 वोट हासिल हुए थे, जबकि कतर को 14. एक व्हिसिल ब्लोअर फेड्रा अलमजीद ने दावा किया कि कतर के पक्ष में वोट डालने के लिए फीफा की कार्यकारी समिति को पैसे दिए गए. इसके बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने इस मामले की अलग जांच की. अमेरिकी एजेंसी ने अपनी जांच में इन आरोपों को सही पाया और 14 लोगों को चिन्हित किया है, जिनमें नौ फीफा ऑफीशियल, पांच स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव शामिल हैं, जिनके खिलाफ षड़यंत्र, रैकेटिंग और मनी लाउंड्रिंग के आरोप लगे हैं. कुछ लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, जो पकड़ में नहीं आए हैं, उनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है.■

क्वीन ऑफ बॉलीवुड

बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिन्हें उनकी नायिकाओं के बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाता है. साथ ही बॉलीवुड में बहुत कम ऐसी नायिकायें हुई हैं जिन्होंने बॉलीवुड में नायकों के वर्चस्व को चुनौती दी है. उनमें से एक हैं कंगना रनौत. हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से ग्लैमर की इस दुनिया में पहुंची कंगना नौ साल के अंतराल में बॉलीवुड की क्वीन बन गईं. साल 2006 में महज 17 वर्ष की उम्र में फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में एंट्री, फिर साल 2008 में फिल्म फैशन के लिए नेशनल अवार्ड, इसके बाद साल 2014 में फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड जीतना. इसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्नस को साल 2015 की पहली सुपरहिट फिल्म बनाने के साथ 100 करोड़ के क्लब में शामिल कराना. यह सब एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है. लेकिन रील जैसी लगने वाली यह रियल स्टोरी कंगना रनौत की है.

कंगना बॉलीवुड में फिल्म हिट कराने की गारंटी बन गई हैं. फिल्मों को हिट कराने के लिए उन्हें किसी सुपरहिट को-एक्टर की जरूरत नहीं है. उन्हें अब फिल्म जगत में किसी मेल एक्टर से इंसेक्युरिटी नहीं है. बॉलीवुड में जिस मुकाम पर आज कंगना हैं वहां कुछ दिनों पहले तक डर्टी गर्ल विद्या बालन थीं. जिन्हें अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए अपने दमदार अभिनय और बेहतरीन पटकथा के अलावा और किसी चीज की दरकार नहीं थी. लेकिन विद्या की पिछली कुछ फिल्में असफल रही हैं, लेकिन कंगना सफलता की नित नई इबारत लिख रही हैं. इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स देने के बाद हर तरफ कंगना की धूम है. महिलायें घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं. समाज में महिलाओं की भूमिका लगातार बदल रही है. बॉलीवुड में महिलाओं के किरदार भी सीमाओं के दायरे से बाहर चले गए हैं, लड़कियां अब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं. हर दिन सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं. इसी वजह से फिल्मों में और फिल्म जगत में महिलाओं को लेकर विचार बदल रहे हैं. इसी वजह से बॉलीवुड में लगातार महिला केंद्रित कहानियों पर फिल्में बन रही हैं. इन फिल्मों के जरिये कंगना जैसी अभिनेत्रियां स्वयं को बॉलीवुड में स्थापित करने में सफल हो रही हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन उनकी ये फिल्में सफल होती हैं तो वे कंगना की तरह क्वीन के रूप में उभरकर सामने आ रही हैं.

कंगना की अपनी फिल्मों की सफलता के तीन मंत्र हैं. पहला वह किसी रोल को पकड़ने के लिए उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर काम करती हैं. इसके बाद वह उसकी बॉडी लैंग्वेज पर काम करती हैं और उसकी वर्तमान स्थिति को समझती हैं. कंगना मानती हैं कि एक रोल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा भी अपने साथ ले जाता है. वह आपको फिर कभी वापस नहीं मिलता है. इसलिए उस हिस्से को जितनी बेहतरी से जिया जा सकता है जी लेना चाहिए. यही उनकी एक कलाकार के रूप में सफलता का राज है. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सफलता के बाद ऐसा लगता है कि कंगना आमिर खान के नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं और बॉलीवुड की मिस परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं. यह बात इससे साबित होती है कि कंगना ने हाल ही में अपने फिल्मी कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा फेरबदल किया है. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में शर्त रखी है कि वह फिल्म एडिटिंग का भी हिस्सा होंगी. अब तक ऐसा आमिर खान करते आये हैं. लेकिन कंगना के इस कदम से यह भी जाहिर होता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद वह फिल्मों में अपने रोल को लेकर और ज्यादा संजीदा हो गई हैं, लेकिन कंगना की यह नई शर्त कई लोगों के गले नहीं उतर रही है. कंगना ने फिल्म क्वीन के कुछ डॉयलाग्स लिखे थे. वह अपनी फिल्मों की ज्यादातर प्रॉसेस से जुड़ी रहती हैं. इसके लिए उनकी तारीफ भी की जाती रही है. लेकिन कलाकारों की इस मांग को लेकर निर्देशक हमेशा सतर्क रहते हैं. क्योंकि इस तरह के क्लॉज की वजह से कई बार एडिटिंग के दौरान कई तरह की कांट-छांट का सामना करना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्ट में कंगना चाहती हैं कि उन्हें लिखित में यह दिया जाये कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर उन्हें भी दखल करने की अनुमति होगी. यदि उन्हें कोई सीन पसंद नहीं है तो वह उसे हटाने का निर्णय ले सकेंगी.

महेश भट्ट पहले गैंगस्टर में कंगना के रोल के लिए चित्रांगदा सिंह को लेना चाहते थे. कंगना की उम्र कम बताकर महेश भट्ट ने पहले उन्हें फिल्म में नहीं लिया. लेकिन बाद में चित्रांगदा के साथ बात नहीं बन सकी और इस तरह कंगना को करियर की पहली फिल्म मिल गई. फिल्म में कंगना का अभिनय अन्य कलाकारों के अभिनय पर भारी पड़ा. उन्होंने अपने इस रोल में जान फूंक दी. फिल्म समीक्षकों ने कंगना की तारीफ करते हुए लिखा कि बॉलीवुड को एक बेहतरीन अभिनेत्री मिल गई है. कंगना को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया था. इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म फैशन के लिए उन्हें सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया. क्वीन के बाद तो कंगना दर्शकों के दिलों की रानी बन गईं.

ऑज बॉलीवुड में यह स्थिति है कि कलाकार कंगना के साथ काम करने से पहले कई बार सोचते हैं. सबको इस बात का डर होता है कि कहीं कंगना फिल्म में उनका रोल न खा जायें. फिलहाल कंगना इरफान खान के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. शूटिंग के दौरान इरफान ने उनसे कहा कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी. इस बात को कंगना ने अपने लिए कॉम्पलीमेंट समझा कि इरफान उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं. सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कंगना मानती हैं कि उन्होंने अभी तक सफलता के शिखर को नहीं छुआ है. उनका मानना है कि मैं बॉलीवुड के लिए हमेशा आउटसाइडर रहूंगी. इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा. आज उनके लिए काम पाना स्ट्रगल नहीं है लेकिन एक समय ऐसा था जब काम पाना भी स्ट्रगल ही था. हालांकि स्ट्रगल आज भी है लेकिन वह दूसरे तरह का है. वैसे नहीं जैसे शुरूआती दौर में थे. करियर को लेकर कंगना का मानना है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने अब तक अपने करियर के टॉप को छुआ है यह मेरे करियर का पिनेकल पीरियड है. कंगना नंबर एक गेम से आगे का काम करना चाहती हैं वह अपनी जगह सुरक्षित करना चाहती हैं. वह मानती हैं कि नंबर वन का गेम उन लोगों के लिए है जिनकी कभी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, जो बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हों लेकिन वह सदाबहार बनना चाहती हैं.

आज कंगना एक बात बड़े गुमान के साथ कहती हैं कि मैंने ना शोज किए, ना अवार्ड फंक्शन्स में गई और ना ही शादियों में नाची. इसलिए कई बार मुझे दरकिनार कर दिया गया. इसी वजह से मुझे यहां तक पहुंचने में 10 साल लग गए. हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस तरह की चीजों की आदी नहीं है कि यहां लोग बिना किसी जाने पहचाने चेहरे के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. कंगना का बॉलीवुड में कोई गॉड फादर भले ही न रहा हो लेकिन उनके पास अपने काम को लेकर दीवानगी थी. कंगना अपने काम को लेकर फोकस्ड थीं. कंगना ने कभी भी बॉलीवुड की स्थापित परंपराओं का पालन नहीं किया. हर बार उन्होंने उन्हें चुनौती दी. उन्होंने न तो बॉलीवुड के पैरामीटर्स पर खरे उतरने वाले कपड़े पहने और न ही लोगों के साथ नेटवर्किंग की. उनके उच्चारण की और अंग्रेजी न बोल पाने की हमेशा आलोचना हुई, लेकिन अपनी एक्टिंग की काबीलियत और मेहनत के बल पर बॉलीवुड में ऐसी जगह बनाई है जिसकी लोग आने वाले सालों में मिसाल देंगे.■

कंगना बॉलीवुड में फिल्म हिट कराने की गारंटी बन गई हैं. फिल्मों को हिट कराने के लिए उन्हें किसी सुपरहिट को-एक्टर की जरूरत नहीं है. उन्हें अब फिल्म जगत में किसी मेल एक्टर से इंसेक्युरिटी नहीं है. बॉलीवुड में जिस मुकाम पर आज कंगना हैं वहां कुछ दिनों पहले तक डर्टी गर्ल विद्या बालन थीं. जिन्हें अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए अपने दमदार अभिनय और बेहतरीन पटकथा के अलावा और किसी चीज की दरकार नहीं थी. लेकिन विद्या की पिछली कुछ फिल्में असफल रही हैं, लेकिन कंगना सफलता की नित नई इबारत लिख रही हैं.

निर्माता नहीं बनना चाहतीं दीपिका पादुकोण

डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण का कहना है कि वह फिल्मों का निर्माण नहीं करना चाहती हैं. आज के दौर में अभिनेताओं की राह पर चलते हुए कई अभिनेत्रियां निर्माता बन चुकी हैं. इनमें लारा दत्ता, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं. प्रियंका चोपड़ा भी निर्माता बनने जा रही हैं, लेकिन दीपिका न निर्देशक बनना चाहती हैं और न ही निर्माता. दीपिका ने कहा कि मैं पिछले छह-सात साल से एक्टिंग सीख रही हूं, निर्देशक तो मैं नहीं बन सकती. निर्माता बन कर सिर्फ पैसा कमाने में नहीं जुट सकती. मैं तो केवल साइड के काम संभाल सकती हूं. जैसे, खाना खिलाना, चाय पिलाना, ऑफिस की देख-रेख आदि. यदि ऐसा कुछ हो तो कर सकती हूं. लाइन प्रोड्यूसर बन सकती हूं. मैं फाइलिंग, प्रिंटिंग, अकाउंट्स अच्छे से हैंडल कर सकती हूं बाकी कुछ नहीं. पैसों के मामले में मैं उलझूंगी नहीं क्योंकि पैसा मेरा नहीं है मैं तो लाइन प्रोड्यूसर हूं.■

मैं पिछले छह-सात साल से एक्टिंग सीख रही हूं, निर्देशक तो मैं नहीं बन सकती. निर्माता बन कर सिर्फ पैसा कमाने में भी नहीं जुट सकती. मैं तो केवल साइड के काम संभाल सकती हूं.

पीके ने चीन में मचाई धूम

अभिनेता आमिर खान अभिनीत फिल्म पीके ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड एक करोड पैंतीस लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की है. समीक्षकों का कहना है कि चीन बॉलीवुड से एक शानदार एवं मर्मस्पर्शी कॉमेडी फिल्म बनाना सीख सकता है. सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स केअनुसार राजकुमार हिरानी के निर्देशन वाली पीके ने 22 मई को चीन में रिलीज होने बाद से अब तक चीन की सबसे बड़ी फिल्म समीक्षक वेबसाइटों में से एक दोउबान पर 8.3 प्वाइंट स्कोर किए हैं. वर्ष 2009 में आमिर की 3 इडियट्स ने भी चीन में सफलता केझंडे गाड़े थे. और अब पीके ने नया इतिहास बनाया है. यह पिछले साल विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 70वीं फिल्म है. इसमें कहा गया है कि फिल्मकारों को पीके से सीखना चाहिए कि एक शानदार और मर्मस्पर्शी कॉमेडी फिल्म की कहानी को किस तरह कलात्मक तरीके से पेश किया जा सकता है. चीन में भारतीय फिल्मों का प्रचार करने वाली चीनी कंपनी स्ट्रैटजिक अलायंस में साझेदार प्रसाद शेट्टी ने कहा कि पीके ने गैर अंग्रेजी भाषी विदेशी फिल्मों की श्रेणी में एक करोड़ पैंतीस लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई कर रिकॉर्ड बनाया है. शेट्टी ने बताया कि यह किसी भी अन्य भारतीय फिल्म की कमाई से चार गुना ज्यादा है.■

डॉ. विद्या बालन

मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन को गुजरात की राय यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ आर्ट्स का खिताब दिया गया है. इस यूनिवर्सिटी ने विद्या बालन के नाम पर ही स्कॉलरशिप की योजना भी शुरू करने की बात की है, जिसका नाम विद्या बालन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप रखा गया है. इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. मुंबई के एक पांच सितारा होटल में आयोजित इवेंट के दौरान विद्या को इस खिताब से नवाजा गया और विद्या ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उनकी जिंदगी की एक इच्छा पूरी हो गई है. विद्या ने कहा कि, यह बहुत ही खुशी की बात है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं 10 जून को इंडस्ट्री में अपने 10 साल पूरे कर रही हूं और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है. यह एक अभिनेत्री के लिए बड़ा सम्मान है, जिसके द्वारा कई सारी जिंदगियों को छुआ जा सकता है. इवेंट के दौरान विद्या बालन के माता-पिता और सास-ससुर भी मौजूद थे. उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी इस सम्मान समारोह में शामिल हुए थे. विद्या ने इस मौके पर सिद्धार्थ की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप (सिद्धार्थ) मेरी जिंदगी में हमेशा रहेंगे. मैं भी आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी. इतना ही नहीं, विद्या ने इस दौरान यह भी कहा कि सिद्धार्थ के आने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार - झारखंड

15 जून -21 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सरोज सिंह

बिहार की चुनावी जंग में तरह-तरह के सियासी रंग दिखने लगे हैं. खासकर तालमेल और गठबंधन के इतने रंग शायद ही सूबे के लोगों ने कभी देखे हों. आखिर ऐसी क्या बात है इस बार कि तालमेल की गाड़ी लाख जतन के बावजूद अटकलों और कयासों की पटरी पर ही चल रही है और नेताओं के लाख प्रयास के बावजूद सही तस्वीर के साथ चुनावी जंग की गाड़ी पटरी पर नहीं दौड़ पा रही है. अगर एक लाइन में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करें तो वह लाइन यह है कि हम किसी से कम नहीं. सूबे की राजनीति को थोड़ा बहुत भी प्रभावित करने वाला हर छोटा बड़ा नेता यह मानकर चल रहा है 2015 के नवंबर में बनने वाली बिहार की नई सरकार उसकी और उसका साथ देने वाली पार्टियों की ही होगी. अगर कोई भी उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा तो गलती ही नहीं महागलती करेगा और चुनावी जंग में उसकी हार होनी सौ फीसदी तय है. सूबे में तालमेल का खाका इसी महादावे की पृष्ठभूमि में खींचा जा रहा है और यही वजह है कि धरातल पर कोई बात सामने नहीं आ रही है. बात बनते-बनते बिगड़ जा रही है और एक बार फिर नए सिरे से नए साथियों की तलाश शुरू हो जा रही है. तालमेल बने न बने पर इससे राजनीतिक गलियारों से लेकर चाय व पान दुकानों में चर्चा के लिए रोज एक नई सुर्खी तो इन दिनों मिल ही जा रही है. इस संदर्भ में पहले कुछ बातें मौटे तौर पर बड़ी पार्टियों की करते हैं. जदयू की पहली प्राथमिकता राजद व कांग्रेस हैं. अगर यह न हो तो फिर जदयू का प्रयास कांग्रेस के साथ पप्पू यादव को साथ लाने का है. राजद की चाहत है कि दूसरे विकल्प के तौर पर जीतनराम मांझी और कांग्रेस के साथ तालमेल हो जाए. भाजपा चाहती है कि लोजपा और रालोसपा के अलावा मांझी और पप्पू उनके खेमे में आ जाएं. लेकिन हर चाहत अधूरी रह जा रही है क्योंकि इस बार छोटे दलों ने भी ठान लिया है कि तालमेल अगर होगा तो हमारी शर्तों पर नहीं तो फिर सूबे में एक नई राजनीति का आग़ाज़ कर देंगे. यही वजह है कि जीतनराम मांझी की पार्टी हम, पप्पू यादव का जनाधिकार मोर्चा, संजय वर्मा की नेशनल पीपुल्स पार्टी, मायावती की बसपा, आनंद मोहन की बीपीपा और नागमणि की समरस समाज पार्टी अभी वेट एंड वाच की भूमिका में है. जिस दिन इन दलों को यह आभास हो जाएगा कि बड़े दलों में इनकी दाल नहीं गलने वाली तो उसी दिन से यह छोटी पार्टियां अपने आप को एक प्लेटफार्म में लाकर चुनावी जंग का शंखनाद कर देंगी. जानकार सूत्र बताते हैं कि इन दलों के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सीटों के बंटवारे का फार्मूला भी इन्होंने तैयार कर लिया है. पप्पू यादव और जीतनराम मांझी के बीच बातचीत तो पहले से ही चल रही थी. नेशनल पीपुल्स पार्टी के बिहार प्रमुख संजय वर्मा ने इसको विस्तार देते हुए बसपा और बीपीपा नेताओं से भी बात की और एक छतरी में आने के लिए लगभग तैयार कर लिया. गौरतलब है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी की भी एनडीए से तालमेल पर बातचीत चल रही है. पार्टी ने 17 सीटों का दावा ठोंका है. दीघा, राघोपुर, पीपरा, छातापुर, बेलसंड, कुर्था, हरलाखी, झंझारपुर, बड़हिया, कुढ़नी, समस्तीपुर, बाजपट्टी, लालगंज, धमधाहा और बहादुरगंज की सीटों पर नेशनल पीपुल्स पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है. संजय वर्मा को उम्मीद है कि भाजपा नेतृत्व उनकी मांगों पर विचार करते हुए जल्द ही फैसला लेगा. सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने भले ही 17 सीटों पर दावा ठोंका है पर पांच सीटों के लिए वह अड़ी हुई है. इनमें दीघा, छातापुर और पीपरा, बेलसंड और राघोपुर की सीट शामिल हैं. संजय वर्मा कहते हैं कि नेशनल पीपुल्स पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी जंग में कूदेगी और भारी जीत दर्ज करेगी. संजय के अनुसार बिहार की राजनीति में किसी को बनाने या बिगाड़ने की ताकत नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास है. संगमा साहब के नेतृत्व में हमारी पार्टी बिहार को सुशासन और विकास देने के लिए संकल्पित है.

नागमणि की समरस समाज पार्टी भी इस खेमे में शामिल होने के लिए तैयार हो गई है. नागमणि का दावा है कि उनका गठबंधन सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और अपनी सरकार बनाएगा. नागमणि ने साफ किया कि लालू और नीतीश का फेज अब खत्म हो गया है इसलिए जनता नए विकल्प की तलाश में है. हमारा प्रयास है कि तीसरी ताकत इस कमी को पूरा करे.

बसपा के पास बिहार में खोने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए वह चाहती है कि इस चुनाव में वह एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा बने जिसमें उसको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले और पार्टी को मजबूती मिले. छोटे दलों का यह मोर्चा अगर अस्तित्व में आता है तो यह तय है कि बड़े दलों के लिए भारी परेशानी पैदा होगी. ऐसा इसलिए कि यह मोर्चा अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही जातियों में अपनी दखल देगा और अब तक जो बड़ी पार्टियां यह मानकर चल रही है कि फलां वोट मेरा ही है, उसमें सेंध लग जाएगी. सूत्रों पर भरोसा करें तो यह मोर्चा जीतनराम मांझी को नेता मानकर चुनावी अखाड़े में उतरेगा. हालांकि नागमणि ने अभी जीतनराम मांझी के नाम को हरी झंडी नहीं दी है. लेकिन यहां यह बात गौरतलब है कि छोटे दलों का यह मोर्चा तभी अस्तित्व में आएगा जब बड़ी पार्टियां इनको ना कह देगी. यह तय है कि जीतनराम मांझी की पहली प्राथमिकता भाजपा और दूसरी राजद है. अगर इन दोनों से निराशा हाथ लगेगी तभी मांझी तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करेंगे. यही हाल पप्पू यादव का भी है. भाजपा और जदयू उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर तीसरी ताकत को मजबूत करने के लिए वह पूरी शक्ति लगा देंगे. इसलिए कहा जा सकता है कि छोटे मियां अभी इंतजार के मूड में हैं. लेकिन अगर इंतजार खत्म हुआ तो इनका एक्शन भी काफी दिलचस्प होगा.■

साथ आ सकते हैं आनंद मोहन और पप्पू यादव !

कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस खेल में सारे विकल्प हमेशा खुले रहते हैं. जब भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक मंच पर आए तो लोगों ने इसी जुमले को याद किया. अब एक बार फिर किसी जमाने में एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच नजदीकियां बढ़ने की चर्चा है. यह चर्चा अगर हकीकत में बदलती है तो तय है कोशी की राजनीति में भारी भूचाल आ जाएगा. आनंद मोहन और पप्पू यादव की मिलीजुली ताकत इस इलाके में कई दिग्गजों के समीकरण खराब कर सकती है. बताया जाता है कि अभी इन दोनों के मिलने पर कोई फैसला तो नहीं हुआ पर नुमाइंदों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत सकारात्मक हुई है. हालांकि दोनों ही दलों के लोग फिलहाल इस तरह की संभावना से इनकार कर रहे हैं. इस बीच बिहार पीपुल्स पार्टी सूबे के चुनाव में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी शुरू कर दी है. गौरतलब है की 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना आनंद मोहन के नेतृत्व में हुई थी.1995 में युवा आनंद मोहन में भावी मुख्यमंत्री देख रहा था. 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था. आनंद मोहन 1996 और 1998 में दो बार शिवहर से सांसद रहे. जल्द ही पार्टी पटना में एक बड़ा आयोजन कर अपनी भावी राजनीति का खुलासा करने वाली है. बीपीपा से जुड़े नेताओं का मानना है कि बिहार में अभी राजनीतिक दिवालियेपन की स्थिति है ऐसे में बीपीपा सूबे के लोगों को एक बेहतर विकल्प दे सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

बिहार में होगी भाजपा सरकार

किशनगंज के टाउन हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय कार्यशाला की बैठक हुई. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश क्रीड़ा मंच के उपाध्यक्ष वरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में काफी सराहनीय काम किया है. जिससे भारत की नींव मजबूत हुई है. प्रधानमंत्री के सफल विदेश नीति से विश्व पटल पर भारत सम्मान बढ़ा है. डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, युवा आयोग की नीति बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार से जंगल राज खत्म होगा. और भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी. इस कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अमित सिन्हा ने किया जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गौतम पोद्दार ने की. कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य ज्योति कुमार सोनू, जिला महामंत्री अरविंद गुप्ता, जिला मंत्री नोगेन राय, मंडल अध्यक्ष अभिजीत चंद्रा, सूरज तिवारी, रोहित बल, भाजपा नेता राजेश्वर चौधरी, बसंत सिन्हा, ज्यानेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष विक्रम पासवान, धीरज सिन्हा, आदर्श कुमार, अजीत दास, रातीराम स्वर्णकार, छवि लाल सिंह, विपिन घोष, कालू सरकार, शकील अख्तर राही, पांडव महतो, उत्तम मावाकार, विनोद महल, धनंजय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे. **- भारती**

सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीआर

जनता दल राष्ट्रवादी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मो. शमीम आलम ने प्रेस कांफ्रेस में यह बात कही है. आलम के मुताबिक पार्टी अपने ही दम पर चुनाव लड़ेगी. चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी सरकार बनाने में सशक्त भूमिका में होगी. उन्होंने कहा की पार्टी बिहार में किसानों, महिलाओं, युवाओं और बेरोज-गारों को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर जनता के बीच जाएगी साथ ही शिक्षा के बिगड़ते स्तर पर उन्होंने कहा की राज्य के हर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा का कानून बनाया जाएगा. आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए भी पार्टी कदम उठाएगी. ऐसा कानून बनाया जाएगा, जिससे कि हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके. प्रेस कांफ्रेस में प्रदेश प्रवक्ता रंजय कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. शफीकुल रहमान, और अन्य लोग भी मौजूद थे. **- रजनीकांत पांडेय**

सम्राट अशोक की जयंती मनेगी

सम्राट अशोक फाउंडेशन की ओर से बिहार में महान सम्राट अशोक की जयंती 15 जून को मनायी जायेगी. फाउंडेशन इस बार जयंती को भव्य और आकर्षक रूप देने की तैयारी में है. सम्राट अशोक फाउंडेशन के अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा (पप्पू) ने बताया की बिहार के करीब 30 जिलों में 15 जून से 20 अगस्त तक में गांव-गांव जाकर सभा और कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. इस प्रोग्राम की शुरुआत हाजीपुर से होगी. अध्यक्ष कुशवाहा ने बताया की इसके बाद 20 अगस्त को पटना के रविन्द्र भवन में कार्यक्रम का समापन होगा. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता छगन भुजबल होंगे. इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी उपस्थित होंगे. **- रजनीकान्त पांडेय**

Enjoy with Nature MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

पेट दर्द और गर्मी का मौसम
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. आलोक कुमार
Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethicone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Ornidazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylcobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma
- रजनीकान्त पाण्डेय

गया

ये साजिश है या कुछ और

सुरेश चौहान

गया जिला जदयू अध्यक्ष अभय कुशवाहा के घर पार्सल बम विस्फोट ने मगध के राजनीतिक हलकों में हलचल और दहशत पैदा कर दी है. बिहार में किसी नेता के घर पार्सल बम विस्फोट की यह पहली घटना है. इसमें जिला जदयू अध्यक्ष के समर्थक संतोष की मौत हो गयी तो एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गये. ऐसे तो बिहार में राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बाद बिहार की राजनीति में हिंसा की शुरुआत भी करीब सदी तीन दशक पूर्व हो गयी थी. इसके बाद ही बिहार की राजनीति में दबंगों, माफियाओं, अन्दर बल्वे के सरगनाओं का दबदबा बढ़ता चला गया. तब से बिहार की राजनीति भी जनभावना से दूर मतलब की रह गयी. फलत: अच्छे लोग राजनीति से दूर होने लगे और जो अच्छे लोग राजनीति में आये, उन्हें तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. गया जिला जदयू अध्यक्ष के घर पार्सल बम विस्फोट राजनीति के किस रूप का हिस्सा है, पुलिस इसी की जांच में जुटी है. फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाया है. ऐसे पुलिस इस मामले को सुलझाने का दावा कर रही है. जिला जदयू अध्यक्ष अभय कुशवाहा कह चुके हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है. पुलिस को जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कोई निर्दोष फंस जाये. लेकिन पुलिस को कहना है कि आखिर जिला जदयू अध्यक्ष के घर 26 मई 2015 की सुबह पार्सल बम रखने वाला या भेजने वाला का कोई तो मकसद होगा?

सुबह-सुबह जिला जदयू अध्यक्ष के घर के दरवाजे पर जब अचानक पार्सल पैकेट को देखा गया और इस पैकेट में बम जैसा कुछ लगा तब जाकर संतोष उसे फेंकने क्यों जा रहा था? घर वालों ने इसे हल्के में क्यों लिया? जब तक अभय कुशवाहा के साले जयहिन्द संतोष को उस पार्सल पैकेट को फेंकने से मना कर रहा था कि तब तक बम फट गया और संतोष की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी और जयहिन्द घायल हो गया. गया जिला जदयू अध्यक्ष के घर बम विस्फोट की घटना की सूचना मिलते ही पूरे गया जिले में सनसनी फैल गयी. जिले में हर कोई तरह-तरह की बातें करने लगा. लेकिन पुलिस अपने हिसाब से सारी आशंकाओं को ध्यान में रखकर जांच करने में जुटी है. ऐसे कई तो अभय कुशवाहा की छवि कोई दबंग वाली नहीं रही है. एक युवा व तेज तर्रार मुखिया से वह राजनीति में आये. गया शहर विधान सभा क्षेत्र से भी इन पर हुए. इस पर अभय कुशवाहा का कहना है कि ये सभी मामले समाज सेवा के कारण हुए थे और आज की तारीख में वो सभी मामले में बरी हो चुके हैं. पुलिस समझ नहीं पा रही है कि आखिर गया जिला जदयू अध्यक्ष के घर पार्सल बम रिस्फोट किसी तरह की साजिश है या कुछ और है.

निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और बाद में जदयू में शामिल हो गए. फिर वो जिला जदयू के अध्यक्ष बने. उनका कारोबार भी पुश्तैनी है जो खेती बाड़ी के अलावा ईंट-भट्ठा तथा फिल्टर्ड वाटर प्लांट का है. इसके अलावा वे जमीन की खरीद-बिक्री का भी धंधा करते रहे हैं. लेकिन इन सब धंधों में भी दबंगई की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. हां यह हो सकता है कि अपने घर के पंचायत कुजापी में मुखिया होने के नाते कुछ वार्ते होती होंगी, जिसे उनके विरोधियों द्वारा प्रचारित भी किया जाता होगा. इसी में कुछ मुकदमे भी इन पर हुए. इस पर अभय कुशवाहा का कहना है कि ये सभी मामले समाज सेवा के कारण हुए थे और आज की तारीख में वो सभी मामले में बरी हो चुके हैं. पुलिस समझ नहीं पा रही है कि आखिर गया जिला जदयू अध्यक्ष के घर पार्सल बम रिस्फोट किसी तरह की साजिश है या कुछ और.

बिहार विधान सभा चुनाव भी निकट आता जा रहा है. मगध के नव पदस्थापित डीआईजी शालिन और गया के सिनियर एसपी मनु महाराज गया शहर के तथाकथित सफेदपोशों, छुटभैयों, राजनीतिज्ञों तथा अन्य कई व्यक्तियों को बेमतलब सरकारी अंगरक्षक रखे जाने की समीक्षा कर वापस लेने की कवायद कर रहे हैं. कई तो दो-तीन-तीन अंगरक्षक रखे हुए हैं स्टेटस के लिए. ऐसे कई सवाल हैं, जो गया शहर के लोगों की जुबान पर है. ऐसे अभय कुशवाहा सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष हैं, इस नाते तो उन्हें अंगरक्षक की जरूरत तो थी और है भी. अब तो इनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गयी है. लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिलना चिंता का विषय है. फिलहाल इस घटना के लिए एक आई टी का गठन कर जांच किया जा रहा है. गया के सीनियर एसपी मनु महाराज खुद इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय में दम ठोंकने को तैयार महिला नेत्रियां

सुरेश चौहान/संदीप कुमार

हम किसी से कम नहीं, हमें भी विधानपालिका में भागीदारी चाहिए. आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए बेगूसराय की महिला नेत्रियां कुछ इसी लहजे में अपने पार्टी आलाकमान के सामने दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं. कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, राजद, जदयू, रालोसपा आदि की ये नेत्रियां राजनीति में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं. जिले की नेत्रियों की राजनीति में गहरी पैठ पूर्व से ही कायम है. श्रीमति कृष्णा शाही एवं श्रीमति चंद्रभनु देवी जिले के बेगूसराय एवं बलिया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. कांग्रेस पार्टी की इन दोनों सांसदों में श्रीमति कृष्णा शाही तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान प्राप्त कर चुकी हैं. आपातकाल के बाद हुए संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक सांसद कृष्णा शाही बेगूसराय से ही विजयी हुई थीं. इससे पता चलता है कि बेगूसराय कांग्रेस पार्टी का कितना मजबूत किला था. पूर्व सांसद स्व. चन्द्रभानु देवी की पुत्री श्रीमती अमिता भूषण वर्तमान में कांग्रेस महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष हैं.

भाकपा की श्रीमति शकुन्तला सिन्हा जिले के बरौनी (अब तेघड़ा) विधान सभा क्षेत्र से प्रथम महिला विधायक निर्वाचित हुईं. भाकपा की ही श्रीमति ऊषा सहनी स्थानीय निकाय चुनाव क्षेत्र बेगूसराय-खगड़िया से विधान पार्षद निर्वाचित हो चुकी हैं. जदयू की श्रीमति परवीन अमानुल्लाह जिले के साहेबपुर कमाल विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होकर नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त कर चुकी हैं. वर्तमान में जदयू की श्रीमति मंजू वर्मा जिले के चेरियाबरियरपुर विधान सभा क्षेत्र की विधायक हैं. उपरोक्त नेत्रियों से प्रभावित जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों की नेत्रियां आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रही हैं. आगामी विधान सभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से श्रीमति अमिता भूषण एवं श्रीमती शांति स्वामी प्रत्याशी बनने की प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं. अमिता भूषण को राजनीति विरासत में मिली है. वे पूर्व सांसद स्व. चन्द्रभानु देवी की पुत्री हैं. लोक सभा चुनाव में वे बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं. पार्टी संगठन में वे प्रदेश महासचिव पद पर कार्य कर चुकी हैं. संप्रति अमिता भूषण कांग्रेस महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष हैं. इसके साथ ही वे कई अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों से भी जुड़ी हैं. अमिता भूषण समर्पित एवं निष्ठावान कांग्रेसी हैं. श्रीमती शांति स्वामी लंबे समय तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं. गत विधान सभा चुनाव में बेगूसराय विधान सभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं. शांति स्वामी भी कर्मठ, समर्पित एंव निष्ठावान कांग्रेसी हैं. भाकपा की श्रीमति सहनी को पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनाया है. जदयू की श्रीमति मंजू वर्मा चेरियाबरियारपुर विधान सभा क्षेत्र की विधायक हैं. पार्टी की विभिन्न आनुशांगिक इकाइयों की पदधारक महिलाएं पुरजोर ढंग से पार्टी आलाकमान के सामने अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं. भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष इन्दू मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष आभा सिंह, भाजपा की जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर आशा सिन्हा, भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय प्रभारी एवं नगर पार्षद अनिता राय, भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री पूनम देवी, जिला उपाध्यक्ष सुजाता मिश्रा, रंजना मिश्रा आदि अगामी विधान सभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने के लिए सशक्त दावेदारी पेश कर रही हैं. ये सभी भाजपा के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान हैं. राजद की प्रदेश महासचिव उर्मिला ठाकुर एवं क्रांति सिंह भी पार्टी प्रत्यशी की प्रमुख दावेदार हैं. रालोसपा की प्रदेश महासचिव संजू प्रिया भी प्रबल दावेदार हैं और पार्टी आलाकमान पर प्रत्याशी बनाए जाने का दबाव बनाये हुए हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

देवघर में स्टेडियम निर्माण अधर में

रणजीत झा

देवघर जिले में विभागों के अभियंता सरकारी राशि का जमकर दुरूपयोग कर रहे हैं. यह प्रक्रिया विभागों के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है. निविदा में वर्तमान लागत को ध्यान में रखकर एक आकलन बनाया जाता है और इसमें कार्य पूरा करने की समय सीमा होती है परन्तु आज शायद ही कहीं तय समय सीमा में काम पूरा हो रहा है, इसका कारण है कि जानबूझ कर समय सीमा में काम पूरा नहीं करके संवेदक पुर्नप्राक्कलन का दावा कर मनचाही राशि प्राप्त कर रहे हैं. तय समय सीमा में काम पूरा करने की बाध्यता व शर्तो की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है. निविदा कार्य को 75 प्रतिशत काम पूरा करके निर्धारित समय सीमा पार करते ही पुर्नप्राक्कलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है. ऐसे ही मामले का प्रत्यक्ष गवाह है जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत 85 लाख की लागत से बना प्रखंड स्तरीय खेलकूद स्टेडियम निर्माण कार्य. सहज ही देख सकते हैं कि स्टेडियम बनकर तैयार है सिर्फ मैदान समतलीकरण के कारण हैंडओवर नहीं किया गया. देखने से साफ लगता है कि यह सब जानबूझ कर ही किया गया है. स्टेडियम निर्माण कार्य एनआरईपी विभाग से कनीय अभियंता के जिम्मे ही हो रहा है. हालत यह है कि इतने लंबे समय तक काम पूरा नहीं होने के कारण व वीरान जगह पर होने के कारण अब चोरों ने मेन गेट व ग्रिल चुराने का काम प्रारंभ कर दिया है. पूरे स्टेडियम परिसर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है. यदि यही हाल कुछ और दिन रहा तो शायद दरवाजे, खिड़की आदि भी नहीं बच पाएगा. इसके बाद फिर इसके लिए सरकारी राशि की मांग होगी. सवाल है कि स्टेडियम पूरी तरह बनकर जिला प्रशासन को हैंडओवर भी नहीं हुआ और सामान गायब होने पर फिर खरीदने की नौबत आ गई. इन सब में कनीय अभियंता की घोर लापरवाही, सरकारी राशि का दुरूपयोग व लूट का मामला बनता दिख रहा है. एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता जनार्दन चौधरी जल्द ही पुर्नप्राक्कलन बनाकर काम पूरा करने की बात कहते हैं. इनके जबाब में कहीं भी सरकारी राशि के दुरूपयोग होने की गंभीरता नहीं दिखी. ऐसे बंदरबांट, राशी के दुरूपयोग व लूट के खेल के कारण ही झारखंड की हालत बदतर होती जा रही है. इसमें सब सेटिंग का खेल हो रहा है. इस प्रकार का मामला सिर्फ एनआरईपी विभाग में ही नहीं है, लगभग सभी विभागों में यह खेल बदस्तूर चल रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढी

समाहरणालय गोलीकांड : जेल की सलाखों में पहुंचे 15 आंदोलनकारी

लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना-प्रदर्शन, सत्याग्रह, उपवास, सड़क जाम जैसे न जाने कितने उपाय किये गये हैं, जिनकी बदौलत देश में विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अनेको बार शासन से लेकर प्रशासन तक को झुकने के लिए बाध्य किया है. परंतु सीतामढ़ी जिले के एक आंदोलन ने 17 साल की इंतजार के बाद 15 राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ताओं को सलाखों में पहुचा दिया है. स्थानीय न्यायालय के इस फैसला ने नेपाल के विनाशकारी भूकंप को भी काफी पीछे छोड़ दिया है. फिलहाल सीतामढ़ी व शिवहर जिले की राजनीति में न्यायालय के फैसले से राजनीतिक भूकंप का आगमन हो गया है. बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने समेत 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पूर्व सांसद नवल किशोर राय, शिवहर के पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक, सोनबरसा के भाजपा विधायक राम नरेश प्रसाद यादव, शिवहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मो. असद व रालोसपा के सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष राम लक्षण सिंह कुशवाहा समेत 15 नेताओं को मंडलकारा सीतामढ़ी की यात्रा करनी पडी है .....

वाल्मीकि कुमार

11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी समाहरणालय पर हजारों की संख्या में जिले के बाढ़ पीड़ितों ने प्रदर्शन किया था. उस वक्त प्रदर्शन के नेतृत्व का कमान तत्कालीन पुपरी के विधायक नवल किशोर राय ने थामी थी. 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीतामढ़ी समाहरणालय पर प्रदर्शन के क्रम में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं कि जिला प्रशासन के सारथी तत्कालीन डीएम रामनंदन प्रसाद व एसपी डॉ परेश सक्सेना को भीड़ पर काबू पाने के लिए 17 चक्र गोलियां चलाने का आदेश देना पड़ा था. घटना में एक पूर्व विधायक समेत 5 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए थे. मामले को लेकर आंदोलनकारी व जिला प्रशासन की ओर से अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया गया था. प्रशासन की ओर से तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी डीके वर्मा के बयान पर डुमरा थाना में एक प्राथमिकी कांड संख्या- 111/98 दर्ज करायी गयी थी, जिसमें करीब 5 दर्जन से अधिक लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों के परिजनों की ओर से न्यायालय में चार अलग-अलग मुकदमा दायर कर तत्कालीन डीएम रामनंदन प्रसाद, एसपी डॉ परेश सक्सेना, प्रभारी सदर डीएसपी मदन मोहन लाल, कार्यपालक दंडाधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा, समाहर्ता के निजी सहायक विनोद कुमार, नगर थाना के सअनि रंजीत कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपित करते हुए न्याय की गुहार लगायी गयी थी. बताया जाता है कि यह मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है.

तकरीबन 17 साल बाद 02 जून 2015 को सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. इरशाद अली की अदालत में मामले की सुनवाई के बाद पूर्व सांसद नवल किशोर राय, पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक, भाजपा विधायक राम नरेश प्रसाद यादव, शिवहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मो. असद, राजद नेता मनोज कुमार, जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह चुम्मन, भाकपा नेता विश्वनाथ बुंदेला, रालोसपा जिलाध्यक्ष राम लक्षण सिंह कुशवाहा, रालोसपा नेता मोहन कुमार सिंह, पूर्व मुखिया महेंद्र यादव, पूर्व जिला पार्षद कौशल किशोर राय, मदन राय, विनोद प्रसाद, विपीन बिहारी यादव व सिपाही सूर्यदेव राय को मामले में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया. इसके साथ ही सीतामढ़ी व शिवहर जिले की राजनीति में एक भूचाल आ गया है. तकरीबन सभी राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता के बीच यह चर्चा का विषय बना है. चर्चा चल रही है कि अब लोकतांत्रिक तरीके से भी कोई सरकार व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का हिम्मत न करे इसी मंशा के तहत मुकदमे को जटिल बना कर ऐसी नौबत खड़ी कर दी गयी है. सच्चाई इस बात में कितनी है यह कहना मुश्किल है, परंतु न्यायालय के इस फैसला के बाद दोनों ही जिले की राजनीति में सक्रिय नेता से लेकर कार्यकर्ता तक फिलहाल परेशान होकर रह गये हैं.

अब साल 1998 के इस चर्चित मामले की तह में पहुचने का प्रयास करना चाहिए. एक ओर जहां प्रशासनिक अमला गोलीकांड के लिए सीधे तौर पर आंदोलनकारी को दोषी बताते रहे हैं, वहीं आंदोलनकारी प्रशासनिक दलील को खुद को बचाने का षड्यंत्र करार दे रहे है. साथ ही माननीय उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाने की सोच रहे हैं. आंदोलन के सेनापति रहे पुपरी के तत्कालीन विधायक सह पूर्व सांसद नवल किशोर राय द्वारा पूर्व में घटना को लेकर किये गये चर्चा पर यकीन करें तो समाहरणालय के समीप हुई घटना प्रशासनिक चूक व जल्दबाजी में लिये गये निर्णय की देन है. 11 अगस्त 1998 के इस चर्चित आंदोलन को करीब से जानने वालों की माने तो तत्कालीन जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, जनसमस्याओं के सवाल पर अगस्त क्रांति के अवसर पर 09 अगस्त से 14 अगस्त 1998 तक राज्य व्यापी धरना-प्रदर्शन का आयोजन सूबे के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किया जाना था. इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले में प्रदर्शन की तिथि 11 अगस्त 1998 निर्धारित की गयी थी. कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिले के अलग-अलग प्रखंडो में बैठक का दौर जारी था. परंतु जिला प्रशासन ने आंदोलन की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं किया. बाढ़ व सुखे से परेशान हाल हजारों लोगों ने निर्धारित तिथि को सीतामढ़ी गांधी मैदान से बाढ़ पीड़ितों को राहत दो का नारा बुलंद करते जिला मुख्यालय डुमरा स्थित समाहरणालय के समीप प्रदर्शन के लिए पहुंचे. जहां प्रशासनिक स्तर पर मुक्कमल सुरक्षा इंतजाम कार्यक्रम की सूचना के बाद भी नहीं किये गये थे. बताया जाता है कि जिला प्रशासन के आलाधिकारियों ने आंदोलन के संबंध में सरकार के तत्कालीन मुखिया से बात की और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग शुरू कर दिया. प्रशासनिक स्तर पर की गयी लाठी-गोली की बौछार से पूर्व विधायक राम चरित्र राय यादव, पूर्व मुखिया सह जिला जनता दल के उपाध्यक्ष मो अयूब, जनता दल नेता महंत मंडल व मुनीफ नदाफ के अलावा सीपीएम कार्यकर्ता रामपरी देवी की मौत हो गयी. जबकि सीपीएम की मंजू देवी, हीरालाल साह व मोहन साह समेत दर्जनों कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गये थे. घटना के बाद पुलिस ने राजद नेता मनोज कुमार को पकड़ कर ऐसा हाल कर दिया कि सदमे से इनके पिता का देहांत तक हो गया. बाद में पुलिस हिरासत में रहते हुए मनोज ने पिता का अंतिम संस्कार किया था. बताया जाता है कि आंदोलन के दौरान घटी इस घटना के बाद गणेश प्रसाद यादव, शरद यादव, राम बिलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, रघुनाथ झा व नीतीश कुमार ने चार दिनों तक घटना के विरोध में सीतामढ़ी गांधी मैदान में आमरण अनशन किया था. साल 2009 में तत्कालीन एनडीए की सरकार में पूर्व सांसद नवल किशोर राय की पहल पर सरकारी स्तर पर मुकदमा उठाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से ऐसा नहीं हो सका और मामला माननीय उच्च न्यायालय के अधीन चला गया. इसी बीच मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया गया. नौकरी देने की घोषणा के बाद तीन लोगों को नौकरी दी भी गयी, लेकिन बाद में मृतकों के शहीद की श्रेणी में नहीं होने का हवाला देकर पुन: नौकरी वापस ले ली गयी. समाहरणालय गोलीकांड के बाद प्रति वर्ष 11 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में पूर्व सांसद नवल किशोर राय की अगुआई में शहादत दिवस 12 सालों तक लगातार मनाया गया. उन दिनों मामले की कानूनी लड़ाई की कमान मोहन कुमार सिंह, अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद गुप्ता व रघुनाथ यादव ने संभाली थी. चल रही चर्चाओं पर यकीन करे तो 1998 के 16 सूत्रीय मांगों के शेष मांगों की चिंगारी अब तक सीतामढी में सुलग रही थी, जो फिलहाल न्यायालय के फैसले के बाद मद्धम पड़ने लगी है. हालांकि न्यायालय परिसर से जीवन में पहली बार जेल जाने के क्रम में नवल किशोर राय जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कार्यकर्ताओं को पूर्व सांसद श्री राय ने पुन: आंदोलन का भरोसा दिलाया, जाते-जाते कहा - कुछ इंतजार करें. अब देखना है कि जनसमस्याओं के निदान को लेकर संघर्ष करने वाले नेताओं को पुन: आंदोलन का मौका मिलता है अथवा आंदोलन की परिपाटी पर विराम लगता है. फिलहाल सभी की नजर माननीय इच्च न्यायालय की चौखट पर टिकी है. वैसे इस फैसला ने सीतामढी की राजनीति से फिलहाल जात-पात व धर्म-मजहब को किनारा कर दिया है.

न्यायालय परिसर में विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, राजद के पूर्व सांसद सीताराम यादव, भाजपा नेता प्रो उमेशचंद्र झा, अरुण कुमार गोप, राजद जिलाध्यक्ष मो शफीक खां, प्रदेश युवा राजद उपाध्यक्ष दिलीप राय, तारकेश्वर प्रसाद यादव, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सीत-राम झा, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मो. मोबिनुलहक, अंजारूल हक तौहिद, जदयू नेता भरत प्रसाद, संजय सिंह, दिनेश प्रसाद यादव, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा समेत अन्य ने स्थानीय न्यायालय के फैसला का सम्मान करते हुए दोषी करार दिये गये साथियों से मिल कर अगली अदालत से पूर्ण न्याय की उम्मीद जतायी. साथ ही जन समस्याओं के सवाल पर आंदोलन के क्रम को जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

थुम्मा गांव को लिया गोद

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के थुम्मा गांव में विकास का प्रवाह होगा. पिछले दिनों थुम्मा हाई स्कूल परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मुखिया मीरा देवी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बैठक में बताया गया कि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना की ओर से थुम्मा गाव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चयनित किया गया है. संस्थान द्धारा रॉबर्ट बोस्थ जीएमबीएच नामक मल्टी नेशनल जर्मन संस्थान व भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से गांव को आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में विकसित करने का लक्ष्य है. कार्यक्रम में संस्थान के डीन प्रो डॉ के बाल कृष्णन, बीडीओ नीरज आनंद, प्रभारी सीडीपीओ बबिता कुमारी, एसडीओ विद्युत निलेश कुमार, सीओ मृत्युंजय कुमार, डॉ अनिल कुमार, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान, प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश कुमार, प्रफुल्ल कुमार चौधरी, सुजीत कुमार झा, विजय कुमार सिन्हा, अभिनव कुमार, अमित कुमार झा, नीतीन कुमार, बीईओ बालेश्वर चौधरी समेत अन्य थे. **- विभा**

सामूहिक विवाह सम्पन्न

जन कल्याण सांस्कृतिक कला केन्द्र द्धारा सुगौली के स्टेडियम में 18 वर-वधुओं का सामूहिक विवाह हुआ. हजारों की भीड़ इस अनोखे विवाह की गवाह बनी और मधुर गाने व समाज सेवियों के बीच 18 जोड़ियो ने सात फेरे लेकर एक दूजे के लिए दाम्प्त्य सूत्र में बंध गये. यहां हिन्दू रीति रिवाज व मुस्लिम रीति रिवाज से एक साथ निकाह तथा विवाह के रस्मों को पूरा किया गया. इस मौके पर संबोधित करते हुए आयोजक जन कल्याण सांस्कृतिक कला केन्द्र के सचिव सुनील सारंग ने कहा कि इस आयोजन में आप सभी का परस्पर सहयोग से पूरा हो पाया. मंच पर विवाह के गीत की धुन पर उपस्थित समूह ने थिरकते हुए वधुओं का स्वागत किया. मौके पर मौजूद प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. रिचा भारद्धाज ने इस कार्य में अपना भरपूर सहयोग दिया और कहा कि इस तरह के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत है. मौके पर आयोजन समिति के अवधेश गुप्ता,अशोक कुमार सोनी,वार्ड पार्षद उपेन्द्र सहनी, अनिरुद्ध यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे.

कोषागार कार्यालय का उद्घाटन

पूर्वी चम्पारण के जिला पदाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव ने ढाका में बिहार का 47 वें कोषागार का उद्घाटन सिकरहना अनुमंडल कार्यालय के नव निर्मित भवन में किया. इस अवसर पर डीएम श्रीवास्तव ने कहा कि कोषागार की स्थापना से सिकरहना अनुमंडल के विभिन्न सरकारी विभाग को काफी फायदा होगा और मोतिहारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. शिक्षा, बाल विकास परियोजना विभाग, निबंधन कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत, अंचल कार्यालय, प्रखण्ड कार्यालय सहित 44 डीडीओ इस कोषागार से जुड़ गया है. डीएम श्रीवास्तव ने कहा कि सिकरहना अनुमंडल मुख्यालय में शीघ्र ही व्यवहार न्यायालय को चालू कराया जायेगा. उक्त अवसर पर चिरैया विधायक लक्ष्मीनारायण यादव एवं ढाका विधायक पवन जायसवाल, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आईएस जगदीश सोनंकर मौजूद रहे. उद्घाटन की सभा का संचालन एसडीओ मनोज कुमार रजक ने किया. मौके पर प्रशिक्षु आईएस व बीडीओ राघवेन्द्र सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी विनय चन्द्र झा, डीएसपी उमेश्वर चौधरी, अनुमंडल कोषागार पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, सीओ पंकज कुमार झा,एसबीआई ढाका के शाखा प्रबंधक रविशंकर सिंह सहित कई गणमन्य लोग मौजूद रहे.■ **- इन्तेजारूल हक**

एक नज़र

फेल हैं कुम्हरार विधायक : ब्रजेश

पहली जून को कुम्हरार विधानसभा बचाओ मोर्चा ने शुद्ध पानी और जलजमाव के मसले पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया. कुम्हरार विधानसभा बचाओ मोर्चा के संयोजक ब्रजेश मिश्र ने बताया कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए मोर्चा ने 29 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन पब्लिक वार्ता, पहली मई को जन-जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान, आठ मई को कंकड़बाग अंचल का घेराव, 17 मई को सायकिल जुलूस और 23 मई को पुतला दहन भी किया था. पटना नगर निगम मोर्चा के आन्दोलन पर समस्या का समाधान करने का प्रयास तो किया है लेकिन वह सिर्फ खानापूर्ति मात्र है. नगर आयुक्त के प्रयास पर भी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी एवं सफाई इंस्पेक्टर पानी फेर देते हैं. विधायक की लापरवाही एवं राजनीतिक उदासीनता की वजह से पटना नगर निगम लापरवाह हो जाता है और जनता कष्ट में जीने को मजबूर होती है. कुम्हरार विधानसभा बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ता मो. यूसुफ खां, हरिजी पाडेय, हरिकिशोर सिंह राठौर, कुंदन कुमार, रंजीत सिन्हा, कृष्ण राम पाडेय, विक्की सिन्हा, पुरुषोत्तम पाठक, अमित कुमार, रामकृपाल साव, संजीव कुमार राम, बैजू चंद्रवंशी, आलोक कुमार सिंह, रामपुकार कुशवाहा, कुंदन पाडेय, मो. सईद, मो. नेहाल हसन, सुनील कुमार राम, पप्पू पासवान, राहुल मिश्र, राजू यादव, संजीव चौधरी, अनिल तिवारी, रंजन राजपूत, अवनिश कुमार, पुरुषोत्तम पाण्डेय, अजय विश्वकर्मा, सुनील तिवारी, श्रीध्र पाण्डेय, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार, रणजीत पाण्डेय उर्फ पप्पू साई सहित कई नागरिकों ने प्रदर्शन में भाग लिया.

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

जहानाबाद के मध्य विद्यालय झुनाठी में समर्थ फाउंडेशन, इंडियन मेडिकल एसासिएशन और साई नेत्रालय की ओर से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. इसमें समाजसेवी पद्मश्री सुधा वर्गी ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि चिकित्सा जगत में तेजी से विकास हो रहा है, इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि अब भी यहां स्वास्थ्य जागरूकता की जरूरत है. इसके बाद उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों को इस दिशा में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए. ऐसे संगठन ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है. यहां गरीबी व अशिक्षा अधिक है. इस शिविर में तकरीबन साढ़े तीन हजार लोगों की नि:शुल्क चिकित्सा जांच एवं दवा वितरण किया गया. समर्थ फाउंडेशन द्वारा नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र की सुविधा थी. जिसका लोगों ने लाभ उठाया. इस अवसर पर विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉ सहजानंद सिंह(आईएमए के कार्यकारी अध्यक्ष), राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैप्टन विजय सिंह, डॉ. राजीव रंजन सहित अनेक डॉक्टरों ने सभी प्रकार के रोगियों की जांच की और उन्हें परामर्श दिए. साई नेत्रालय के चिकित्सकों ने हजारों मरीजों की आखों की जांच की. शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ अमरकांत झा अमर जहानाबाद जिला के आईएमए के सचिव डॉ. राजदेव प्रसाद, डॉ एस जीत ने भी जांच की. समाजसेवी तथा पत्रकार संजय कुमार झुनाठी के सरपंच चितरंजन कुमार एवं सामर्थ फांउडेशन की सचिव श्रीमती नूतन कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया. सामर्थ फाउंडेशन के अध्यरक्ष नीरज कुमार शेखर शर्मा जगत नारायण शर्मा नागेंद्र प्रसाद विजय प्रसाद के साथ इलाके के गणमान्य एवं बुद्धिजीवी उपस्थित थे. संस्थान के अध्यक्ष नीरज कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. **- रजनीकांत**

बच्चों का आधार पंजीकरण अभियान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्धारा पांच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार पंजीकरण के लिये बिहार में अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत वर्तमान में बिहार के 10 आंगनबाड़ी केन्द्र पर शून्य से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार पंजीकरण किया जा रहा है. राज्य में लगभग 82,400 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जहां 5 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 36 लाख बच्चे पंजीकृत हैं. जल्द ही राज्य में स्थित इन सभी केन्द्रों पर बच्चों का आधार पंजीकरण का काम आरंभ किया जायेगा. इन केन्द्रों पर इन बच्चों का भी आधार पंजीकरण किया जायेगा जो इन केन्द्रों में पंजीकृत नहीं हैं. प्राधिकरण द्धारा अगले दो महीनों में इन सभी बच्चों का आधार पंजीकरण कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. बिहार में स्थित लगभग 80,500 विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद यहां पढ़ने वाले छात्रों के आधार पंजीकरण के लिये भी विशेष अभियान चलाया जायेगा. इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगभग 2 करोड़ 47 लाख है. इनमें से 1 करोड़ 21 लाख छात्रों का आधार पंजीकरण किया जा चुका है. प्राधिकरण द्धारा शेष छात्रों के आधार पंजीकरण का काम का भी अगले दो महीने में पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. **-भारती**

एक्यूप्रेशर शिरोमणि अवार्ड मिला

सीतामढ़ी शहर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित विहंगम एक्यूप्रेशर केंद्र के चर्चित चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार सुमन को एक्यूप्रेशर शिरोमणि अवार्ड मिला है. अवार्ड सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने पिछले 26 मई को पटना के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में आयोजित एक समारोह में डॉ सुमन को दिया. इससे पूर्व भी उन्हें एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा के कारण एक्यूप्रेशर गोल्ड मेडल मिल चुका है. साथ ही एसएसबी की ओर से भी डॉ. सुमन सम्मानित किये जा चुके हैं. चिकित्सक को मिले सम्मान पर मुनींद्र राय, अमित कुमार, रामबाबू यादव, गीतकार गीतेश, डॉ. शत्रुघ्न यादव समेत दर्जनों ने प्रसन्नता व्यक्त की है. डॉ सुमन ने सफलता पर चर्चा करते हुए कहा कि एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में अब लोगों को बेहतर लाभ मिल पा रहा है. आने वाले दिनों में और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की योजना है. लोगों के सहयोग से जन कल्याण के कार्य को मुकाम तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे. **-ब्रजेश**

मच्छर से निजात के लिए छिड़काव

सीतामढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में गंदगी के कारण जहरीले मच्छरों का आतंक कायम होकर रह गया है. इससे आम लोगों को निजात दिलाने को लेकर नगर परिषद द्वारा कीटनाशक समेत अन्य छिड़काव की कवायद की जाती है. परंतु साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण मच्छरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. बताया जाता है कि नगर परिषद कार्यालय की लापरवाह कार्यशैली के कारण नगर के मुख्य पथ को छोड़कर वार्ड की गलियों में नियमित सफाई की अब तक व्यवस्था नहीं की जा सकी है. सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण प्रसाद, गोविंद झा, नवल किशोर समेत अन्य ने जिला प्रशासन से नियमित साफ-सफाई सभी वार्डो में कराने की मांग की है. **- विकास**

जनप्रतिनिधियों को मिले सम्मान

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में पिछले दिनों आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में जदयू नेता सह विधान परिषद स्थानीय निकाय के प्रत्याशी राजेश चौधरी ने कहा कि जब तक पंचायत व नगर निकाय के प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विकास का सपना साकार नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायत प्रतिनिधियों समेत नगर निकाय के प्रतिनिधियों के सम्मान व सुरक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी. मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से श्री चौधरी की हर संभव मदद का भरोसा दिया. कार्यक्रम में स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी, बेलसंड विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रंधीर सिंह चौहान समेत सैकडों पंचायत प्रतिनिधि समेत अन्य मौजूद थे.■ **- विभा**

कल्याणपुर में बिछने लगी चुनावी बिसात

कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद पहली बार 2010 में चुनाव हुआ. तब सूबे में भाजपा जदयू का गठबंधन था.जिसके कारण कल्याणपुर सीट जदयू के पाले में आयी और जदयू ने यहां से अपनी पार्टी के पूर्व विधायक मो. ओबैदुल्लाह की पत्नी रजिया खातून को प्रत्याशी बनाया. जिन्होंने राजद के उम्मीदवार मनोज यादव को 15402 मतों से पराजित कर विजय हासिल की. 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहां संभावित प्रत्याशियों की लंबी कतार दिख रही है. सबसे ज्यादा भाजपा के नेता ताल ठोंक रहे हैं. इसका कारण है कि 20 वर्षों बाद भाजपा को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है.

राकेश कुमार

विधान सभा चुनाव 2015 को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है. पार्टी नेताओं सहित स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए संभावित प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है.क्षेत्र में किये अपने कार्यों समेत जीत के बाद उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की रूप रेखा से लोगों को अवगत कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे चुनावी तापमान बढ़ने लगा है.

पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 2008 में नये परिसीमन के बाद हुआ. केसरिया, पीपरा क्षेत्र से काट कर बने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कोटवा एवं कल्याणपुर प्रखण्ड का 34 पंचायत समाहित है. लगभग दो लाख पांच हजार मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र का भौगोलिक आकार लंबा है,जिसके कारण एक छोर से मुख्यालय की दूरी करीब 25 से 30 किलो मीटर है. सड़क, बिजली, पेयजल आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है.ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कृषि संबंधित समस्याएं यहां के निवासियों को ज्यादा प्रभावित करती हैं.चकिया चीनी मिल के बंद होने के कारण इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ता है. एक तो किसानों को अपना गन्ना अब चकिया की बजाये गोपालगंज जिले के हरखुआ व सिंधवलिया चीनी मील को देना पड़ता है, जहां किसानों को घटतौली व कम दर पर गन्ना बेचने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद पहली बार 2010 में चुनाव हुआ. तब सूबे में भाजपा जदयू का गठबंधन था.जिसके कारण कल्याणपुर सीट जदयू के पाले में आयी और जदयू ने यहां से अपनी पार्टी के पूर्व विधायक मो. ओबैदुल्लाह की पत्नी रजिया खातून को प्रत्याशी बनाया. जिन्होंने राजद के उम्मीदवार मनोज यादव को 15402 मतों से पराजित कर विजय हासिल की. 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहां संभावित प्रत्याशियों की लंबी कतार दिख रही है. सबसे ज्यादा भाजपा के नेता ताल ठोंक रहे हैं. इसका कारण है कि 20 वर्षों बाद भाजपा को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है. पूर्व में केसरिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहे इस क्षेत्र से भाजपा 1995 तक चुनाव लड़ी थी. लेकिन नये परिसीमन व गठबंधन के कारण उसे यह सीट छोड़नी पड़ी, लेकिन 2014 में गठबंधन टूटने के बाद आसन्न विधानसभा चुनाव में 20 वर्षों के बाद भाजपाईयों को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है. जिसके कारण इस सीट पर संभावित प्रत्याशियों की भीड़ में राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर प्रखंड तक के नेता ताल ठोंक रहे हैं.

दूसरी ओर जदयू एवं राजद के महागठबंधन को लेकर नेताओं में दावेदारी को लेकर संशय है. जदयू की सिटिंग विधायक रजिया खातून सेटिंग-गेटिंग के तहत अपना टिकट सुनिश्चित मान रही हैं. वहीं गठबंधन के बाद राजद के स्थानीय नेता इस सीट पर अपना दावा जता रहे हैं. इस सीट के संभावित दावेदारों में जदयू से वर्तमान विधायक रजिया खातून अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं. जदयू के वरिष्ठ नेता व केसरिया के विधायक रह चुके मो. ओबैदुल्लाह की पत्नी रजिया खातून अपने विकास कार्यों से संतुष्ट हैं. बकौल रजिया क्षेत्र में अभी कई समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना बाकी है.भाजपा के दावेदारों में मयंकेश्वर सिंह गोवंश विकास प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं. क्षेत्र में उन्होंने कई विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभायी है. बकौल मयंकेश्वर कल्याणपुर के कैथवलिया में बन रहे विश्व के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर के निर्माण में उन्होंने ग्यारह लाख की भूमि खरीद कर दान में दे दी है. वह हर वर्ष जरूरतमंदों के बीच नियमित रूप से कंबल का वितरण करते हैं तथा हर सुख-दुख में उनके साथ रहते हैं. क्षेत्र की जनता की सेवा में जुटे रहने के कारण आम जन में उनकी खासी पकड़ है. जहां राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व से जुड़े होने के कारण उन्हें टिकट मिलने का भरोसा है. वहीं जनता को भी भरोसा है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र का विकास हो सकेगा.

अखिलेश कुमार सिंह भाजपा के जमीनी नेता माने जाते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ष प्रशिक्षित अखिलेश अखिल भारतीय विधार्थी परिषद के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे. क्षेत्र की जनता के दुख-सुख में दशकों से जुड़े रहने के कारण क्षेत्र में अच्छी पहचान है.

रामलोचन यादव को भी भाजपा का जमीनी नेता माना जाता है. प्रखंड एवं विधानसभा क्षेत्र की सेवा में लंबे समय से जुड़े रहे हैं. चुमन यादव भाजपा प्रखंड अध्यक्ष हैं. समाज सेवा के कारण आम-जन में लोकप्रिय हैं और पार्टी संगठन के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं. राजेन्द्र यादव जिला परिषद के पूर्व उपसभापति रहे हैं. राजेंद्र जातीय वोट एवं अपनी अलग पहचान के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. सत्यनारायण यादव कोटवा प्रखंड के जगीराहां पंचायत के तीन बार से लगातार मुखिया हैं. जातिगत वोट एवं अन्य जातियों में व्यक्तिगत प्रभाव के बलबूते चुनाव लड़ना चाहते हैं. सियावर सिंह प्रखंड भाजपा के युवा नेता हैं. जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं. वहीं जिला भाजपा महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष प्रभावती गुप्ता भी प्रबल दावेदार हैं. आधी आबादी के बल पर चुनाव लड़ना चाहती हैं. लोजपा की ओर से अब तक यहां किसी की प्रबल दावेदारी नहीं दिख रही है. रालोसपा के राष्ट्रीय नेता व कल्याणपुर निवासी राजेश्वर सिंह भी दावेदारी रखते हैं. 2010 के चुनाव में राजेश्वर सिंह चौथे स्थान पर थे.

राजद के मनोज यादव सशक्त दावेदार है बकौल मनोज महागठबंधन हो या न हो कल्याणपुर सीट से राजद के प्रत्याशी वही होंगे. राजद से 2 बार केसरिया के विधायक रह चुके स्व. यमुना यादव के पुत्र मनोज यादव 2010 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे. कम्युनिस्ट पार्टी के रामायण सिंह भी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं. वे 2010 के चुनाव में तीसरे स्थान पर थे. आम आदमी पार्टी से पंडित बृजेश ओझा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. बकौल बृजेश अगर आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती है तो वे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. बृजेश भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं. क्षेत्र में उनकी पहचान साफ-सुथरे चरीत्र वाले जमीनी नेता के रूप में हैं.

क्षेत्र की समस्याओं की फेहरिस्त लंबी हैं. बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कें पक्की नहीं हो पाई हैं. लगभग 50 फीसदी गांव में बिजली नहीं है पेयजल के संसाधनों का अभाव हैं. विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली सनौती नदी के कारण हजारों एकड़ भूमि जल-जमाव के कारण खेती योग्य नहीं रह गई है. जिससे 5 हजार से ज्यादा किसान परिवार प्रभावित हैं. हालांकि सनौती नदी को जल संग्रहण योग्य बनाकर कृषि के लिए उपयोगी बनाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी. 1984 में इस योजना के तहत लगभग 100 किलोमीटर लंबाई एवं 66 फीट चौड़ाई में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया था. किसानों को इसका भुगतान भी किया गया लेकिन योजना फाइलों में बंद हो गई. अभी तक किसानों के जमाबंदी से अधिग्रहण की गई भूमि को घटाया भी नहीं गया है. जिसके कारण आज भी किसान लगाम दे रहे हैं. अगर यह योजना पूरी हो गई होती तो हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य हो जाती साथ ही मत्स्य पालन एवं सिंचाई भी की जा सकती थी.

आश्चर्य की बात है कि क्षेत्र को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने वाले इस योजना के संबंध में किसी ने पूछने तक की जहमत नहीं उठाई हैं.

फिलवक्त संभावित प्रत्याशी चुनावी समीकरण के जोड़ घटाव में लगे हैं. समस्या व चुनावी मुद्दों की जगह जातीय समीकरण की जोड़-तोड़ की जा रही हैं. हालांकि सरकारी तौर पर जातीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं हैं. एक आकलन के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में जातीगत वोटरों की संख्या निम्न हैं.

यादव	–	32000 लगभग
मुस्लिम	–	24000 लगभग
भूमिहार	–	22000 लगभग
ब्राह्मण	–	10000 लगभग
कायस्थ	–	4000 लगभग
राजपूत	–	10000 लगभग
कुषवाहा	–	10000 लगभग
कुर्मी	–	8000 लगभग
अति.पिछड़	–	40000 लगभग
अनु.जाति/जजा	–	20000 लगभग
अन्य	–	20000 लगभग

सभी प्रत्याशी इसी गणित में लगे हैं कि गठबंधन के बाद या गठबंधन नहीं होने की स्थिति में उनके पाले में किस जाति का वोट आ सकता है. वर्तमान में मुद्दों से ज्यादा जातीय आधार पर गुणा भाग किया जा रहा हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी एवं पप्पू यादव के बीच के ताल मेल के असर का भी आकलन किया जा रहा हैं. यह पक्ष भी परिणामों को प्रभावित करेगा. बहरहाल जोड़-तोड़ एवं गठबंधन की राजनीत अंतिम समय में क्या होगा इसी पर जातीय समीकरण के साथ प्रत्याशी रणनीति बनायेंगें.■

feedback@chauthiduniya.com

पैसे के लिए चरित्र गंदा न करें

रजनीकांत पांडेय

जीवन के छोटे से छोटे कार्य भी हमारे जीवन में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी कोई काम करें तो पूरे जोश और ईमानदारी से करें . इससे जीवन में खुद-ब-खुद नए-नए रास्ते खुलते चले जाते हैं. ऐसा ही है वरिष्ठ वकील दीनू कुमार की जिन्दगी की कहानी. इनकी कहानी उन युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सफल वकील बनना चाहते हैं. दीनू कुमार पटना हाईकोर्ट में सफल वकील हैं. दीनू कुमार गया जिले के परैया थाना के छोटे से गांव हरिदास पुर की धरती से आते हैं. उन्होनें गांव के मिडिल स्कूल से पढ़ाई शुरू की और वहां से सातवीं तक की पढ़ाई कर के वह परैया के कोरिया हाई स्कूल से दसवीं की परीक्षा सन 1973 में पास किया. दीनू कुमार का सपना था वकील बनने का उनके के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी. उन्होंने आगे की पढ़ाई गया से शुरू की. वहां से उन्होंने सन 1977 में आईएससी और बीएससी तक की पढ़ाई पूरी की. दीनू कुमार की जिन्दगी में एक मात्र उद्देश्य था, वकील बनना. सन 1977 में वकालत करने का फैसला किया और उसी साल एएम कॉलेज गया से वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी. सब कुछ ठीक चल ही रहा था की दीनू की जिन्दगी ने अचानक यूटर्न ले लिया और उनके पिता का देहांत हो गया. पिता के देहांत के बाद दीनू पर परिवार और घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया. बहन की शादी करना उनके जीवन की मुख्य चुनौती बन गई. परिवार के दूसरे सदस्यों ने दीनू पर दबाव बनना शुरू किया कि अब पढ़ाई छोड़कर खेती करो और घर देखो. लेकिन उनकी मां चाहती थी की दीनू अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़े. दीनू कुमार ने माता का आशीर्वाद लेकर पटना चले आए. सन 1978 में कॉलेज आफ कॉमर्स पटना से लॉ की पढ़ाई शुरू की सन 1982 में लॉ की डिग्री भी ले ली. इसके बाद वह संघर्ष करते गए और आगे बढ़ते गए. वह कभी कर्म और मेहनत से पीछे नहीं हटते थे. सन 1983 से प्रैक्टिस में लग गये. शुरू में उन्होनें सीनियर रामचन्द्र प्रसाद सिन्हा के यहां अपनी ट्रेनिंग शुरू की. फिर एक साल बाद वहां से छोड़ सीनियर नागेन्द्र राय के यहां प्रैक्टिस करने लगे . 10 जुलाई 1990 को उनके सीनियर जज हो गए. इसके बाद दीनू ने खुद का काम शुरू कर दिया. दीनू बताते हैं की प्रैक्टिस के दौरान तरह-तरह के लोगों से मुलाकात हुई और मैंने यही सीखा कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए. मुकाम और लक्ष्य होना चाहिए . इससे आपके जीवन में खुद-ब-खुद रास्ते खुलते चले जाते हैं. वह कहते हैं गरीब छात्र हों और जिसको बैक सपोर्ट न हो, ऐसे स्टूडेंट को बहुत संघर्ष करना पड़ता हैं. लेकिन वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी और एक समय के बाद पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है. वह अपने जीवन की हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. दीनू कहते हैं की हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए. उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया है और ऐसा कर के वह बहुत खुश हैं. वह कहते हैं कि पैसे के लिए अपना चरित्र को गंदा न करे पैसा आयेगा लेकिन ईमानदारी से मेहनत करते रहें.■

सन 1977 में वकालत करने का फैसला किया और उसी साल एएम कॉलेज गया से वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी. सब कुछ ठीक चल ही रहा था की दीनू की जिन्दगी ने अचानक यूटर्न ले लिया और उनके पिता का देहांत हो गया. पिता के देहांत के बाद दीनू पर परिवार और घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया. बहन की शादी करना उनके जीवन की मुख्य चुनौती बन गई. परिवार के दूसरे सदस्यों ने दीनू पर दबाव बनना शुरू किया कि अब पढ़ाई छोड़कर खेती करो और घर देखो. लेकिन उनकी मां चाहती थी की दीनू अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़े. दीनू कुमार ने माता का आशीर्वाद लेकर पटना चले आए.

feedback@chauthiduniya.com

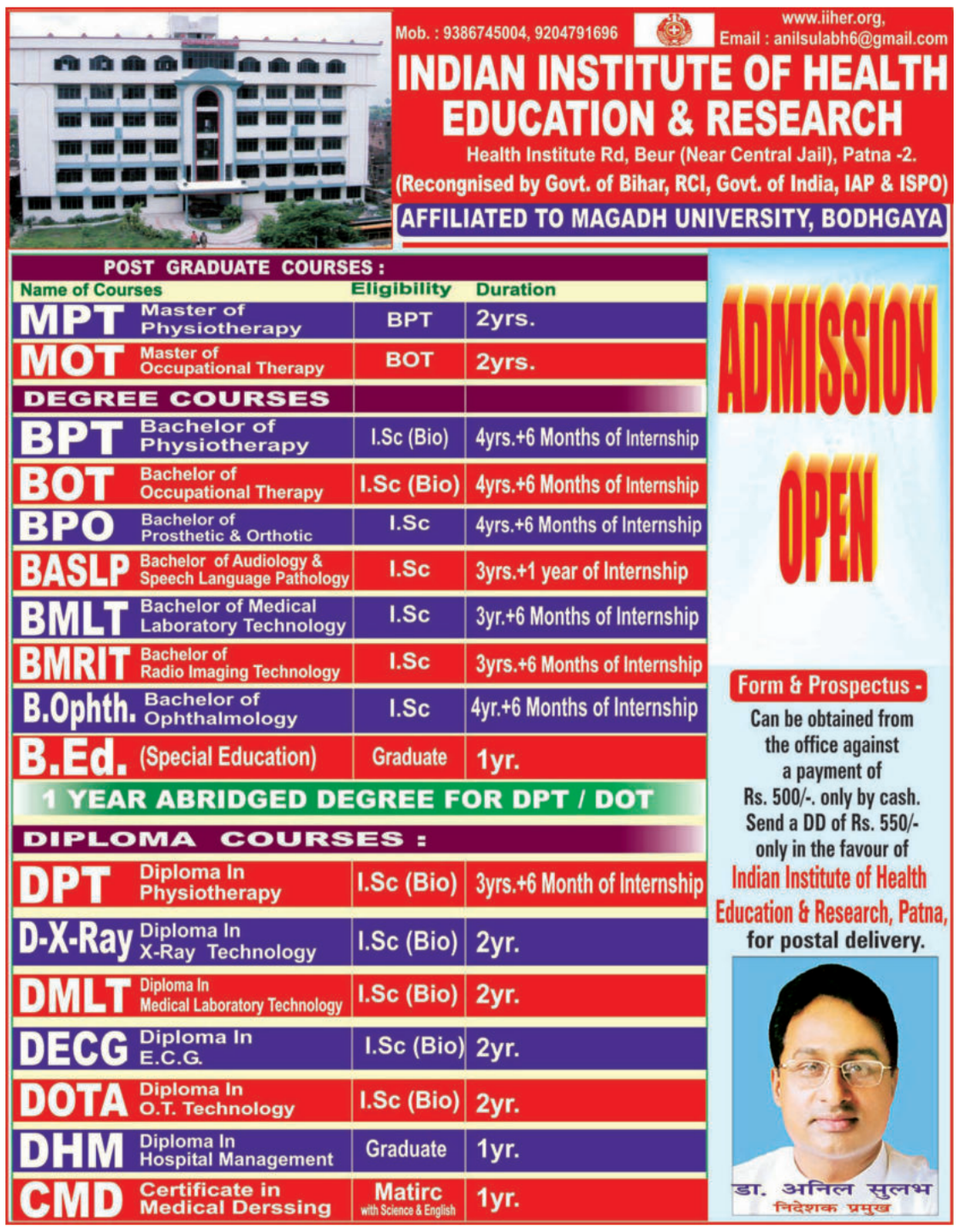

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

15 जून -21 जून 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

अखिलेश और राजीव के क्रिकेट-करार का हुआ बेइंतेहा प्रचार

करार पर उठते सवाल

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास पर पिछले दिनों आयोजित भव्य कार्यक्रम में भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर खूब तकरीरें हुईं और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजीव शुक्ला के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का करार हुआ. विज्ञापनों के जरिए इसका खूब प्रचार भी हुआ था. लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि डेढ़ साल पहले वाली घोषणा और इस करार के दरम्यान अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना पटाक्षेप क्यों कर गए, प्रदेश सरकार पहले से ही स्टेडियम बनवा रही है, तो इस एमओयू के अति-प्रचार का तार्किक औचित्य क्या है?

प्रभात रंजन दीन

मुख्यमंत्री जी! डेढ़ साल पहले आपने जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था और शिलान्यास भी किया था, वह काम औचित्यपूर्ण था या अब आपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बड़े-बड़ों से जो करार किया है, उसका अधिक औचित्य है? तब राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना की मौजूदगी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के बारे में जो फैसले हुए थे उसे लेकर इस तरह विज्ञापनबाजी नहीं हुई थी, लेकिन अब राजीव शुक्ला से करार को लेकर बेतहाशा विज्ञापनबाजी क्यों हुई? इस अति-प्रचार ने तब और अब के फर्क के साथ-साथ तब और अब की वजहों को भी सामने ला खड़ा किया है. स्वाभाविक सवाल है कि तब का फैसला अर्थपूर्ण था या अब का प्रचार? अब का करार राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन कराने मात्र को लेकर हुआ तो विज्ञापनों में सरकार ने इसे स्पष्ट क्यों नहीं लिखा? स्टेडियम निर्माण को इस करारनामे से जोड़ कर क्यों दिखाया गया? करार केवल राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन को लेकर हुआ तो प्रकाशित विज्ञापनों में यूपीसीए और इकाना स्पोर्ट्स सिटी के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रमुखता से क्यों छापा गया? मैचों के आयोजन में प्राधिकरण की क्या कोई भूमिका है? खेल मामलों में इकाना कंपनी के क्या योगदान हैं?

इन सवालों से घिरी रही लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर की गई बेतहाशा विज्ञापनबाजी और करार-कार्यक्रम की बेमानी भाषणबाजी. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास पर पिछले दिनों आयोजित भव्य कार्यक्रम में भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर खूब तकरीरें हुईं और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजीव शुक्ला के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का करार हुआ. विज्ञापनों के जरिए इसका खूब प्रचार भी हुआ था. लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि डेढ़ साल पहले वाली घोषणा और इस करार के दरम्यान अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना पटाक्षेप क्यों कर गए, प्रदेश सरकार पहले से ही स्टेडियम बनवा रही है, तो इस एमओयू के अति-प्रचार का तार्किक औचित्य क्या है? पूरे-पूरे पेज पर प्रकाशित विज्ञापनों में भी सरकार ने इन सवालों को स्पष्ट नहीं किया और न भाषणबाजियों में ही इसे साफ किया गया.

बहरहाल, पहले तो यह देखते चलिए कि इस महान करारनामा-कार्यक्रम में क्या-क्या ताल ठोके गए. इसके बाद आपको बताएंगे कि डेढ़ साल पहले क्या-क्या कहा गया था. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीन जून को अपने सरकारी आवास पर आयोजित भव्य करार-कार्यक्रम में समाजवादी सरकार के खेल-कूद को बढ़ावा देने के प्रयासों की आत्मप्रशंसा की और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करार पर हस्ताक्षर के गवाह बने. इस कार्यक्रम की खूबी यह रही कि विभिन्न अखबारों में अंधाधुंध छपवाए गए विज्ञापनों में लखनऊ के प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन और इकाना स्पोर्ट्स सिटी के बीच करार का प्रचार किया गया. लेकिन विज्ञापनों में करार का असली मुद्दा नहीं बताया गया. करार-कार्यक्रम में यह कहा गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम (कानपुर) में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार और यूपीसीए के बीच करार हो रहा है. यह भी कहा गया कि लखनऊ में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए विकासकर्ता कम्पनी और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए. इस प्रायोजित घालमेल को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी उलझन में रहे. हां, इस प्रायोजित घालमेल के बीच मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की खूब प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि इस करार से उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा.

करार की कहानी के इस अध्याय को भी ध्यान में रखते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर के प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम को 30 साल के लिए यूपीसीए को लीज़ पर देने जा रही है. इस लीज़ को सरकार लाइसेंस बता रही है. हालांकि सरकार यह भी कहती है कि स्टेडियम का स्वामित्व सरकार का ही रहेगा. इसके लिए बीसीसीआई के नियम का हवाला दिया गया है कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच प्रदेश को तभी आवंटित किया जाएगा, जब एसोसिएशन के पास अपना क्रिकेट स्टेडियम हो या एसोसिएशन का किसी क्रिकेट स्टेडियम के स्वामी से 30 वर्ष का अनुबन्ध हो. इसी शर्त को ध्यान में रखते हुए यूपीसीए को ग्रीन पार्क स्टेडियम 30 साल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. इस अवधि में क्रिकेट एसोसिएशन पारिभाषित क्षेत्र की देख-रेख अपने खर्च पर करेगा. प्रकाशित विज्ञापनों में प्रदेश सरकार ने इस तथ्य का कहीं जिक्र नहीं किया.

कार्यक्रम में ही प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कह दिया कि लखनऊ में 400 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है और इस पर तेजी से काम भी जारी है. फिर, इस करारनामा-कार्यक्रम के आयोजन और प्रचार का औचित्य क्या था? यह सवाल कार्यक्रम स्थल पर भी तैरता रहा. खेल के इस कार्यक्रम में आवास विभाग के प्रमुख सचिव सदाकान्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रियल इस्टेट को भी ठूंसने के निर्णय पर अघाते रहे. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही ग्रीन पार्क स्टेडियम को यूपीसीए को सौंपने के करार पर खेल विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. अनीता भटनागर जैन और यूपीसीए के सचिव राजीव शुक्ला ने हस्ताक्षर जड़े. भविष्य में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हों, इसके लिए भी यूपीसीए के सचिव राजीव शुक्ला और इकाना स्पोर्ट्स सिटी के निदेशक उदय सिन्हा के बीच करारनामे पर हस्ताक्षर की औपचारिकता हुई.■

feedback@chauthiduniya.com

खूब उड़ाई सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिकेट-करार का विज्ञापन छपवाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाईं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की फोटो छापने पर पाबंदी लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि विज्ञापनों पर केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ही तस्वीर लगाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि मंत्री और नेता सरकारी पैसे का व्यापक दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी वाहवाही लूटने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं. करोड़ों रुपये की बर्बादी रोककर उस पैसे से अन्य महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकते हैं. लेकिन प्रदेश सरकार ने तीन जून को जो पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन छपवाए, उन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ-साथ यूपीसीए के सचिव कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नारद राय, राज्य मंत्री रामकरन आर्या और फरीद महफूज किदवई की तस्वीरें चस्पा हैं. विज्ञापन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम चुनौती दे डाली है. जिस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उस समय तो सरकारी विज्ञापनों से मुख्यमंत्री की फोटो हटा दी गई थी, लेकिन तीन जून को छपे विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर दी गई. यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनरविचार याचिका दाखिल करती उसके पहले ही विज्ञापन छाप कर सार्वजनिक चुनौती दे डाली. तमिलनाडु सरकार इस मामले में याचिका दायर कर चुकी है.

...पर नारद राय तो खेल मंत्री हैं ही नहीं

बेतहाशा प्रचारित क्रिकेट-करारनामा प्रशासनिक बेवकूफियों, लापरवाहियों और साठगांठ में फंस गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके अखबारों में पूरे-पूरे पेज के जो विज्ञापन छपवाए गए, उसमें भीषण गलती पाई गई. लेकिन गलती तब पकड़ी गई जब विज्ञापन सारे अखबारों में छप गए. विज्ञापन में कैबिनेट मंत्री नारद राय को खेल मंत्री बता कर छापा गया, जबकि नारद राय खेल विभाग के मंत्री हैं ही नहीं. खेल विभाग खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास है और दो राज्य मंत्री रामकरन आर्या और फरीद महफूज किदवई उनके साथ सम्बद्ध हैं. नारद राय पहले खेल मंत्री थे, लेकिन पिछले साल जून महीने में ही मुख्यमंत्री ने उनसे खेल विभाग लेकर उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का मंत्री बना दिया था. आपको याद होगा कि उसी समय राजेंद्र चौधरी से कारागार विभाग लेकर बलराम यादव को कारागार मंत्री बनाया गया था. उस समय कुछ और मंत्रियों के विभाग बदले गए थे. तीन जून 2015 को सभी अखबारों में पूरे पेज का जो विज्ञापन छापा गया, उसमें नारद राय को बाकायदा खेल विभाग का कैबिनेट मंत्री बताया गया. इस विज्ञापन ने पूरे शासन-प्रशासन की बेवकूफी उजागर कर दी. उक्त विज्ञापन यंग एडवरटाइजर नाम की कंपनी के जरिए जारी किया गया था, लेकिन उसे आखिरी तौर पर पास करने की जिम्मेदारी सूचना विभाग के अफसरों की थी. उन अफसरों ने हरी झंडी दी तो विज्ञापन छपने के लिए रिलीज कर दिया गया. अब इसे थोपने के लिए एक दूसरे का सिर तलाशा जा रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने कहा कि विज्ञापन में प्राधिकरण का नाम और लोगो जरूर छपा है. लेकिन छपने के पहले उन्हें विज्ञापन नहीं दिखाया गया था. उन्हें विज्ञापन के बारे में जानकारी भी नहीं थी. खेल विभाग के निदेशक आरपी सिंह ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें पता ही नहीं कि विज्ञापन किसने छपवाया.

विज्ञापन जारी करने वाली यंग एडवरटाइजर कंपनी से लेकर एनसीआर में यूपी सरकार के खर्चे पर होर्डिंग्स और एलईडी लगाने वाली ओरिजिंस कंपनी और सूचना विभाग की साठगांठ ने इस तरह की अराजकता का सृजन किया है. निष्पक्षता से अगर जांच हुई तो घोटाले और कमीशनखोरी का एक और एपिसोड सामने आएगा.

परिदृश्य से क्यों गायब हो गए सुरेश रैना

तकरीबन डेढ़-दो साल पहले देश के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी और यूपी निवासी सुरेश रैना ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिल कर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराने की सार्थक पहल की थी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना ने राज्य में खेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए ढांचा विकसित करने की मुख्यमंत्री से अपील की थी. तब मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का आश्वासन दिया था. फिर स्टेडियम निर्माण का आदेश भी जारी कर दिया गया. लेकिन आज वही सुरेश रैना परिदृश्य से गायब हैं. इस पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है.

फरवरी 2014 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का बाकायदा शिलान्यास भी हो गया. फिर सितम्बर 2014 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद ही मीडिया को बताया कि लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्टेडियम बनाने में पांच सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. जबकि अभी (एक साल बाद) मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि इस पर चार सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री ने बताया था कि सुलतानपुर रोड पर शहीद पथ के निकट बन रहे स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन कराया जाएगा और नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने तब यह कहा था कि स्टेडियम सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर बन रहा है. इसे बनाने का ठेका हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसकी सहायक एनजीसीसी को दिया गया है. डेवलपर को 137 एकड़ में से 67 एकड़ जमीन रियल इस्टेट विकसित करने के लिए दी जाएगी. इससे स्टेडियम के निर्माण का खर्च निकाला जाएगा. 70 एकड़ में खेल परिसर होगा. इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और क्रिकेट अकादमी भी शामिल होगा. गर्ल्स और ब्वॉयज हॉस्टल समेत एक हेल्थ सेंटर का भी निर्माण होगा. क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 50 हजार दर्शकों की होगी. स्टेडियम निर्माण करने वाली कंपनी ही अगले 35 सालों तक स्टेडियम की देखरेख भी करेगी.इतना सब कुछ कराने के सूत्रधार रहे क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना आज परिदृश्य से गायब हैं या गायब कर दिए गए हैं. आज वे लोग परिदृश्य में हैं, जिनके निजी-सियासी-आर्थिक हित ही सर्वोपरि रहे हैं.

रीयल इस्टेट कंपनी है इकाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बहु-प्रचारित करार में जिस इकाना स्पोर्ट्स सिटी को अत्यंत प्रमुखता से स्थान दिया, वह असलियत में रीयल-इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाली कंपनी है. महज एक साल पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई इस संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार से मिली इतनी तरजीह की कुछ न कुछ खास वजह तो रही ही होगी. नई दिल्ली के बाबर रोड स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका दफ्तर है और संजय सिन्हा, विजय सिन्हा और उदय सिन्हा कंपनी के तीन निदेशक हैं. करारनामा कार्यक्रम में इकाना स्पोर्ट्स सिटी के निदेशक उदय सिन्हा लखनऊ आए थे.

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

फर्जी आईएएस मामला

एसआईटी और हरीश सरकार बैकफुट पर

44 दिन तक जांच के नाम पर एसआईटी रूबी मामले की जांच को लेकर केवल समय पास करती रही. जांच के परिणाम के नाम पर अदालत में बगले झांकने के सिवा कुछ भी नहीं रहा. सूत्र बताते हैं कि पूरे प्रकरण में आईएएस अकादमी के दिग्गज अफसरों के फंसने की बन रही स्थिति के अंदेशा के कारण पूरी आईएएस लॉबी बचाव में सक्रिय हो गयी. जिसका नतीजा यह रहा कि जांच दल ने अधर में मैदान छोड़ दिया. जांच दल केवल 44 दिनों तक इस अतिसंवेदनशील मामले में जांच के नाम दिखावा करता रहा, जबकि यह मामला राष्ट्रपति और देश की सर्वोच्च अकादमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. इस मामले को लेकर जनता के दिमाग में कई यक्षप्रश्न उठ रहे हैं. पहला सवाल यह है कि आखिर रूबी चौधरी आईएएस अकादमी में कैसे, किसके माध्यम से पहुंची? अकादमी में अनवरत छ:मास तक वह कैसे और किसके कृपा पर रही? किन लोगों की मेहरबानी से परिसर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बतौर आईएएस ट्रेनी फोटो सेशन में भाग लिया?

राजकुमार शर्मा

देश के चर्चित लालबहादुर शास्त्री आईएएस अकादमी में रूबी चौधरी मामले में उत्तराखंड पुलिस के हाथ खड़ा करने से राज्य के कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है. इस मामले में गठित एसआईटी के अधिकारियों ने पहले तो बड़े जोश के साथ जांच शुरू की थी. जांच की सुई जब मोदी सरकार के एक मंत्री एवं संस्थान के मुखिया तक पहुंची, तो जांच दल को सांप सूंघ गया. जिसके कारण एसआईटी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गयी है. सूबे के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर पुलिस को आइना दिखाते हुए कहा कि उनकी अक्षमता की स्थिति में हम स्वयं जांच अधिकारी बनने को तैयार हैं. सरकार पूरे केस को मेरे हवाले करे, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे. अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो उसे जेल जाना ही चाहिए. भट्ट के पत्र के जवाब में भी मुख्यमंत्री कार्यालय के महारथियों ने कहा है कि सक्षम हो तो उन्हें अपने घर की जांच करनी चाहिए. इस मामले में गिरफ्तारी के पहले दिन से ही इस मामले की कथित अभियुक्त रूबी चौधरी संस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ जैन को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है. असली गुनहगारों पर हाथ डालने से पहले ही पुलिस का हथियार डालना अब यही संदेश दे रहा है कि कानून की धमक सिर्फ निर्बल जनता तक है. अब पूरे मामले में एक बात साफ हो गयी है कि पुलिस की भूमिका सच को छिपाने की ही रही है, जो हर हाल में सच पर पर्दा डालकर अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है. देहरादून की अदालत ने इस पूरे मामले में केस डायरी को हल्का बताते हुए रूबी को जमानत भी दे दी. 44 दिन तक जांच के नाम पर एसआईटी रूबी मामले की जांच को लेकर केवल समय पास करती रही. जांच के परिणाम के नाम पर अदालत में बगले झांकने के सिवा कुछ भी नहीं रहा. सूत्र बताते हैं कि पूरे प्रकरण में आईएएस अकादमी के दिग्गज अफसरों के फंसने की बन रही स्थिति के अंदेशे के कारण पूरी आईएएस लॉबी बचाव में सक्रिय हो गयी. जिसका नतीजा यह रहा कि जांच दल ने अधर में मैदान छोड़ दिया. जांच दल केवल 44 दिनों तक इस अतिसंवेदनशील मामले में जांच के नाम दिखावा करता रहा, जबकि यह मामला राष्ट्रपति और देश की सर्वोच्च अकादमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. इस मामले को लेकर जनता के दिमाग में कई यक्षप्रश्न उठ रहे हैं. पहला सवाल यह है कि आखिर रूबी चौधरी आईएएस अकादमी में कैसे, किसके माध्यम से पहुंची? अकादमी में अनवरत छ:मास तक वह कैसे और किसके कृपा पर रही? किन लोगों की मेहरबानी से परिसर में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बतौर आईएएस ट्रेनी फोटो सेशन में भाग लिया? यह सभी सवाल आज भी समय के गर्भ में है. इस पूरे प्रकरण में सम्बन्ध अकादमी के मुखिया से भी जुड़े होने के कारण जांच दल ने इस मामले में असल गुनाहगार को बचाने का काम किया है. इस पूरे प्रकरण ने उत्तराखंड कानून व्यवस्था के झण्डाबरदारों की पोल खोल कर रख दी है. यह बात सूबे की आम जनता की समझ में आती है कि अकादमी में रूबी चौधरी की जगह कोई आतंकी संगठन का सदस्य घुस गया होता तो परिणाम क्या होता. इतना सब कुछ होने के बावजूद जांच दल के हाथ मात्र रूबी का चढ़ना एक सोची समझी जांच की ओर इशारा करता है.

नव दिन चले ढाई कोस की तर्ज पर चली इस चर्चित प्रकरण की जांच में उत्तराखंड पुलिस ने सरकार से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि जांच दल के सदस्यों की हिम्मत नहीं है कि वह बड़े गुनहगारों पर हाथ डाले. इसी डर के कारण अधिकारियों ने आनन-फानन में मामले की जांच सीबीआई से कराने की संतुति कर दी. पूरे मामले में पुलिस की नक्कारी का खुलासा होने के बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस की साख बचाने के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति को ठंडे बस्ते में डालकर भाजपा को सरकार की अक्षमता उजागर करने का एक और मौका दिया. राज्य के पुलिस के मुखिया बी एस सिद्धू पर पहले ही राज्य के वन विभाग ने वन माफिया के रूप में काम करने की शिकायत अदालत में दर्ज करा रखी है, जो अभी विचाराधीन है. मोदी सरकार के मंत्री का नाम वरिष्ठ आईएएस के साथ जुड़ने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत की भूमिका को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं. बड़े अपराधियों को बचाने के खेल में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की गलबहियां करने का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है. दोनों ही सरकारें असल गुनहगार को बचाने के लिए नूरा कुश्ती कर रही हैं. आईएएस अकादमी की साख पर जो दाग लगे हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

एमिटी के लखनऊ कैंपस में जुटीं फिल्मी हस्तियां

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ के एमिटी विश्वविद्यालय में भी गांधीगीरी हो रही है. छात्र-छात्राओं के बीच फिल्मी दुनिया के लोगों की आमद, उनकी गहमागहमी और शूटिंग के तामझाम से परिसर में चहलपहल बनी रही. अनुपम श्याम, जिसे टीवी स्क्रीन पर ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से लोग जानते हैं, ने छात्र-छात्राओं को संबोधित भी किया. फिल्मी परदे पर दिखने वाले नामचीन चेहरों को अपने बीच पाकर सब उत्साहित थे. कोई उनके साथ सेल्फी लेने को उन्मुख था, तो कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए. फिल्मी हस्तियों ने भी खूब मौज की और विश्वविद्यालय भवन के आगे खड़े होकर अपनी तस्वीरें खिंचवाईं.

मुंबई के आगमन फिल्म्स के सनोज मिश्रा के निर्देशन में एमिटी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों गांधीगीरी फिल्म की शूटिंग हुई. अस्वस्थ होने के कारण ओमपुरी तो नहीं आ पाए, लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम लखनऊ आए. फिल्म की शूटिंग भी हुई और उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया.

एमिटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति मेजर जनरल (रि.) के के ओहरी ने अनुपम श्याम का स्वागत किया. इस दरम्यान एमिटी बिजिनेस स्कूल के निदेशक प्रोफेसर वीपी साही सहित बड़ी संख्या में छात्र- छात्राएं और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे. अनुपम श्याम को एमिटी विश्वविद्यालय परिसर देखकर प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर की याद आ गई. उन्होंने छात्रों से कहा कि विश्वविद्यालय विद्या का सागर होता है. छात्रों को जीवन सूत्र देते हुए अनुपम श्याम ने कहा कि दुनिया भले ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हो, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति की हमेशा जरूरत बनी रहती है. दृढ़ निश्चय और देशा सेवा का लक्ष्य लेकर चलने वाले के लिए कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता. छात्रों से मुलाकात के बाद फिल्म गांधीगीरी की टीम ने आगे की कहानी का फिल्मांकन किया जिसमें लाईब्रेरी में फिल्म के मुख्य किरदारों से जुड़े दृश्य शूट किए गए. शूटिंग के लिए अनुपम श्याम, फिल्म के हीरो ऋषि भूटानी और हिरोइन डॉली चावला समेत निर्देशक सनोज मिश्रा और निर्माता प्रताप यादव और उनकी पूरी टीम विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद थी. विश्वविद्यालय परिसर के कई हिस्सों में दृश्यांकन हुआ, जिसमें मुख्य भवन, मैंगो आर्चिड, फाउन्टेन एरिया क्लास रूम प्रमुख थे. फिल्म गांधीगीरी में ओमपुरी, मुकेश तिवारी, राजपाल यादव सरीखे कलाकार भी शामिल हैं.■

प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3300 करोड़ का नुकसान

तीन केंद्रीय मंत्रियों की सराहना

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र के तीन मंत्रियों उमा भारती, नितिन गडकरी व प्रकाश जावेडकर की सराहना की. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाने पर सरकार उक्त तीनों केंद्रीय मंत्रियों का आभार प्रकट करती है. फंडिंग पैटर्न से उत्तराखंड को हो रहे नुकसान की पीड़ा भी केंद्र के समक्ष रखनी बेहद जरूरी है.

रेनू शर्मा

मोदी सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर मोदी समर्थक जब अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से अपनी उपलबधियों का डंका बजा रहे थे. इसी समय देवभूमि उत्तराखंड से उपचुनावों में मोदी के लहर की हवा निकालने में समर्थ रहे हरीश रावत मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण हो रही जन क्षति को उजागर कर मोदी की स्वप्निल नीतियों को तार-तार कर रहे थे. मोदी सरकार राहुल गांधी के निशाने पर पहले से रही है और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सुट-बुट की सरकार का नाम दिया है. हरीश ने खुला आरोप लगाया फंडिंग पैटर्न बदलने से उत्तराखंड को इस वित्तीय वर्ष में करीब 3300 करोड़ का नुकसान हो रहा है. कई अन्य हिमालयी राज्यों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है. ऐसे में नीति आयोग की अगली बैठक में सभी प्रभावित राज्य सामूहिक रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे. उन्होंने बदले फंडिंग पैटर्न से हो रहे नुकसान के तथ्यों को झुठलाने पर भाजपा के प्रदेश नेताओं को भी निशाने पर लिया. मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वरिष्ठ नेता राज्य को हो रहे नुकसान के तथ्यों को लगातार झुठला रहे हैं, जबकि हिमाचल व कई अन्य प्रदेश भी केंद्र के सामने यह मसला उठा चुके हैं. उत्तराखंड को विशेष राज्य के रूप में केंद्रीय योजनाओं में 90/10, 80/20 व 70/30 अनुपात में जो वित्तीय मदद मिलती थी, इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 50/50 का अनुपात कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों के अंशदान में 10 फीसद बढ़ोत्तरी के केंद्र के फैसले को पहली बार सराहा भी. फंडिंग पैटर्न में बदलाव के नुकसान की तुलना में इसे नगण्य बताया.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बावजूद इसके राज्य सरकार आय के वैकल्पिक स्रोत भी तलाश रही है, इस बड़े नुकसान की भरपाई भी कठिन है. इसका असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है. फंडिंग पैटर्न से राज्य को हो रहे नुकसान की हकीकत केंद्र के समक्ष रखना जरूरी है. सभी प्रभावित राज्य इस मुद्दे को नीति आयोग में प्रभावी ढंग से उठाएंगे. उन्होंने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से भी दलगत भावना को छोड़कर राज्य हित में इस मसले को सामूहिक रूप से केंद्र के समक्ष उठाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा देर से भेजने के विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नमामि गंगे योजना में दस हजार करोड़ का पहला प्रस्ताव पूर्व में भेज चुकी है. केंद्र के निर्देश पर इसका संशोधित प्रस्ताव भी भेजा गया. केदारनाथ के लिए भी केंद्र के कहने पर अलग से प्रस्ताव भेजा गया. उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो जिले बागेश्वर व चमोली को चयनित कर लक्ष्य तय किया. हकीकत यह है कि केंद्र से इस मिशन की नियमित किश्त भी राज्य को नहीं मिल रही. विपक्ष पर्यटन विकास के प्रस्ताव नहीं भेजने का आरोप भी लगा रहा है, जबकि पर्यटन को केंद्र ने राज्यों के जिम्मे पर छोड़ दिया है. विपक्ष के एक नेता ने नमामि गंगे में राज्यांश खर्च नहीं करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ यात्रा तक निकाल दी, जबकि केंद्र ने अपनी इस योजना को वित्तीय स्वीकृति ही बाद में दी.■

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर सपाई कब्जे के खिलाफ शिया समुदाय सड़क पर

सपा को आजम प्रिय, शिया नहीं...

सूफी यायावर

feedback@chauthiduniya.com

सूबे की सरकार ... सुन्नी नेता आजम खान की तरफदारी में उत्तर प्रदेश सरकार शियाओं से टकराव मोल ले रही है. शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कराए गए चुनाव और फेरबदल को शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद अखिलेश सरकार की सीधी दखलंदाजी बताते हैं. जव्वाद का कहना है कि यूपी सरकार एकता की ताकत से डरती है, इसी वजह से प्रदेश में 200 से अधिक दंगे कराए गए. वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अब सरकारी शह पर डाकुओं का अड्डा बन गया.

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वसीम रिजवी की नियुक्ति के खिलाफ शिया समुदाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. स्थानीय आसिफ मस्जिद में लोगों ने पिछले दिनों सपा सरकार और मुलायम सिंह के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन किया. नारे लगाते हुए लोग मस्जिद से बाहर निकले और रूमी दरवाजा, घंटाघर होते हुए छोटे इमामबाड़े पहुंचे. वहां मुस्लिम महिला जागरूक मंच की महिलाएं वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहले से भूख हड़ताल कर रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी चोर है, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, बुक्कल नवाब मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद और आजम खान मुर्दाबाद के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों के हाथ में सपा विरोधी नारे वाली तख्तियां भी थीं.

शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की शह पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर काबिज हुए डाकुओं को जब तक हटा नहीं लिया जाता, विरोध जारी रहेगा. मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी एकता की ताकत से डरती है, इसलिए वह कभी हिन्दू-मुस्लिम दंगे कराती है तो कभी शिया-सुन्नी फसाद कराती है ताकि एकता न हो सके. मुजफ्फनगर में हिंदू मुस्लिम दंगे कराए गए ताकि एकता शक्ति को समाप्त कर दिया जाए और पूरे राज्य में योजना के साथ 200 से अधिक दंगे कराए गए, जो एक रिकॉर्ड है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आने देना चाहती, क्योंकि ओवैसी शिया व सुन्नी समुदाय की एकता का समर्थक है. समाजवादी पार्टी के नेता उससे भयभीत हैं. आगरा में ओवैसी के कार्यक्रम पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया, क्योंकि वहां शिया-सुन्नी दोनों एकजुट होकर उसके साथ हैं. मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है. जब वह मुजफ्फरनगर का दंगा करा सकती है, तो कुछ भी कर सकती है. मुलायम सिंह की सरकार में मौलवीगंज लखनऊ में मुसलमानों पर गोलियां चलाई गईं, बेदर्दी के साथ उनकी हत्या की गई, मगर एक एफआईआर नहीं लिखी गई. पुलिस ने सरकार के कहने पर मुसलमानों को डराया था कि अगर एफआईआर की तो और लोग मारे जाएंगे. मौलाना ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अनशनरत महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ प्रशासन ने उठाने की कोशिश की, तो पूरे शहर में मातमी विरोध होंगे. फिर क्रमशः बड़ा इमामबाड़ा और छोटे इमामबाड़े को बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद हजरतगंज पर शिया समुदाय के लोग भारी तादाद में गिरफ्तारी देंगे. मौलाना ने कहा कि जब से सऊदी अरब के राजदूत लखनऊ आए, शिया समुदाय के लोगों पर उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ता जा रहा है. शिया वक्फ बोर्ड में योजनाबद्ध तरीके से वसीम रिजवी को लाए जाने के खिलाफ मुस्लिम महिला जागरूक मंच और कनीजाने जहरा की भूख हड़ताल शिया समुदाय के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है. महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मौलाना सैयद कल्बे आबिद मरहूम की 85 साल की बहन मरजिया शमसी और मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी की पत्नी भी भूख हड़ताल में शामिल हुईं. इस मौके पर लखनऊ की महिलाओं ने बड़ी तादाद में छोटे इमामबाड़े पर पहुंच कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. शिया धर्मगुरु ने यहां भी कहा कि सरकार चाहती है कि वक्फ में हमेशा बेईमान और भ्रष्ट लोग ही रहें ताकि वह अवकाफ की जायदाद को इसी तरह बर्बाद करती रहे. अपराधियों और देशद्रोहियों को वक्फ में लाया गया है. मौलाना ने कहा कि जिन लोगों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, उनकी जांच होनी चाहिए. मरहूम मौलाना सैयद कल्बे आबिद की बहन व मौलाना कल्बे जव्वाद की मां मरजिया शमसी ने कहा कि हम वक्फ सुरक्षा के लिए आए हैं. इमाम की संपत्तियां लुट रही हैं और हम इसे लुटता हुआ नहीं देख सकते. यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है. मरजिया शमसी ने कहा कि मेरे भाई मौलाना कल्बे आबिद ने अजादारी और वक्फ की हिफाजत के लिए आंदोलन शुरू किया था और मेरा बेटा इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है. मैं भी उसके समर्थन में आगे आई हूं. इस मौके पर शबी फातिमा ने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जव्वाद जांच से बचने के लिए यह सब करवा रहे हैं, वह पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें. अगर मौलाना जव्वाद जांच से बचना चाहते, तो वे कभी वक्फ संपत्तियों के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग नहीं करते.

उधर, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीस ने भी कहा कि समाजवादी सरकार के लगातार झूठे वादों से मुसलमान मायूस हो चुके हैं. सरकारी की नाइंसाफियां अब किसी से छुपी नहीं है. मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट दिया था ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सकें, आरक्षण मिल सके. समाजवादी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन यह सरकार निकम्मी निकली. हाजी ने कहा कि मुसलमानों को इस सरकार ने उनके अधिकार से वंचित कर रखा है. एहले सुन्नत सज्जादा नशीन ने कहा कि हम शिया समुदाय के आंदोलन का समर्थन करते हैं और पूरी तरह मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद के साथ हैं. जो नाउम्मीदी वह झेल रहे हैं उसी के हम भी शिकार हैं.■

छोटे और बड़े इमामबाड़े पर जड़ा ताला

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ शिया समुदाय का विरोध अब व्यापक और तल्ख होता जा रहा है. शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की नियुक्ति के विरोध में छोटे इमामबाड़े पर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने चार जून को छोटे इमामबाड़े पर ताला जड़ दिया. इसके बाद पांच जून को आंदोलनकारियों ने बड़े इमामबाड़े को भी बंद कर दिया और उसके दरवाजे पर ताला डाल दिया. अब 14 जून से जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है. आंदोलनकारियों ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के उस पत्र का बैनर बनवाकर इमामबाड़े के गेट पर लगा दिया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वे मौलाना कल्बे जव्वाद की इच्छा के मुताबिक

ही वक्फ बोर्ड में काम कराएंगे, लेकिन वे अपने वादे पर कायम नहीं रहे. इस तालाबंदी के बाद अब कोई भी पर्यटक इमामबाड़ा और भूल भुलैया नहीं देख पाएगा. शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी की मातमी अन्जुमनों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 14 जून को राज्य सरकार की नाइंसाफियों के खिलाफ नाजमी साहब के इमामबाड़ा विक्टोरिया स्ट्रीट से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा. जब तक सरकार मांगें पूरी नहीं करेगी, जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा. तालाबंदी की कार्रवाई को पर्यटन मौसम में भारी झटका माना जा रहा है. छोटे इमामबाड़े पर चार जून को ताला जड़ने का काम मुस्लिम महिला जागरूक मंच और कनीजाने जहरा ने किया. आंदोलनकारी महिलाओं का कहना था कि उनकी मांगों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये और शिया वक्फ बोर्ड में वसीम रिजवी की अवैध नियुक्ति के खिलाफ छोटे इमामबाड़े के आंतरिक दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है. अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया और समुचित कार्रवाई नहीं की गई, तो भूख हड़ताल जारी रहेगी और इमामबाड़ा किसी भी पर्यटक के लिए नहीं खोला जाएगा. महिलाओं ने कहा कि वे हफ्तेभर से भूख हड़ताल पर बैठी हैं मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. मुस्लिम महिला जागरूक मंच शबी फातिमा ने कहा, अब हम हर बलिदान के लिए तैयार हैं, लेकिन अब मांगें मनवाकर ही उठेंगे. इस सरकार को अल्पसंख्यकों से कितनी मोहब्बत है, इसीसे अंदाजा होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं सात दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और सरकारी बेखबरी का प्रदर्शन कर रही है. यह सरकार महिला सुरक्षा की बात बेमानी करती है.

शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव सरकार की साजिश : जव्वाद

मजलिस-ए-उलमा-ए-हिंद के महासचिव व शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने सिया वक्फ बोर्ड का जबरन चुनाव कराए जाने को सरकार की साजिश बताया. मौलाना जव्वाद का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के मामले में सरकार की नीयत पर उन्हें भरोसा नहीं है. शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की गड़बड़ी करने वालों पर पहले कार्रवाई होती, तब चुनाव कराए जाते. शिया धर्मगुरु ने कहा कि शिया वक्फ में लगातार हो रहे गबन के मामले और धांधलियों के आरोपी व सीबीसीआईडी जांच में दोषी पाए गए चेयरमैन को सरकार बार-बार चेयरमैन की कुर्सी नवाज कर वक्फ संपत्तियों को लुटवा रही है. वक्फ की संपत्तियों की होटलों में खुलेआम बिल्डरों से डील की जा रही है. मौलाना ने दो महीने में बदले गए 150 मुतवल्लियों को लेकर भी शिया वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए. गौरतलब है कि अभी हाल ही में शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन वसीम रिजवी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मौलाना कल्बे जव्वाद समेत तमाम औकाफ के मुतवल्लियों को हटाकर उनकी जगह नए मुतवल्लियों की नियुक्ति कर दी थी. मौलाना कल्बे जव्वाद के अलावा मौलाना अमीर हैदर को भी मुतवल्ली के पद से हटा दिया गया था. राजधानी लखनऊ की वक्फ सज्जादिया कदीम, वक्फ हुसैनबांदी बेगम और वक्फ इमामबाड़ा झाऊलाल तीनों ही जगह से मौलाना कल्बे जव्वाद को मुतवल्ली पद से हटा दिया गया था. लखनऊ के अलावा रामपुर, रायबरेली, बिजनौर, मेरठ, बरेली, मुजफ्फर नगर आदि शहरों की वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों में फेरबदल किया गया था. इसके बाद सरकार के संरक्षण में वक्फ बोर्ड का चुनाव कराया गया और वसीम रिजवी को फिर से काबिज करा दिया गया. प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान के खासमखास वसीम रिजवी फिर से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुन लिए गए. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद गुट द्वारा कोई प्रत्याशी न खड़ा किए जाने की वजह से रिजवी निर्विरोध चुन लिए गए. उनके नाम का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब ने किया था.■

संविधान को चुनौती दे रहे हैं जव्वाद : रिज़वी

शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड का गठन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है, किसी भी न्यायालय में मैं दोषी साबित नहीं हुआ हूं तथा कोई भी आरोप हम पर सिद्ध नहीं हुआ है. कल्बे जव्वाद सीधे-सीधे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं. मेरे अधिकारों का जबरन हनन करने के लिए वे हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मौलाना कल्बे जवाद प्रदेश में अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं. वे सपा विरोधी सियासी पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं. विकास के क्षेत्र में अखिलेश सरकार की उपलब्धियों से घबरा कर सपा विरोधी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में बड़ा दंगा कराना चाहती हैं. इस साज़िश को अंजाम देने के लिए हैदराबाद के ओवैसी और लखनऊ से कल्बे जव्वाद को सामने लाया जा रहा है.■

विधायक ने काम रोका

नाला या गड़बड़झाला!

शत्रुंजय सिंह रैकवार

गोरखपुर महानगर में बन रही आवासीय कालोनी में बरसात के पानी से होने वाले जल जमाव से निजात पाने के लिये शहर वासी व नगर निगम हर वर्ष परेशान रहता है. ऐसे में शहर के कूड़घाट सिंघड़िया से लेकर व अन्य मोहल्लों के जल जमाव से निजात पाने के लिये 16.48 करोड़ की लागत से नाला निर्माण कार्य तो शुरू हुआ है, पर भौगोलिक व स्वाभाविक जल प्रवाह को देखा जाये तो नाले की वर्तमान डिजाइन का कोई औचित्य ही नहीं है. नन्दानगर और एयरफोर्स का वाटर लेबल नीचे है और निर्माणाधीन नाले के बेस का लेबल ऊंचा है. देवरिया रोड से नाले में पानी निकासी के लिए नाले छोटे-छोटे बनाए गए हैं. छेद देवरिया रोड से डेढ़ फीट ऊपर है. छह किलोमीटर लम्बे नाले का सिर्फ डेढ़ किलोमीटर हिस्सा नगर निगम के अंतर्गत आता है, शेष साढ़े चार किलोमीटर ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में है. ग्रामीण क्षेत्र के नाले की सफाई कौन करेगा. नालों को नदी में मिलाने के पहले रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है, इसमें है ही नहीं. उक्त नाला बनने के पहले ही विवादों में आ गया है. माहिर ठेकेदार व निर्माण एजेंसी सीएनडीएस के आला अधिकारी बरसात के पूर्व ही करोड़ों रुपये पानी में बहा देने की तैयारी में हैं. नाला निर्माण को लेकर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल व सपा पार्षदों में ठन गई है, जिसका खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.

बताते चलें कि कूड़ाघाट सिंघड़िया से तुर्रा नाले तक बनाए जा रहे नाले में शुरू से ही मानकों की धज्जियां उड़ाई गईं. 16.48 करोड़ के नाले के लिए न तो डिजाइन तैयार की गयी और न टेंडर निकाला गया. शासन के कुछ चहेते ठेकेदारों को कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य दे दिया गया, जिसे ठेकेदार ने अपने लाभ के लिये जगह-जगह खुदाई कर आनन-फानन में निर्माण कार्य शुरू करा दिया. दरअसल इस नाले की स्वीकृति पिपराईच विधानसभा के विधायक राजमति निषाद के पैड व पार्षद प्रतिनिधि हीरा लाल के कवरिंग लेटर पर हुई. बारिश में भारी जलजमाव को देखते हुये पार्षद प्रतिनिधि हीरा लाल ने प्रस्ताव दिया कि जलभराव समस्या दूर करने के लिये वसुंधरा मोड़ से तुर्रा नाले तक नाले का निर्माण करा दिया जाये. मुख्यमंत्री कार्यालय से नियमानुसार कार्रवाई करने और आख्या देने का आदेश हुआ तो कंसट्रक्शन व डिजाइन सर्विस ने इसका एस्टीमेट तैयार किर दिया. यहीं नही लगात व लाभ का अनुपात भी निकाला गया. शासन ने वर्ष 2013-14 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत धनराशि स्वीकृत की और 4 मार्च 14 को आनन-फानन में काम शुरू कर दिया गया. नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने तकनीकी खामियों की ओर इंगित करते हुए आपत्ति की तो कार्यदायी संस्था के निदेशक ने जांच के नाम पर काम रोक दिया. संस्था ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य हो रहा है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है और बरसात के पानी का स्वाभाविक जल प्रवाह किधर है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाला निर्माण क्षेत्र नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन दूसरे विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में प्रस्ताव देने का एक नया प्रचलन इसी सरकार में शुरू हुआ है. सिंघड़िया से तुर्रा तक नाले की डिजाइन मुसीबत बन गयी है. यही कारण है कि नाले के निर्माण पर सवाल खड़ा हो गया. सवाल उठाया गया है कि यदि मौजूदा डिजाइन पर ही निर्माण कार्य कराया गया, तो क्षेत्र से जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा. नगर विधायक ने विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से कहा कि वे मौके पर जाकर निर्माण कार्य देखें और तय करें कि क्या मौजूदा डिजाइन से समस्या का समाधान निकल पाएगा? स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराज हैं. इंजीनियरिंग कालेज क्षेत्र में निर्माण नाले का काम पिछले कई महीनों से बंद है, जिससे आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं. उन्हें चिंता है कि बारिश तक यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन्हें फिर जलजमाव की समस्या से जूझना पड़ेगा. बताते चलें कि बसपा शासन काल में मुख्यमंत्री आगमन के दौरान एयरपोर्ट से सर्किट हाउस गोरखपुर जाते समय उनका ध्यान रास्ते में भारी-जल भराव पर गया जो कि वायुसेना केन्द्र को प्रभावित कर रहा था. परिणाम स्वरूप जल निकास योजना बनाने का आदेश दिया था. उक्त जल बहाव की निकटतम निकासी व भौगोलिक स्थिति रामगढ़ताल के तरफ ही स्वाभाविक बहाव वाली है, जो कि जल जमाव के स्थान से मात्र डेढ़ किलोमीटर दूर है. उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के खनन के लगाये गये रोक के बावजूद कई हजार घनफीट मिट्टी का खनन इस परियोजना के नाम पर हुआ और उस मिट्टी का लेखा-जोखा नहीं है. जैसा कि हम जानते हैं, इस परियोजना का अन्त तुर्रा नाले में हो रहा है, जो कि एक स्थानीय नदी में जुड़ा हुआ है, जिससे बाढ़ के समय नदी में बहने वाले जीव जन्तु व अन्य अवांछनीय गंदगी शहर के रिहायशी क्षेत्र में आ सकती है. इससे भयावह स्थिति पैदा हो सकती है. स्थानीय नागरिक मेराजुद्दीन का कहना है कि नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से समस्या पैदा हो जायेगी. सिंघड़िया से रानीडीहा तक और काली मंदिर से पेट्रोल पंप के आगे गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा तक जगह-जगह मिट्टी के टीले हैं. बारिश होते ही फिसलन से चलना मुश्किल हो जाता है. कार्यदायी संस्था सीएनडीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस) ने इसे जल्दी नहीं हटाया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है. गोरखपुर, देवरिया से बिहार व बलिया तक को जोड़ने वाली इस सड़क पर छोटे, बड़े वाहनों का आवागमन लगा रहता है. बारिश के दिनों में जल बहाव वायुसेना स्टेशन से सिघड़िया मोहल्ले की तरफ काफी तीव्र गति से होता है. कार्यदाया संस्था सीएनडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर आरके भारती का कहना है कि गुणवत्ता पर किसी को कोई संदेह नहीं है. नगर विधायक ने उसकी लेबल और डिजाइन को लेकर आपत्ति की है इसलिये काम रुक गया है. निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है. सीएनडीएस के निदेशक अनूप सक्सेना ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में बताया कि अनियमितताओं की जांच करने वह गोरखपुर गए थे. जांच लगभग पूरी हो चुकी है. बरसात शुरू होने से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा. जहां तक निविदा की बात है तो इस कार्य को डिपार्टमेंटल कंस्ट्रक्शन यूनिट के तहत कराया जा रहा है. खोदाई में निकली मिट्टी कहां गई इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि परियोजना प्रबंधक से पूछ कर ही बता पाऊंगा.■

नगर विधायक ने पर्चे बांटकर उठाए सवाल

नाले के औचित्य पर सवाल उठाते हुए नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने इंजीनियरिंग कालेज क्षेत्र में पर्चे बांटे. उन्होंने अनियमितता का आरोप लगाया है. कार्यदायी एजेंसी सीएंडडीएस (कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस) की कार्यशैली ठीक नहीं है, ऐसा नगर विधायक का मानना है. उन्होंने कहा कि नाला नंदानगर, एयरफोर्स से लेकर देवरिया रोड के जल निकासी के लिये बनाया जा रहा है परन्तु किसी भी स्थान से निकल कर पानी इस नाले में नहीं जायेगा. दोनों क्षेत्रों के नाल का लेबल निर्माणाधीन नाले से नीचे है. स्वाभाविक जल प्रवाह की दिशा में नाला न बना कर उसके विपरीत पूर्व-पश्चिम दिशा में नाला न बनाकर तुर्रा नाला में मिलाया जा रहा है. निर्माणाधीन नाले में कहीं भी रेगुलेटर नहीं बनाया गया है. उनका कहना है कि 6 किलोमीटर लम्बे नाले का डेढ़ किलोमीटर का हिस्सा नगर निगम की सीमा में है. बाकी हिस्सा कुसम्ही जंगल से गुजरेगा. सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. जब नाला बंद हो जायेगा तो पानी कैसे बहेगा.

चरमरा रही बिजली व्यवस्था

घर ही में चोर और बकाएदार भी

बसे अधिक बिजली की आपूर्ति भी इटावा, सैफई एवं मैनपुरी में होती है और यहीं पर बिजली की चोरी भी सर्वाधिक रिकॉर्ड की जाती है. जो बातें लिखी गईं, वे आधिकारिक सत्य हैं. यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं है. इसी आधिकारिक सत्य का एक और पहलू है, सरकारी विभागों पर बिजली का करोड़ों रुपये का बकाया. प्रदेश का ऊर्जा विभाग करोड़ों रुपये के घोटाले, करोड़ों रुपये के बकाए और करोड़ों रुपये की बिजली चोरी में आकंठ डूबा है, तो बिजली कहां से आए! ऊर्जा विभाग खोखला हो चुका है. हालात और खराब होते जाएंगे, लेकिन नेताओं की नौटंकी जारी रहेगी, केवल सत्ता का मंच बदलता रहेगा.

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से तबाह है. लोग गर्मी से मर रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं है. बिजली नहीं, तो पानी भी नहीं. राजधानी लखनऊ के कुछ चुनिंदा इलाकों को छोड़ दें, तो बाकी इलाकों में बिजली की भारी किल्लत है. प्रदेश के अन्य ज़िलों में तो बिजली ही नहीं है, वह चाहे औद्योगिक क्षेत्र कानपुर हो या प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी. केवल उन पांच संसदीय क्षेत्रों, जहां से मुलायम सिंह यादव परिवार के लोग जीतकर संसद पहुंचे हैं, में बिजली की चकाचक व्यवस्था है. उनमें भी इटावा, सैफई एवं मैनपुरी की बात अलग है. सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति भी इटावा, सैफई एवं मैनपुरी में होती है और यहीं पर बिजली की चोरी भी सर्वाधिक रिकॉर्ड की जाती है. जो बातें लिखी गईं, वे आधिकारिक सत्य हैं. यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं है. इसी आधिकारिक सत्य का एक और पहलू है, सरकारी विभागों पर बिजली का करोड़ों रुपये का बकाया. प्रदेश का ऊर्जा विभाग करोड़ों रुपये के घोटाले, करोड़ों रुपये के बकाए और करोड़ों रुपये की बिजली चोरी में आकंठ डूबा है, तो बिजली कहां से आए! ऊर्जा विभाग खोखला हो चुका है. हालात और खराब होते जाएंगे, लेकिन नेताओं की नौटंकी जारी रहेगी, केवल सत्ता का मंच बदलता रहेगा.

राजधानी लखनऊ में ही सरकारी विभागों पर शासन की कोई पकड़ नहीं है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है. पुलिस, नगर निगम, एलडीए, राज्य संपत्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी एवं जल संस्थान ऐसे विभाग हैं, जिन पर केवल लखनऊ में करोड़ों रुपये का बकाया है, लेकिन इन विभागों से कोई पैसा निकलवा नहीं सकता. इसमें सबसे बड़ा बकाएदार खुद पुलिस महकमा है, उससे पैसे कौन निकलवाए! दूसरा बड़ा बकाएदार राज्य संपत्ति विभाग है. अधिकांश नेता एवं नौकरशाह राज्य संपत्ति विभाग से उपकृत रहते हैं, लिहाजा बकाया भी उपकार वाले खाते में ही पड़ा है. पुलिस विभाग के राजधानी लखनऊ स्थित दफ्तरों पर जो भारी बकाएदारी है, उसे जानेंगे, तो आश्चर्य होगा कि ये किस नैतिकता से दूसरों को क़ानून का पालन करने की ताकीद करते हैं. बकाएदारी को जरा तफ्सील से देखें. राजधानी लखनऊ के सीबीसीआईडी महकमे के एसपी पर बिजली के 14 लाख 288 रुपये बकाया हैं. लखनऊ जोन के आईजी दफ्तर पर 13 लाख 15 हज़ार 871 रुपये बकाया हैं. लखनऊ रेंज के आईजी दफ्तर पर एक लाख 99 हज़ार 631 रुपये बकाया हैं. यूपी बॉर्डर पुलिस के एडीजी मुख्यालय पर दो लाख 62 हज़ार 948 रुपये बकाया हैं.

सीआरपीएफ के आईजी दफ्तर पर तीन लाख 13 हज़ार 364 रुपये, सीबीआई के एसपी पर चार लाख, 77 हज़ार 437 रुपये, सीबीआई के एसपी के दूसरे दफ्तर पर 48 हज़ार 368 रुपये और तीसरे दफ्तर पर 38 हज़ार 244 रुपये बकाया हैं. सीबीसीआईडी के एसपी (क्यू) पर एक करोड़ 56 लाख तीन हज़ार 744 रुपये बकाया हैं. लखनऊ में केवल चिनहट इलाके में आने वाली नौ पुलिस चौकियों पर बिजली विभाग के एक करोड़ 20 लाख 52 हज़ार 721 रुपये बकाया हैं. बकाए के उक्त आंकड़े सरकारी दस्तावेज़ों पर आधारित हैं, जो सूचना का अधिकार क़ानून के तहत फैजाबाद के वकील मो. अतहर शम्सी द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में सरकार ने खुद मुहैया कराए हैं.

राज्य संपत्ति विभाग पर 17 लाख 84 हज़ार 690 रुपये से अधिक का बकाया है. पीडब्ल्यूडी विभाग पर क़रीब 85 लाख रुपये, चीनी निगम मुख्यालय स्थित मॉडर्न कंट्रोल रूम पर छह लाख चार हज़ार 344 रुपये, नेशनल होम्योपैथी कॉलेज लखनऊ पर तीन लाख 88 हज़ार 804 रुपये, लखनऊ जल संस्थान जोन-1 पर दो लाख 10 हज़ार 503 रुपये, नगर निगम जोन-4 के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर 72 हज़ार 653 रुपये, निदेशक जेटीआरआई पर तीन लाख 96 हज़ार 60 रुपये का बकाया है.

अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर दो लाख 99 हज़ार 160 रुपये, एलडीए सचिव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर तीन लाख पांच हज़ार 308 रुपये, एलडीए सचिव प्राधिकरण भवन पर 12 लाख 12 हज़ार 956 रुपये, कांशीराम परिवर्तन प्रबंध संस्थान पर एक लाख 62 हज़ार रुपये, एलडीए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बेहनन पुरवा गोमती नगर पर 22 हज़ार 687 रुपये, एलडीए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास खंड गोमती नगर पर दो लाख 54 हज़ार 355 रुपये, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन खंड-2 पर दो लाख 52 हज़ार 586 रुपये, स्पोर्ट्स अफसर स्पोर्ट्स स्टेडियम विजयंत खंड पर 14 लाख 42 हज़ार 565 रुपये, प्रभागीय वन अधिकारी पर आठ लाख 57 हज़ार 595 रुपये, संगीत नाटक अकादमी के निदेशक पर एक लाख 93 हज़ार 693 रुपये, भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक पर तीन लाख 35 हज़ार 446 रुपये, निबंधन महानिरीक्षक पर 12 लाख 319 रुपये, डूडा के परियोजना अधिकारी पर सात लाख 15 हज़ार 147 रुपये और राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव पर दो लाख 42 हज़ार 349 रुपये से अधिक बकाया है. यह केवल राजधानी लखनऊ के कुछ विभागों का हाल है. हांडी पर चढ़े चावल के कुछ दाने टटोलिए और सारे का हाल जान लीजिए.

उत्तर प्रदेश में बिजली का 29 हज़ार 325 करोड़ रुपये बकाया है और विभाग का घाटा 26 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक है. ध्यान रहे, यह आंकड़ा एक-दो साल पुराना है. इसके अलावा प्रदेश में लाइन लॉस यानी बिजली की चोरी भी क़रीब 30 प्रतिशत है. खरबों रुपये के घोटाले इसके अलावा हैं, जो जांच और कार्रवाई के लिए लंबित पड़े हैं, लेकिन नेता, नौकरशाह, वकील और जज मिलकर पैसे ज़रूर खा गए. अब आप सोचिए कि नेताओं पर जो बिजली का पैसा बकाया है, उसे कौन वसूले! आम नागरिक का बकाया हो, तो लाइन फौरन बंद और क़ानूनी कार्रवाई शुरू, लेकिन नेताओं के बकाए की वसूली के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं रहती. सूचना अधिकार क़ानून के तहत ही संजय शर्मा द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में 2013 में सरकार ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के विधायकों पर डेढ़ करोड़ रुपये का बकाया है. बिजली विभाग और प्रशासन मंत्रियों-विधायकों के सरकारी आवासों के बकाया बिजली बिल की वसूली का कोई इंतजाम नहीं करता और हर बार यह बकाया बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. 2013 में विधायकों के सरकारी आवासों पर क़रीब डेढ़ करोड़ रुपये का बकाया था, लेकिन उसकी वसूली नहीं हुई. यहां कोई कनेक्शन काट नहीं सकता.

बिजली विभाग को तो यह भी पता नहीं कि किस आवास में कौन विधायक रहता है या किस विधायक ने आवास खाली करने से पहले बिजली का बकाया चुकाया था कि नहीं. लखनऊ के विधायक निवास-5 के आवासों, बटलर पैलेस के विधायक आवासों और माल एवेन्यू के विधायक आवासों में रहने वाले विधायकों पर एक करोड़ 49 लाख 38 हज़ार 588 रुपये का बिजली बिल बकाया था, जिसकी वसूली नहीं हुई. सरकारी स्वीकारोक्ति के मुताबिक, विधायक निवास-5 के सभी आवासों पर 79 लाख 68 हज़ार 711 रुपये, बटलर पैलेस कॉलोनी के आवास संख्याङ्क-1/बीपीसी पर छह लाख 94 हज़ार 362 रुपये, आवास संख्याङ्क-2/बीपीसी पर दो लाख 49 हज़ार 41 रुपये, आवास संख्याङ्क-21/बीपीसी पर 54 हज़ार 960 रुपये, आवास संख्या-11/बीपीसी पर 56 हज़ार 447 रुपये, आवास संख्याङ्क-4/बीपीसी पर तीन लाख 29 हज़ार 410 रुपये, माल एवेन्यू विधायक आवास संख्या ई-302 पर आठ लाख 54 हज़ार 96 रुपये, संख्या ई-102 पर नौ लाख 82 हज़ार 442 रुपये, आवास संख्या जी-2 पर एक लाख 42 हज़ार 798 रुपये, आवास संख्या-203 पर तीन लाख 56 हज़ार 843 रुपये, आवास संख्याङ्क-101 पर 12 लाख 66 हज़ार 788 रुपये, आवास संख्याङ्क-202 पर 2,334 रुपये, आवास संख्याङ्क-203 पर 15 लाख 80 हज़ार 832 रुपये, आवास संख्याङ्क-303 पर एक लाख छह हज़ार 100 रुपये, बीजी-3 पर एक लाख 97 हज़ार 15 रुपये और आवास संख्याङ्क-103 पर नौ लाख छह हज़ार 409 रुपये का बिजली बिल बकाया था.

माल एवेन्यू का बीजी-1 अकेला ऐसा आवास है, जिस पर बिजली की कोई भी धनराशि बाकी नहीं है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ के अमीनाबाद डिवीजन में 7,458 लाख, चौक डिवीजन में 8,783 लाख, अपट्रॉन डिवीजन में 2,228 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है. इसी तरह ऐशबाग डिवीजन में 3,703 लाख, सेस प्रथम में 7,935 लाख, सेस द्वितीय में 6,446 लाख, सेस तृतीय में 1,916 लाख रुपये बकाया हैं. हुसैनगंज डिवीजन में 7,360 लाख, राजभवन डिवीजन में 420 लाख, चिनहट डिवीजन में 1,637 लाख, गोमती नगर में 519 लाख, राजाजीपुरम डिवीजन में 305 लाख, महानगर डिवीजन में 997 लाख, लखनऊ विश्वविद्यालय उपकेंद्र डिवीजन में 647 लाख, कानपुर रोड डिवीजन में 590 लाख, वृंदावन डिवीजन में 465 लाख, रेजीडेंसी डिवीजन में 8,411 लाख, ठाकुरगंज डिवीजन में 5,259 लाख, इंदिरानगर डिवीजन में 61 लाख, मुंशी पुलिया डिवीजन में 555 लाख, बख्शी का तालाब में 981 लाख, डालीगंज डिवीजन में 316 लाख, रहीम नगर डिवीजन में 725 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है.■

feedback@chauthiduniya.com

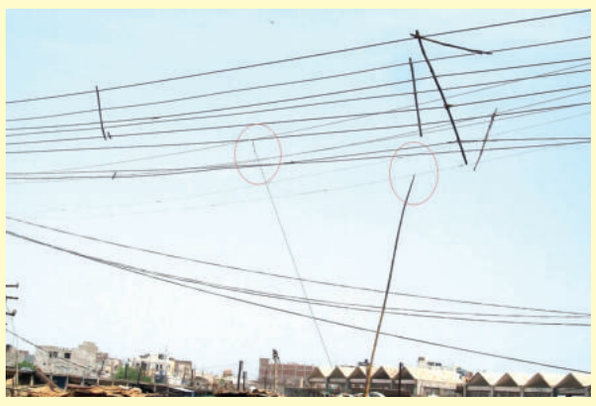

चोरी की बिजली से सत्ता के घर रौशन

सत्ता के अलमबरदारों के राजनीतिक और पैतृक गढ़ों में बिजली चोरी सबसे अधिक है. इस बिजली चोरी को सरकार लाइन लॉस की संज्ञा देती है. इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़ जैसे ज़िलों में सबसे ज़्यादा लाइन लॉस है. प्रदेश के 16 ज़िलों में 50 प्रतिशत और 14 ज़िलों में 40 प्रतिशत से ज़्यादा लाइन लॉस है. रामपुर, संभल, शामली और जेपी नगर में 50 प्रतिशत से ज़्यादा लाइन लॉस दर्ज किया जा रहा है. मैनपुरी बिजली चोरी में अव्वल है. कन्नौज दूसरे, इटावा तीसरे और फिरोजाबाद चौथे स्थान पर है. सत्ता और सपा प्रमुख के गृह क्षेत्र इटावा का वितरण खंड-दो पूरे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी 58 प्रतिशत तक बिजली चोरी कर रहा है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दक्षिणांचल क्षेत्र में आगरा के बाद सबसे ज़्यादा बिजली इटावा को दी गई, लेकिन वहां बिजली बिल सबसे कम वसूला जा सका. विभागीय अधिकारी बिजली चोरी को लाइन लॉस बताकर मामला दबा देते हैं. कथित लाइन लॉस के मामले में लखनऊ चौक, अमीनाबाद, ठाकुरगंज और अपट्रॉन डिवीजन अव्वल हैं. हुसैनगंज डिवीजन में 68, राजभवन डिवीजन में 43 और अमीनाबाद डिवीजन में 20 प्रतिशत बिजली लाइन लॉस में बर्बाद हो जाती है.

चिनहट में 49 प्रतिशत बिजली लाइन लॉस में दिखाई जाती है. सरकार खुद बताती है कि राज्य में हर महीने 400 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली चोरी होती है. यानी बिजली चोरी के चलते विद्युत निगम को 400 करोड़ रुपये का नुक़सान हर महीने हो रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में 71.32, कबीना मंत्री आजम खां के गृह ज़िले रामपुर में 52.44, बुंदेलखंड के जालौन में 60.34 प्रतिशत बिजली चोरी हो रही है. गौतम बुद्ध नगर अकेला ऐसा ज़िला है, जहां बिजली चोरी सबसे कम 7.85 प्रतिशत है. प्रदेश सरकार बिजली चोरों पर शिकंजा कसने और बिजली का बकाया वसूलने में नाकाम है.